

माक्स से माओ
दुनियाँ के शोषित-दमित अवाम के
सबसे खतरनाक दुश्मन थे !
(शोध-ग्रंथ)

लेखक

डॉ. बी. के. वासनिक (Ph.D)

Website : <https://www.bahujanmarch.org>

प्रकाशक

बहुजन मार्च, 14, ठवरे कॉलनी, नागपुर - 440014

मुद्रक

रवि ऑफसेट वर्क्स, करबला के सामने, 39, ग्रेट नाग रोड
नागपुर - 440003 Mobile : 7507637311

प्रथम आवृत्ति : दिसंबर 2018

मुद्रित प्रतियाँ : मात्र 1000 (एक हजार सिर्फ)

सहयोग राशी : 80/-

ANTI-COPYRIGHT

(सर्वाधिकार-मुक्त किताब)

शोषित-दमित जनता को शिक्षित तथा जागरुक करने
के मकसद से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस शोध-ग्रंथ को छापकर
नाममात्र की किमत पर बेचने के लिये स्वतंत्र है।

प्रस्तुति  शोषित समाज जागरुकता मुहिम !

प्रस्तावना

इस किताब को मुख्यतः निम्नलिखित किताबों से विकसित किया गया है:- 1. Under the sign of Scorpion by Juri lina, 2. The Architects of Deception by Juri lina, 3. Mullins' New History of the Jews by Eustace Mullins 4. All Wars Are Bankers' Wars! by Michael Rivero, 5. Michael Bakunin Selected Writings, , Edited and Introduced by Arthur Lehning.

उपरोक्त किताबों के अलावा महत्वपूर्ण जानकारी को इंटरनेट पर उपलब्ध कई अन्य किताबों, दस्तावेजों तथा वेब पेजेस से लिया गया है। कम्युनिस्टों द्वारा चीन पर कब्जा करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित वेब पेजेस से ली गई है :-

1) <http://www.theeuropeangreens.eu/> Are China, Russia and the rest of the world dismantling the Jewish allergy within their nations, or is this another game of Divide and Conquer - THE EUROPEAN GREENS (Eng).htm

2) <https://www.thenewamerican.com/> China Betrayed Into Communism.htm China Betrayed Into Communism Written by James Perloff

विस्तृत जानकारी के लिये उपरोक्त किताबों तथा वेब पेजेस को पढ़ें। सभी किताबें इंटरनेट पर पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में मौजूद हैं।

मौजूदा कॉपीराइट-मुक्त ई-किताब का मकसद प्राप्त जानकारी के तार्किक संश्लेषण (synthesis) से उभरने वाली वैश्वीक शोषण-व्यवस्था की संपूर्ण तस्वीर संक्षेप में पेश करना है। यह किताब कॉपीराइट मुक्त है इसलिये हर किसी को यह अधिकार दिया जाता है कि आप इसका मुक्त रूप से वितरण कर सकते हैं तथा बिना परिवर्तन किये इस किताब को छापकर बेच सकते हैं।

Dr. B. K. Wasnik (Ph.D.)

Address :- 14, Thaware Colony (old),
Nagpur - 440014 (India)

Website : <https://www.bahujanmarch.org>

अनुक्रमणिका

1. यहूदी दुनियाँ के नियंत्रक कैसे बने ? 05

सूदखोरी शोषण-व्यवस्थाओं का भौतिक मूलाधार (5), यहूदियों का लक्ष्य सर्वोच्च सत्ता हासिल करना है (5), यहूदी अपने संगठन की वजह से शक्तिशाली बने (5), यहूदियों की खुद को बचाने की तरकीबें तरकीबें (6), यहूदियों को डाकू तथा परजीवी माना जाता था (7), गैरयहूदी शासकनों ने यहूदियों का संरक्षण किया (7), यहूदियों का विभिन्न देशों से निष्काषण (8), निष्काषित यहूदी दोबारा कैसे वापस आये ? (9), यहूदियों ने आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया (10)]

2. यहूदी बैंकर्स कैसे दुनियाँ के अदृश्य शासक बने 11

कागज की मुद्रा का (fiat Currency) आरंभ (11), आंशिक (Fractional) रिजर्व बैंकींग पध दति (12), बैंक ऑफ इंग्लंड का गठन (12), केन्द्रिय बैंक जनता को गरीब बनाते है (13), रोथ्सचिल्ड परिवार (14), अमेरिका में निजी बैंकों का गठन (14), अमेरिका का गृहयुद्ध (15), यहूदियों को आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नही (17), अमेरिका का फेडरल रिजर्व (17), विश्वयुद्धों का कारण निजी केन्द्रिय बैंक (18), पहले विश्वयुद्ध के माध्यम से यहूदी बैंकर्स ने जर्मनी को गुलाम बनाया (18), हिटलर का उदय (19)

3. मार्क्स तथा एंगेल्स बेनकाब 19

मार्क्स तथा एंगेल्स संपन्न परिवारों से थे (19), कार्ल मार्क्स के शिक्षक (20), मार्क्स शराबी, तानाशाह तथा विश्वासघाति था (21), मार्क्स गैरयहूदी जातियों से नफरत करता था (23), मार्क्स षडयंत्रकारी और झूठा था (23), मार्क्स-एंगेल्स ने दूसरों के साहित्य को अपना दर्शाया (24), मार्क्स-एंगेल्स को बहुत कम लोग जानते थे (25), मार्क्स-एंगेल्स का विरोधाभासी व्यवहार (26), मार्क्स शैतान-उपासक था (26),

4. मार्क्सवाद धोखा-छलावा है 27

संक्षेप में मार्क्स का सिद्धान्त (27), आदीम साम्यवाद (28), राज्य (29), राज्य का उगम (29), राज्य के कार्य (30), उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य (30), क्या मार्क्सवादी राज्य इससे भिन्न है ? (31), मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद (32), ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धान्त प्रतिक्रांतिकारी है (33), परिवार (34), वर्ग तथा वर्ग-चरित्र (35), अतिरिक्त मुल्य का सिद्धान्त (36), अंतर्राष्ट्रीयतावाद (37), सर्वहारा वर्ग और क्रांति (37)

5. मार्क्स-एंगेल्स यहूदी बैंकर्स के एजेंट थे ! 38

मार्क्स ने जासूस के रूप में कार्य किया (38), मार्क्स बैंकर्स का एजेंट था (39), रोथ्सचिल्ड तथा मार्क्स दोनों ही रुस से नफरत करते थे (39), मार्क्स का काम मजदूर आन्दोलन को तहस नहस करना था (40), मार्क्स ने मजदूर आन्दोलनों का भीतराघात किया (40), एक मई मजदूरों का "शहीदी दिवस" नही है (42), यहूदी बैंकर्स ने मार्क्सवाद को प्रचारित-प्रसारित किया (42)

6. रुस में कम्युनिस्ट क्रांति 43

रुस में यहूदी संपन्न समुदाय था (43), सन 1905 की कथित क्रांति (44), सन 1917 की कथित क्रांति (45), बैंकर्स तथा बोल्शेविकों ने रुस से बेपनाह दौलत हासिल की (47), रुस में यहूदी कम्युनिस्ट नौकरशाही ऐशो-आराम में रहती थी (48), चुनावों में रुस की जनता ने

बोल्शेविकों को नकार दिया (50), बैंकरों ने रुस में कम्युनिस्ट सत्ता को बचाया (51), पश्चीमी देशों की कथित नाकाबंदी तथा सैनिक हस्तक्षेप (51), पश्चीमी देशों की मित्र सेना ने अघोषित रूप से बोल्शेविकों को मदद पहुंचाई (51), युक्रेन की जनता को भूखा मारने की कम्युनिस्ट कार्रवाई (53), कम्युनिस्ट रुस आतंकवादी शासन था (54), कम्युनिस्ट रुस में गुलाम-मजदूरी की व्यवस्था (55), कम्युनिस्ट रुस में विदेशी भी गुलाम मजदूर बनाये गए (55), कम्युनिस्ट रुस में सामुहिक जनसंहार (56), कम्युनिस्ट रुस की नई आर्थिक नीति (NEP) (57), विदेशी प्रतिनिधियों के सामने झूठे दिखावे (57), मानवाधिकारों का मतलब सिर्फ यहूदी अधिकार थे (58)

7. वैश्विक सरकार को आकार 59

BIS, WB तथा IMF इ.का निर्माण (59), वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर (60), संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण (60), अमेरिका का यहूदी कॉलनी में रूपांतरण ? (61)

8. चीन में कम्युनिस्ट क्रांति 62

चीन में यहूदियों की तादाद (62), चीन में यहूदियों का विस्तृत सामाजिक संजाल (Network) (63), चीन में यहूदियों का अफीम व्यापार का संजाल (Network) (64), चीन में यहूदियों का व्यवसायिक साम्राज्य (65), चीन में अपराधिक माफीया (66), चीन में विदेशी बैंकों का संक्षिप्त इतिहास (66), चीन की राष्ट्रवादी पार्टी कोमिन्तांग (Kuomintang) (67), चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन (67), कोमिन्तांग में कम्युनिस्ट घुसपैठ (68), माओ झेडांग (Mao Tse Tung) - (69), अमेरिकी सरकार में कम्युनिस्ट समर्थक लॉबी (70), चीन के राष्ट्रवादियों के खिलाफ स्तालिन की नीति (70), कम्युनिस्ट सत्ता के लिये अमेरिका की कोशिशें (72), चीनी कम्युनिस्ट सरकार के नियंत्रक (Handlers) (74), चीनी जनता का क्रूर दमन (74), कथित लंबी छलांग (The Great Leap Forward) (75), लंबी छलांग का परिणाम (76), सौ तरह के फूल खिलने दो अभियान (77), कथित सांस्कृतिक क्रांति (77)

9. नई यहूदी वैश्विक व्यवस्था 79

अमेरिकी अध्यक्ष केनेडी की हत्या (79), वैश्विकरण का असली मतलब (79), डॉलर का संकट (80), पेट्रोडॉलर (80), युरोपियन युनियन (81), सांस्कृतिक-संघर्ष (Clash of Civilization) : तीसरे विश्वयुद्ध का कार्यक्रम (81), BRICS इ. का गठन (82), चीन नई यहूदी वैश्विक व्यवस्था का एजेन्ट है (82)

10. भारत तथा दिगर देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ 83

11. क्या छुटकारे का कोई रास्ता है ? 87

शोषण-व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक मूलाधार (87), शोषण-व्यवस्थाओं का भौतिक मूलाधार (88), राज्य-व्यवस्था का पर्याय (88), सामाजिक-न्याय के संगठनों का स्वरूप (90)

संदर्भ सूची 92- 95

अध्याय 1

यहूदी दुनियाँ के नियंत्रक कैसे बने ?

सूदखोरी शोषण-व्यवस्थाओं का भौतिक मूलाधार !

नीचे दी हुई कहानी से स्पष्ट होता है कि सूदखोरी से शोषण व्यवस्था का जन्म होता है :- एक अज्ञात छोटे से द्वीप के रहिवासी चीजों को आपस में बदल कर अपनी जरूरतें पूरी करते थे। खेतिहर इ. उत्पाद खास मौसम में ही उपलब्ध थे जिससे वस्तुओं को बदलने में दिक्कत थी। संयोगवश नाव से एक आदमी उनके द्वीप पहुंचा। उसने कहा कि उसके पास प्लास्टिक के विभिन्न मूल्य के सिक्के हैं जो उसके बक्से में बंद सोने का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग इन सिक्कों को कर्ज में लेकर सिक्कों की मदद से चीजों को खरीद सकते हैं। लोगों ने सिक्के कर्ज में लिये। सूद सहित कर्ज की किश्तें देने के बाद उनके सिक्कों की तादाद कम होने लगी। उपाय यही था की या तो वे साहुकार से और कर्ज ले या फिर अनैतिक व्यापार नियमों का पालन कर औरों से सिक्के हड़पें। क्योंकि व्याज सहित कर्ज की रकम दिये गये कर्ज से हमेशा ही ज्यादा होती है इसलिये अगर सारे निवासी अपने सारे सिक्के सूदखोर को लौटा दे तो भी सूदखोर का कर्ज खत्म नहीं हो सकता। इसलिये लोगों की हालत बदतर होने लगी। सूदखोर ने द्वीप के कुछ हष्टपुष्ट सशस्त्र लोगों को नौकर रखा। वे जबरन वसूली इ. करते थे। द्वीप के अधिकांश लोग कर्ज से बर्बाद होकर सूदखोर के बंधुआ मजदूर बन गये। सूदखोर के बक्से में सोना नहीं बल्कि कपड़े इ. चीजे थी। उसने चंद प्लास्टिक के टूकड़ों के बदले में लोगों की जाजदाद गिरवी रखवाकर अंततः हड़प ली थी।

यहूदियों का लक्ष्य सर्वोच्च सत्ता हासिल करना है !

यहूदियों के धर्मग्रंथ तलमूद के मुताबिक ईश्वर ने उन्हें गैर-यहूदियों पर राज करने के लिये चूना है। गैर-यहूदी इन्सान नहीं है। ईश्वर ने गैर-यहूदियों को इन्सानों के रूप में इसलिये अवतरित किया है ताकि वे यहूदियों की गुलामी कर सके। इसलिये गैर-यहूदियों के कोई इन्सानी हक नहीं है। तलमूद यहूदियों को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी अनैतिक तरीके से गैर-यहूदियों की संपत्ति और जायजाद को हड़पें। इसलिये सूदखोरी यहूदियों का परंपरागत व्यवसाय है।

यहूदी आपने संगठन की वजह से शक्तिशाली बने !

यहूदी समुदायों की प्रतिनिधि-सभा Sanhedrin आदिमकाल से चली आ रही है। येशु ख्रिस्त्र के समय "काहाल" संस्था यहूदियों के जीवन की नियंत्रक बन गई। काहाल यहूदियों के संरक्षण का काम करती है। काहाल किसी भी गैर-यहूदी का शोषण करने, मसलन किसी गैरयहूदी का घर खरीदने का अधिकार ज्यादा बोली लगाने वाले यहूदी को बेचती है। तब उस यहूदी के रास्ते से बाकी यहूदी हट जाते हैं। तब वह यहूदी उस गैर-यहूदी का घर खरीदने या हड़पने में जूट जाता है। काहाल के मुताबिक किसी भी

तालाब (यानि गांव) में उतने ही मछरे (यानि सूदखोर यहूदी) होने चाहिये जितनों को तालाब पाल सकता है। (Russian Jews and Gentiles FROM A RUSSIAN POINT OF VIEW By Mme Z Ragozin). सन 1869 में पश्चिमी राज्यों की 73% स्थिर जायदाद यहूदियों के हाथों में आ गई। सन 1806 में रशीया, पोलंड, गॅलिसिया, रोमानिया के पश्चिमी प्रांत तथा फ्रांस के सारे विभाग यहूदियों के पास गिरवी पड़े थे।

काहाल यहूदी समाज को नीचे दिये हुए साधनों से नियंत्रित करती है :-

1. खेरेम (Kherem) :- खेरेम विद्रोही यहूदी का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार है। ऐसे यहूदी को धार्मिक अनुष्ठान में कोसने के बाद काहाल उसपर खेरेम घोषित करती है। काहाल को कर अदा किये बिना किसी भी प्राणी या पक्षी को मांस के लिये नहीं काटा जा सकता वरना ऐसे मांस को निषिद्ध करार देकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खेरेम घोषित किया जा सकता है।

2. बेथ-डीन (Beth-din) तलमूद के नियमों से चलने वाला काहाल का न्यायालय है। यहूदियों का धार्मिक कानून गैर-यहूदियों के न्यायालयों को मान्यता नहीं देता इसलिये बेथ-डीन बना है। बेथ-डीन यह दर्शाता है कि यह यहूदियों के बीच मेलमिलाप कराने वाली संस्था है इसलिये गैर-यहूदी सरकारों ने उसे बर्दाश्त किया है हालांकि बेथ-डीन को कानूनी मान्यता नहीं होती।

बेथ-डीन हर पक्ष के व्यक्ति से कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराता है। हारा हुआ यहूदी अगर सरकारी न्यायालय में मुकदमा दायर करता है तो बेथ-डीन उसके हस्ताक्षर किये हुए कोरे कागज पर चाहे जो लिख कर सरकारी फैसला उसके खिलाफ कर सकती है।

यहूदियों के धार्मिक शासकों को "ज़ायन के वरीष्ठ" (Elders of Zion) कहा जाता है जो यहूदी समुदाय पर सख्ती से शासन करते हैं। यहूदियों का धार्मिक कानून गैर-यहूदियों का शोषण करने वाले यहूदियों को बचाने तथा यहूदियों द्वारा गैर-यहूदियों को सतत रूप से अपराधिक शोषण होता रहे इससे संबंधित है। इसलिये हर यहूदी को वही करना होता है जिसे काहाल ने करने को कहा है। धोखेबाजी का संदेह मात्र होने से उस यहूदी की जान ली जा सकती है। ऐसे कठोर नियमों से ही परजीवी समुदाय खुद का संरक्षण कर सकता है। यहूदी बैंकर्स तथा काहाल आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध तथा अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर बेहद एकीकृत है और पूरे तालमेल और सामंजस्य से यहूदी सत्ता के लिये वे कार्यरत रहते हैं।

यहूदियों की खुद को बचाने के तरकीबें (Survival Techniques)

सन 1492 में स्पेन के प्रमुख धर्मगुरु (Rabbi) चेमोर को Constantinople स्थित Grand Sanhedrin ने यहूदियों के संभावित निष्काषण को लेकर निम्नलिखित सलाह दी :-

1. अगर आपको स्पेन का राजा ईसाई बनने के लिये मजबूर करें तो आप ईसाई बन जाओ क्योंकि तुम इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते।

2. जहां तक जायदाद से तुम्हे बेदखल करने का सवाल है, अपने बेटों को तुम व्यापारी बनाओ ताकि तुम धीरे धीरे ईसाईयों को उनकी जायदाद से बेदखल कर सको।

3. वे तुम्हारे जान के लिये खतरा है, इसलिये तुम अपने बेटों को डॉक्टर तथा फार्मासिस्ट बनाओ ताकि वे ईसाईयों की जान ले सकें।

4. वे तुम्हारे धर्मस्थल (synagogues) नष्ट करते हैं तो तुम अपने बेटों को पादरी, धर्म गुरु बनाओ ताकि तुम उनके चर्चों को अपनी शिक्षा से नष्ट कर सको।

5. अपने बेटों को वकील और न्यायविद बनाओ और यह सुनिश्चित करो कि वे राज्य के मामलों में दखलंदाजी करते हुये ईसाईयों पर अपना वर्चस्व कायम कर उनसे बदला ले सकें।

6. इन आदेशों का पूरी तरह से पालन करो। तब तुम अपने अनुभवों से जान जाओगे कि तुम सत्ता के शिखर तक पहुंच रहे हो। (हस्ताक्षर) कॉन्टान्टीपोल के यहूदियों के राजकुमार (L. Fry, Waters Flowing Eastward: The War Against the Kingship of Christ. TBR Books, Washington, D. C., (2000), pp. 51-52) भले ही किसी यहूदी ने दबाव में या कूटनीति के तहत अपना धर्म बदला हो, वह काहाल के कठोर अनुशासन में गुप्त रूप से यहूदी ही रहा है।

यहूदियों को डाकू तथा परजीवी समझा जाता था !

इउस्टास मुलिन्स (Eustace Mullins) के मुताबिक यहूदियों के इतिहास के आरंभिक समय में यहूदी डाकू थे। वे टोह में इधर से उधर भटकते रहते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी कहते हैं कि ईश्वर ने उनकी दूष्टता की वजह से उन्हें बेघर भटकने के लिये मजबूर किया। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ने यहूदियों को गैर-यहूदियों पर राज करने के लिये नहीं चूना है।

तत्कालीन सभ्यताओं ने यहूदी डाकूओं के खिलाफ सैनिक कार्रवाईयों की तथा कईयों को बंदी बनाकर अपने शहर ले आये। बंदी बने यहूदियों ने अपनी औरतों तथा रिश्वत के जरिये हुक्मरान तबके से संबध बनाये। वे हुक्मरानों के लिये अवाम से टैक्स वसूलने, जासूसी, हत्याएं इ. काम करने लगे। यहूदियों की अपराधिक कार्रवाईयों आंतरराज्यीय थी। वे क्रूर तथा चालबाज साहूकार भी थे। उन्होंने शासन-प्रशासन में उच्च पद हासिल किये। वे गैर-यहूदियों से नफरत करते थे इसलिये उन्होंने गैर-यहूदियों पर जुल्म ढाये, उन्हें गरीब लाचार बना दिया।

गैर-यहूदी शासकों ने यहूदियों का संरक्षण किया !

इउस्टास मुलिन्स (Eustace Mullins) के मुताबिक गैर-यहूदी शासक यहूदियों का उपयोग कर्जा हासिल करने में, विदेशी राज्यों में जासूसी करने में, दूसरे देशों के बीच बातचीत तथा समझौते करने में, तथा मुख्यतः राज्य की जनता से जबरन टैक्स वसूलने के लिये करते थे। राजा-रजवाडों तथा यहूदियों का मकसद जनता का

दमन-शोषण करना था।

यहूदियों का विभिन्न देशों से निष्काषण !

यहूदियों को ईसा मसीह की मौत का जिम्मेदार माना गया। यहूदी कुआंरी मेरी को वेश्या कह कर उसका उपहास करते थे तथा ईसाईयों का सलीब देखते ही नफरत से थूकते थे।

यहूदी दो हजार सालों से गैरयहूदियों के रीतिरीवाजों, भाषा तथा धर्मों का मखौल उडाते हुए विद्रोहियों की तरह गैर-यहूदी राज्यों में उनसे अलग पहचान बनाकर रहे। (The Secret Powers Behind Revolution FREEMASONRY AND JUDAISM, By Vicompte Leon De Poncix) वे गैर-यहूदियों को जानवरों से भी नीचले दर्जे का मानते हैं। इसलिये यहूदी किसी गैर-यहूदी को धर्मांतरण से यहूदी नहीं बनाते। इसलिये वे आंतरधर्मीय विवाहों का विरोध करते हैं। यहूदी हर जगह जनता में परजीवी बने रहे। यहूदी अपनी इन्सानी बली देने, खून पीने इ. प्रथाओं को गैर-यहूदियों से छूपाने के तथा सामुहिक सुरक्षा के मकसद से अपनी वसाहतों में अलग-थलग रहना पसंद करते हैं। इन वसाहतों को "घेटो" ghettos कहा जाता है।

यहूदियों द्वारा गैरयहूदियों का क्रूरता से दमन शोषण किया जाना, गैर-यहूदी बच्चों का अपने कर्मकांड के लिये कत्ल करना इ. की वजह से जब जनता विद्रोह पर उतार हो जाती थी तभी मजबूर होकर राजा को अपने राज्य से यहूदियों को निष्काषित करने पर मजबूर होना पड़ता था। सन ईसापूर्व 250 के बाद से अबतक 109 प्रांतों से यहूदी निष्काषित किये जा चुके हैं :- सन 250 Carthage, सन 415 Alexandria, सन 554 Diocèse of Clermont (France), सन 561 Diocèse of Uzès (France), सन 612 Visigoth Spain, सन 642 Visigoth Empire, सन 855 Italy, सन 876 Sens, सन 1012 Mainz, सन 1182 France, सन 1182 Germany, सन 1276 Upper Bavaria, सन 1290 England, सन 1306 France, सन 1322 France (again), सन 1348 Switzerland, सन 1349 Hielbronn (Germany), सन 1349 Saxony, सन 1349 Hungary, सन 1360 Hungary, सन 1370 Belgium, सन 1380 Slovakia, सन 1388 Strasbourg, सन 1394 Germany, सन 1394 France, सन 1420 Lyons, सन 1421 Austria, सन 1424 Fribourg, सन 1424 Zurich, सन 1424 Cologne, सन 1432 Savoy, सन 1438 Mainz, सन 1439 Augsburg, सन 1442 Netherlands, सन 1444 Netherlands, सन 1446 Bavaria, सन 1453 France, सन 1453 Breslau, सन 1454 Wurzburg, सन 1462 Mainz, सन 1483 Mainz, सन 1484 Warsaw, सन 1485 Vincenza (Italy), सन 1492 Spain, सन 1492 Italy, सन 1495 Lithuania, सन 1496 Naples, सन 1496 Portugal, सन 1498 Nuremberg, सन 1498 Navarre, सन 1510 Brandenburg, सन 1510 Prussia, सन 1514 Strasbourg, सन 1515 Genoa, सन 1519 Regensburg, सन 1533 Naples, सन 1541 Naples, सन 1542 Prague & Bohemia, सन 1550 Genoa, सन 1551 Bavaria, सन 1555 Pesaro, सन 1557 Prague, सन 1559 Austria, सन 1561 Prague, सन 1567 Wurzburg, सन 1569 Papal States, सन 1571 Brandenburg, सन 1582 Netherlands, सन 1582 Hungary, सन 1593

Brandenburg, Austria, सन 1597 Cremona, Pavia & Lodi, सन 1614 Frankfort, सन 1615 Worms, सन 1619 Kiev, सन 1648 Ukraine, सन 1648 Poland, सन 1649 Hamburg, सन 1654 Little Russia (Beylorus), सन 1656 Lithuania, सन 1669 Oran (North Africa), सन 1669 Vienna, सन 1670 Vienna, सन 1712 Sandomir, सन 1727 Russia, सन 1738 Wurtemberg, सन 1740 Little Russia (Beylorus), सन 1744 Prague, Bohemia, सन 1744 Slovakia, सन 1744 Livonia, सन 1745 Moravia, सन 1753 Kovad (Lithuania), सन 1761 Bordeaux, सन 1772 Deported to the Pale of Settlement (Poland/Russia), सन 1775 Warsaw, सन 1789 Alsace, सन 1804 Villages in Russia, सन 1808 Villages & Countrysides (Russia), सन 1815 Lbeck & Bremen, सन 1815 Franconia, Swabia & Bavaria, सन 1820 Bremen, सन 1843 Russian Border Austria & Prussia, सन 1862 Areas in the U.S. under General Grant's Jurisdiction[1], सन 1866 Galatz, Romania, सन 1880s Russia, सन 1891 Moscow, सन 1919 Bavaria (foreign born Jews), सन 1938-45 Nazi Controlled Areas, सन 1948 Arab Countries. (<http://www.biblebelievers.org.au/>)

बर्नार्ड लाज़ारे (Bernard Lazare) के मुताबिक क्योंकि जिन प्रांतों ने यहूदियों को निष्काषित किया वे वांशिक रूप से एक-दूसरे से अलग थे, उनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, उनके कानून भी अलग थे, वे अलग सिधान्तों के तहत शासित थे, उनके नैतिक मूल्य अलग थे, उनके रिवाज तथा परंपराएं अलग थी तथा उनकी प्रवृत्तियां तक अलग थी। इसलिये यह निष्कर्ष निकलता है कि यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा होने के पीछे खुद यहूदियों का अपना बर्ताव था। यहूदी पीड़ित नहीं बल्कि उत्पीड़क थे। इसलिये यहूदि-विरोध (Antisemitism) की वजह खुद यहूदी थे न कि वे जिन्होंने इनके जुल्म का प्रतिरोध किया।

निष्काषित यहूदी दोबारा कैसे वापस आये ?

यहूदी जानते थे कि उन्हें किसी दिन निष्काषित किया जायेगा। इसलिये उन्होंने उस राज्य में गैर-यहूदियों के बीच उपहार, रिश्वत इ. के तथा बाद में ब्लेकमेल से अपने सहयोगी बनाये। निष्काषण के बाद वे हुक्मरानों के एजन्टों से संपर्क कर हुक्मरानों के लिये बेहद आकर्षक प्रस्ताव पेश करते थे। यहूदियों को निष्काषित करने में हिस्सा लेने वाले जन नेताओं को षडयंत्रों से पारिवारिक तथा आर्थिक नुकसान पहुंचाते थे। उन्हें जनता के बीच बदनाम किया जाता था। तब यहूदियों से मदद हासिल नये नेता उभरते थे। जो भी इन नेताओं का विरोध करता षडयंत्रों से उन्हें भी दुष्ट साबित किया जाता था। ये नेता यहूदियों को वापस आने में मदद करते थे।

सन 1290 के अक्टूबर में सोलह हजार निष्काषित यहूदी इंग्लैंड से जहाज पर बैठ कर फ्रांस, फ्लॉडर्स, जर्मनी तथा स्पेन के लिये रवाना हुए। इंग्लैंड ने यहूदियों को लगभग तीन सौ सालों तक बाहर रखा। इस दौरान इंग्लैंड दुनिया का महान देश बनने में कामयाब हुआ।

यहूदियों ने ओलिवर क्रामवेल को इंग्लैंड में बगावत के लिये आर्थिक मदद दी। उसने सैनिक जुटाये और सत्ता पर कब्जा किया। क्रामवेल तथा यहूदियों का शासन इतना क्रूर था कि लोगों ने बगावत कर राजा चार्ल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाया। लोगों की मांग थी कि इंग्लैंड से यहूदियों को निष्काषित किया जाये। चार्ल्स द्वितीय पक्का ऐय्याश था। अपनी ऐय्याशियों के लिये उसे यहूदियों से धन की जरूरत थी इसलिये उसने लोगों की मांग को नामंजूर कर दिया। तब से यहूदी आज तक इंग्लैंड में है। उन्होने सत्ता पर अपनी मजबूत पकड बना ली है।

यहूदियों ने आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया !

1. इजिप्त : अपनी तिकडमों से यहूदियों ने इजिप्त में उंचे ओहदे हासिल किये। तभी से इजिप्त की सीमा से बाहर डाकूओं के दल ज्यादा हिंसक और मुखर होते गए; उन्हे पता होता था कि कब कहां और कैसे हमला किया जाये, किस जगह बेहद कमजोर सुरक्षा व्यवस्था है। इजिप्त में भ्रष्टाचार और अनैतिकता विकराल रूप धारण करने लगी। राजनेता हालत को नजरंदाज करते रहे जिससे जनता का मनोबल टूटा। इजिप्त में समस्याएं पैदा हुई। यहूदियों ने हिक्सोस (Hyksos) या शेफर्ड राजाओं को आक्रमण के लिये निमंत्रित किया और उनके लिये शहर के दरवाजे खोल दिये। बिना कोई लडाई लडे उन्होने इजिप्त की जनता पर 511 सालों तक क्रूरता से राज किया। इस शासन के दौरान यहूदी ऐश करते रहे और इजिप्त की जनता पर जुल्म ढाते रहे। अंततः इजिप्त की जनता ने विद्रोह किया और हिक्सोस को अपने राज्य से हमेशा के लिये भगा दिया। इजिप्त की जनता ने यहूदियों को उनकी गद्दारी और क्रूरताओं के लिये सजाएं दी तथा उन्हे गुलाम बनाकर कठोर परिश्रम करने पर मजबूर किया। यह मोजेस के काल में हुआ। उनकी गद्दारी के लिये यहूदियों को दी हुई सजा पूरी तरह से स्वाभाविक थी। यहूदियों ने षडयंत्रों से उनके पानी के स्रोतों में जहर मिलाया और प्लेग जैसी बीमारियों का संक्रमण कराया। अंततः तंग आकर इजिप्त के लोगों ने यहूदियों को इजिप्त छोडने की इजाजत दे दी।

2. बॅबिलॉन :- पर्शिया का मुखिया सायरस (Cyrus) बॅबिलॉन पर कब्जा करना चाहता था। यहूदियों ने बॅबिलॉन के मुख्य द्वार उनकी सेनाओं के लिये खोल दिये। इसतरह पर्शिया ने बिना किसी लडाई के बॅबिलॉन पर कब्जा कर लिया। सायरस के संरक्षण में यहूदियों को बॅबिलॉन की जनता को लूटने की पूरी आजादी दी गई। सायरस बॅबिलॉन की जिस संपत्ति को अपने साथ नही ले जा सका वह संपत्ति यहूदियों की संपत्ति बन गई। परिणाम स्वरूप बॅबिलॉन में यहूदी ताकतवर शासक बन बैठे और उन्होने तलमूद लिखी जिसे बॅबिलॉन तलमूद के नाम से जाना जाता है।

3. पर्शिया :- बहूत बडी तादाद में यहूदी सायरस के साथ पर्शिया गए और वहां बस गए। पर्शिया में यहूदियों की बढती तादाद और उनके द्वारा की जाने वाली जनता की लूट तथा षडयंत्रों से प्रधान मंत्री हमान विचलित हो उठा। राजा अहासुएरस (Ahasuerus) ने यहूदी मसले को सुलझाने के लिये हमान को अधिकृत किया। राजा की पसंदीदा बिबी का नाम इस्थर (Esther) था। वह असल में यहूदी थी। उसका

यहूदी नाम हाडासाह (Hadassah) था। राजा को अपने रूप से संमोहित कर यहूदी हितों की रक्षा के लिये उसे स्थापित किया गया था। वह राजा के पास गई और कहा कि वह यहूदी है इसलिये राजा उसका कत्ल कर दे। राजा उसके मोहपाश में बंधा था इसलिये उसने ईस्थर की मांग पर हमान को फांसी दी। हमान के दस पुत्रों को भी फांसी पर लटका दिया और उनकी चल-अचल संपत्ति ईस्थर के रिश्तेदारों में बांट दी। ईस्थर के आग्रह पर राजा ने यहूदियों को इकट्ठा होने, अपने दुश्मनों को मारने तथा उनकी संपत्ति पर कब्जा करने को मान्यता दी। इसके बाद पूरे राज्य में यहूदियों ने गैर-यहूदियों के जनसंहार किये।

4. रोमन साम्राज्य :- रोमन राज्य ने दुनियां पर कब्जा किया लेकिन वह अपने ही राज्य में बसे यहूदियों के आगे बेबस था। हर बार यहूदी वापस आते रहे। रोमन इतिहासकार मार्कस (Marcus) के मुताबिक रानी पोलटीना की वजह से सम्राट ट्राजान (Trajan) ने यहूदियों के प्रतिनिधियों का रोम में स्वागत किया। पर्शीया के प्रधानमंत्री हमान की तरह ही रोमन हरमाइसकस (Hermaiscus) को भी मौत की सजा दी गई क्योंकि उसने रोम के राजदरबार में यहूदियों की उच्च पदों पर उपस्थिति का विरोध किया था। रोम में कई परस्पर विरोधी समुदाय रहते थे। यहूदियों को अपने साथ मिलाने वाले की ताकत बढ जाती और वह औरों को भी आसानी से अपने साथ मिला सकता था। ज्युलियस सीजर को यहूदियों की ताकत का अंदाजा था। यहूदियों ने सीजर का समर्थन किया और सीजर ने यहूदियों को सैनिक बनाये जाने से मुक्त रखा, उन्हें जहाज में सोना येरुशलेम के मंदिर में ले जाने की इजाजत दी तथा विशेष यहूदी न्यायालयों को मंजूर किया। सीजर ने यहूदियों को सुविधा संपन्न ऐसा समुह बना दिया जो कानून के भी उपर था। यहूदियों की इस कदर हिमायत करने की वजह से ही रोम के प्रति इमानदार सिनेटर्स के एक समुह ने ब्रुटस की अगुआई में बगावत कर सीजर की हत्या कर दी।

अध्याय 2

यहूदी बैंकर्स दुनियां के अदृष्य शासक कैसे बने ?

कागज की मुद्रा (fiat Currency) का आरंभ !

सन 1024 में सुनार सामान्यतः यहूदी हुआ करते थे। जब भी कोई अपना सोना उनकी तिजोरियों में सुरक्षित रखवाता तो उसे सोने की रसीद देते थे। सोने को लाने ले जाने की अपेक्षा इन रसीदों को लाना ले जाना सुरक्षित था। दूसरे प्रांत में सुनारों के कार्यालय में कुछ कमीशन देकर रसीदों को सोने में तब्दिल किया जा सकता था। जल्द ही इन रसीदों का व्यापार होने लगा। बाद में रसीदों को धारक (bearer) बनाया गया। इस तरह रसीदें पहली कागजी मुद्रा बन गईं।

आंशिक (Fractional) रिजर्व बैंकिंग पध्दति !

सुनारों ने पाया कि अधिकांश रसीदों का व्यापार में लेनदेन होते रहता है इसलिये रसीदों का बहुत छोटा सा हिस्सा ही सोना लेने के लिये जमा होता है। इसलिये सुनारों ने व्यापारियों को ज्यादा रसीदें कर्ज में देनी शुरू की। उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और जितना सोना उनके पास है उससे दस गुणा ज्यादा मुल्य की रसीदों को उन्होंने ऋण पर देना शुरू किया। रसीदों के रूप में दिये गए कर्ज पर अगर वे 6% व्याज लेते थे तब भी वे मूल सहीत 60% व्याज मुफ्त में कमाते थे क्योंकि उन्होंने दस गुना ज्यादा सोने की रसीदे कर्ज के रूप में जारी की है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड का गठन !

सन 1694 में इंग्लैंड के राजा विलियम ऑफ आरेंज को भय था कि स्टुअर्ट्स (Stuarts) उनकी गद्दी न छीन ले। इसलिये भारी सेना रखना उसकी मजबूरी थी। अपने सैनिकों की तनखाह देने के लिये उसे कर्ज की जरूरत पडी। यहूदियों ने विलियम को इस शर्त पर कर्जा दिया कि यहूदी अपना निजी बैंक कायम कर कर्ज की रकम के बराबर की मुद्रा जारी कर सकेंगे। यह बैंक सरकारी लगे इसलिये बैंक का नाम "बैंक ऑफ इंग्लैंड" रखा गया। तय हुआ कि सरकार कर्ज की अदायगी टैक्स के पैसे से करेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड को सरकारी मुद्रा छापने के लिये मात्र कागज और स्याही का ही खर्चा होता था। यह नकली नोट छापने की तरह ही था। फर्क इतना था कि यह सब सरकार की इजाजत से हो रहा था। इंग्लैंड की सरकार पाउंड का बांड तो जारी कर सकती थी लेकिन वह पाउंड मुद्रा नहीं जारी कर सकती थी। इसलिये बहुत जल्द ब्रिटेन सरकार तथा गैर-यहूदी जनता कर्ज में डूब गई। सन 1934 में अपने 20th जुन के संस्करण में लंडन की न्यू ब्रिटेन नामक पत्रिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जार्ज (David Lloyd George) का यह कथन छापा कि इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रिय आर्थिक समुह (bloc) का गुलाम मात्र है। सन 1941 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के डायरेक्टर (1928-1941) ने कहा कि आधुनिक बैंक व्यवस्था शुन्य से ६ इन पैदा करती है ... तथा असल में बैंकर्स ही पृथ्वी के मालिक है। यहूदियों ने अपने एमस्टरडैम स्थित मुख्यालय को इंग्लैंड में स्थानांतरित किया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को मजबूर किया कि वे यूरोप देशों में यहूदी हितों का संवर्धन करें। यहूदी D'Israeli को इंग्लैंड का प्रधान मंत्री बनाया गया।

सन 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे राज्य के अधिकार में बैंक के सारे शेअर्स आ गये। शेअर्स की रकम अदा करने सरकार के पास ६ इन नहीं था इसलिये शेअर धारकों को सरकारी बांड दिये गए। सरकार को बैंक से होने वाली आमदानी मिलने लगी लेकिन बांड पर व्याज देना पडा। मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण निजी हाथों में ही था क्योंकि अपने सारे बांड बेचकर वे मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते थे।

यह दावा किया गया है कि ईरान, क्युबा तथा उत्तर कोरिया को छोडकर बाकी

सभी देशों के केन्द्रिय बैंकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहूदी नियंत्रित बैंक समुहों का नियंत्रण है।

केन्द्रिय बैंक जनता को गरीब बनाते है !

बैंकर्स जब कर्ज लेना आसान बनाते है तो ज्यादा लोग कर्जा लेते है। बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। तब कच्चा माल इ. महंगा हो जाता है। जब कर्जा लिये हुए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तब केन्द्रिय बैंक कर्जा मिलना बेहद मुश्किल कर देते है। कर्जदार और कर्जा न मिलने से तबाह और बर्बाद हो जाता है। बैंक उसकी चल अचल संपत्ति को बेहद कम मुल्य पर अपने कब्जे में कर लेते है। इस तरह बैंकों को बेशुमार फायदा होता है। मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करने वाले आधुनिक बैंकर्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रख सकते है और जब चाहे तब आर्थिक संकट पैदा कर कर्जदारों को दिवालिया तथा लोगों को और ज्यादा गरीब बना सकते है। बैंकर्स के पास हर पूंजीपति की आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा होता है। बैंकर्स उद्योगपतियों को मिलने वाली पूंजी की मात्रा पर नियंत्रण रखकर उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते है। बाजार में वस्तुओं की मात्रा कम हो जाये तो चीजें महंगी और मात्रा ज्यादा हो जाये तो चीजे सस्ती हो जाती है। वह अपने एजेन्ट मजदूर नेताओं के माध्यम से कारखानों में हड़ताल करवाकर या हड़ताल ना करवाकर न सिर्फ उत्पाद की मात्रा को बल्कि उद्योगपति की आमदानी को भी प्रभावित करते है। पूंजी की आपूर्ति पर नियंत्रण से वे पूंजीपतियों को नियंत्रित करते है, उनका भविष्य अपने मन के मुताबिक तय करते है।

अध्यक्ष गारफील्ड (Garfield) ने कहा कि जो भी कोई देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, वह देश के उद्योग तथा व्यापार का असली मालिक है और जब आप यह अनुभव करते है कि पूरी यंत्रणा को चंद ताकतवर लोगों व्दारा बडी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, तुम्हे यह बताने की जरूरत नही होगी कि कैसे मुद्रास्फिती और डिप्रेसन के दौर पैदा होते है। चंद दिनों बाद ही अध्यक्ष गारफील्ड की हत्या कर दी गई। अध्यक्ष थॉमस जेफर्सन ने बयान दिया कि अगर अमेरिकन जनता कभी निजी बैंकों को देश की मुद्रा जारी करने का अधिकार देती है तो पहले इन्फ्लेशन (बहुत ज्यादा मुद्रा जारी होना) और बाद में डीफ्लेशन (बहुत कम मुद्रा उपलब्ध होना) के जरिये बैंक तथा कार्पोरेशन्स बेतहाशा धन बटोरेंगे और लोगों को उनकी संपत्ति से तबतक वंचित करते रहेंगे जब एक दिन उनके बच्चे नींद से जागकर देखेंगे कि वे बेघर हो चुके है।

बैंकों की पूरजोर कोशिश होती है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्जदार बनाए। इसके लिये बैंक तरह तरह के प्रलोभन वाले क्रेडिट कार्ड जारी करते है। विलासिता की वस्तुएं क्रेडिट कार्ड के जरिये खरीदने पर भारी डिस्काउंट का लालच दिया जाता है। आज हालात यह है कि अधिकतर अमेरिकी नागरिकों ने अपनी आने वाले दशकों तक की आमदानी इन क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से खर्च की है। हजारों अमेरिकन ब्याज चुकाने की हालत में नही होने से खुदकशी कर रहे है।

रोथ्सचिल्ड परिवार ('The Rothschilds')

सन 1760 में यहूदी मेयर अम्सचेल बाउअर (Mayer Amschel Bauer) ने अपना नाम बदलकर मेयर अम्सचेल रोथ्सचिल्ड (Rothschild) किया। वह सरकारों और राजघरानों को कर्जा देता था क्योंकि दिये जाने वाले कर्ज की गॅरन्टी राज्य को जनता से मिलने वाला टॅक्स होता है। नाथान रोथ्सचिल्ड ने सन 1809 में लंडन में अपना बैंक कायम किया। उसके चार भाईयों के भी फंक्फर्ट, पॅरिस, विएन्ना तथा नेपल्स में बैंक थे। वह अपनी कुरियर नेटवर्क का इस्तेमाल नेपोलियन के खिलाफ चल रहे युद्ध में वेलिंगटन (Wellington) की सेना को धन इ. पहुंचाने के लिये भी करता था। नेपोलियन चाहता था कि यहूदियों ने उसके साम्राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिये। यूरोप के देश यहूदियों के कर्जें तले दबे थे। रोथ्सचिल्ड ने यूरोप के देशों के राजाओं को नेपोलियन के खिलाफ भारी मात्रा में कर्ज जारी किया जो नेपोलियन के खिलाफ अपनी सेना भेजने को राजी थे। जब विजयी नेपोलियन इल्बा (Elba) से वापस लौटा तो वाटरलु में नेपोलियन का बहुत बड़ी सहयोगी देशों की सेना से सामना हुआ और नेपोलियन को परास्त होना पडा। नाथान रोथ्सचिल्ड को सबसे पहले पता चला कि नेपोलियन हार गया है। शेयर बाजार में उसने इंग्लैंड के सरकारी बांड बेचने शुरू किये जिससे यह संकेत गया कि युद्ध में इंग्लैंड हार गया है। घबराकर लोगों ने सरकारी बांड बेचने शुरू किये। सरकारी बांडों की कीमत बेतहाशा गीर गई। तब नाथान रोथ्सचिल्ड ने अपने एजेन्टों के जरिये सारे बांड खरीद लिये। उसे बेशुमार फायदा हुआ जबकि हजारों लोग तबाह-बर्बाद हुए।

रोथ्सचिल्ड ने यूरोप के देशों के हुक्मरानों को आदेश दिया कि वे ऐसा मसौदा तैयार करे जिससे यूरोप का कोई भी देश नेपोलियन की तरह शक्तिशाली न हो सके। "सत्ता-संतुलन" योजना बनाई गई जिसके मुताबिक कोई भी देश बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगे तो यूरोप के बाकी देश मिलकर उसपर हमला करेंगे। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी देश इतना ताकतवर नहीं हो पाएगा कि वह यहूदी सत्ता को चुनौति दे सके। विएन्ना काँग्रेस ने यहूदियों के खिलाफ जो थोड़े से प्रतिबंध थे वे भी समाप्त करा दिये।

अमेरिका में निजी बैंकों का गठन !

अमेरिका ने क्रांतियुद्ध मुख्यतः इंग्लैंड के राजा जार्ज तृतीय के उस करेंसी कानून के खिलाफ लडा जिसमें ब्रिटीश वसाहतों को अनिवार्य किया गया था कि वे बैंक ऑफ इंग्लैंड से ब्याज पर हासिल की हुई मुद्रा का ही अपनी वसाहतों में उपयोग करें। इस क्रांतियुद्ध के बाद अमेरिका की सरकार ने अपनी खुद की मुल्यों पर आधारित मुद्रा जारी की ताकि इंग्लैंड के निजी बैंक अमेरिका का धन व्याज के रूप में ना बटोर सके। लेकिन बैंकर्स ने देश के भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ मिलाकर अमेरिका में पहला निजी केन्द्रिय बैंक कायम करने में कामयाबी हासिल की। इस बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह-बर्बाद कर दिया। इसलिये अमेरिकी काँग्रेस ने इसके चार्टर का

दोबारा नवीनीकरण करने से इन्कार कर दिया। अमेरिकी काँग्रेस खुद की सरकारी मुद्रा जारी करना चाहती थी। नाथान मेयर रोथ्सचिल्ड ने अमेरिकी सरकार को धमकी जारी की "या तो चार्टर के नविनीकरण की अर्जी को मंजूर किया जाये वरना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका खुद को बेहद तबाही वाले युद्ध में घिरा जाएगा। अमेरिकी काँग्रेस ने चार्टर का नविनीकरण करने से इन्कार किया। तब नाथान मेयर रोथ्सचिल्ड ने ब्रिटेन की सरकार से कहा कि इन बेअदब अमेरिकनों को सबक सिखायें और उन्हें दोबारा से उपनिवेशिक स्तर पर लाये। ("Teach those impudent Americans a lesson ! Bring them back to colonial status !")

ब्रिटीश प्रधानमंत्री स्पेंसर पेरसेवाल (Spencer Perceval) ने अमेरिका से युद्ध करने से इन्कार कर दिया कि इंग्लंड की सेनाएं पहले से ही नेपोलियन के खिलाफ युद्धरत है। स्पेंसर की हत्या की गई और राबर्ट बैंक जेन्कीनसन (Robert Banks Jenkinson) को प्रधानमंत्री बनाया गया। रोथ्सचिल्ड द्वारा नियंत्रित बैंक ऑफ इंग्लैंड से पूरी पूरी आर्थिक मदद पाकर ब्रिटेन ने सन 1812 में अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू किया। भले ही अमेरिका यह युद्ध जीत गया इसके बावजूद भ्रष्ट नेताओं के माध्यम से अमेरिकी काँग्रेस को मजबूर किया गया कि वह नये चार्टर को मंजूर कर नये निजी अमेरिकन बैंक को व्याज पर मुद्रा जारी करने का अधिकार दे।

सन 1832 में एन्ड्रयु जॅकसन (Andrew Jackson) ने अमेरिकी अध्यक्ष के चुनाव में यह प्रचारित किया कि "जॅकसन और कोई बैंक नहीं" (Jackson And No Bank!) जॅकसन ने कहा कि "तुम लोग गुफा के विषैले दांतों वाले चोर हो, और मैं तुम्हे भगा देना चाहता हूं, और ईश्वर की सौगंध है कि मैं तुम्हे भगाकर ही दम लुंगा ("You are a den of thieves vipers, and I intend to rout you out, and by the Eternal God, I will rout you out.") सन 1838 में 8 जनवरी को अध्यक्ष जॅकसन ने राष्ट्र के कर्ज की अंतिम किश्त चुकाई। राष्ट्र को कर्ज से मुक्त करने वाले वे इकलौते अमेरिकी अध्यक्ष थे।

अमेरिका का गृहयुद्ध !

सन 1861 में जब दक्षिण कैरोलिना अमेरिकी युनियन से अलग हुआ तब अमेरिकन गृहयुद्ध शुरू हुआ। दक्षिणी राज्य गहरे आर्थिक संकट में थे क्योंकि उत्तरी राज्यों के उद्योगपतियों ने व्यापारिक आयात-निर्यात नियमों (trade tariffs) का इस्तेमाल करते हुए दक्षिणी राज्यों को यूरोप से सस्ते मूल्य पर चीजें खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसका नतिजा यह हुआ कि यूरोप ने दक्षिणी राज्यों से कपास का आयात करना बंद कर दिया। फलस्वरूप दक्षिणी राज्य को चीजों की ज्यादा कीमत देनी पडी जबकि उसकी आमदानी बहुत कम हो गई थी। यही युद्ध की असली वजह थी। इस गृहयुद्ध का काले वंशियों की गुलामी से संबंध नहीं है क्योंकि अमेरिकी अध्यक्ष लिंकन ने कहा था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी प्रथा में हस्तक्षेप करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मकसद अमेरिकन युनियन को बचाना है चाहे फिर वह गुलामों को आजाद करके बचती है या फिर गुलामों को आजाद किये बिना बचती है।

अध्यक्ष लिंकन को अमेरिका की रक्षा के लिये धन की जरूरत थी। सूदखोरों ने 24% से 36% की व्याज दर मांगी। तब लिंकन ने सरकारी मुद्रा छापनी शुरू की। टाईम्स ऑफ लंडन ने बैंकर्स के इशारों पर अपने अंक में छापा कि उत्तरी अमेरिका अपनी खुद की मुद्रा छापकर अपने सारे कर्ज चुकाकर कर्जमुक्त हो जाएगा। उसके पास अपने व्यापार को जारी रखने के लिये पर्याप्त धन होगा। वह एक बेहद संपन्न देश बन जाएगा। तब विश्व के दूसरे देशों के प्रतिभाती व्यक्ति और दूसरे देशों का ध्यान उत्तरी अमेरिका में जाना शुरू होगा। ऐसी सरकार को अवश्य ही ध्वस्त कर देना चाहिये वरना वह दुनियां भर के राजतंत्रों का नाश कर देगा। बैंकर्स उत्तरी अमेरिका को यूरोप के देशों की सेनाओं के माध्यम से कुचल देने के लिये बेताब थे। रूस के जार अलेक्झांडर द्वितीय ने यह ऐलान किया कि इंग्लैंड या फ्रांस अगर अमेरिका के गृहयुद्ध में दक्षिणी राज्य की मदद करता है तो रूस इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा। जार अलेक्झांडर द्वितीय ने अपने पॅसिफीक जहाजों के बेड़े के एक हिस्से को सॅन फ्रांसिस्को के बंदरगाह पर तैनात किया और ब्रिटेन तथा फ्रांस के उत्तरी अमेरिका के खिलाफ युद्ध करने के इरादों पर पानी फेर दिया। इसके पहले जार ने बैंकर्स के रूस में केन्द्रिय बैंक कायम करने की कोशिशों को नाकाम किया था। रूस भली भांति जानता था कि अमेरिका का ब्रिटेन तथा फ्रांस के नियंत्रण में आने का मतलब अमेरिका का बैंकर्स के नियंत्रण में आना है। बैंकर्स की ताकत का ऐसा विस्तार रूस के लिये बड़ा खतरा साबित होता।

सन् 1864 में अमेरिकी अध्यक्ष लिंकन को आठ नवंबर को दोबारा चुना गया। सन् 1865 की April 14th को लिंकन को गोलियों से हलाक किया गया। कॅनेडियन अटार्नी जनरल गेराल्ड जी. मॅकगीर (Gerald G. McGeer) ने कहा कि अंतर्राष्ट्रिय बैंकर्स केन्द्रिय बैंक को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे तथा वे यह भी चाहते थे कि अमेरिका सोने के मानक (Gold Standard) को अपना ले। जबकि लिंकन सरकारी मुद्रा ग्रीनबैंक का मानक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की साख को मानते थे। बैंकर्स अमेरिका तथा विश्व के सभी देशों पर सोने का मानक थोपना चाहते थे क्योंकि बैंकर्स शुरू से ही अन्य देशों को सोने के लिये खुद पर निर्भर बनाने के लिये भारी मात्रा में सोने का संग्रह करते रहे थे। अंतर्राष्ट्रिय व्यापार में कागज की मुद्रा का समर्थन सोने, चांदी इ. द्वारा होना चाहिये वरना जरूरी सामानों की आपस में अदलाबदली (barter) ही विकल्प रहता है।

सन् 1872 में रोथ्सचिल्ड नियंत्रित बैंक ऑफ इंग्लैंड ने Ernest Seyd को अमेरिका भेजा। उसे \$100,000 दिये गए थे ताकि वह अमेरिकी कॉॅंग्रेसमेन को घूस देकर चांदी के सिक्के बंद कराये (silver demonetization) और सोने के मानक को मंजूर कराये। बैंकर्स चांदी के खिलाफ थे क्योंकि पश्चिमी अमेरिका में भारी मात्रा में चांदी पाई जाती थी। एक साल के भीतर ही अर्नेस्ट कामयाब हुआ और चांदी का डिमानिटाइज़ेशन हुआ और सोने के मानक को लागू किया गया।

सन् 1907 में बैंकर्स अमेरिका के लिये दूसरा निजी केन्द्रिय बैंक स्थापित करना चाहते थे। रोथ्सचिल्ड के खासमखास जॅकोब स्चीफ (Jacob Schiff) ने न्यू यार्क

चेंबर ऑफ कामर्स में अपने भाषण में धमकाया कि अगर हमें कर्ज के स्रोतों (credit resources) पर नियंत्रण करने में सक्षम केन्द्रिय बैंक की इजाजत नहीं दी जाती है तो अमेरिका में ऐतिहासिक आर्थिक संकट देखने को मिलेगा। इसके बाद जे.पी.मार्गन तथा उसके साथियों ने पूरी गोपनीयता से शेयर बाजार को आँधे मुंह गिराया (crashed)। हजारों छोटे बैंक जिनके पास बहुत कम संरक्षित धन (reserve) था वे बुरी तरह प्रभावित हुए। इस आर्थिक संकट से घबराकर अमेरिकन कॉंग्रेस ने रोथ्सचिल्ड के दबाव में दूसरे केन्द्रिय बैंक को मंजूरी दे दी और मार्गन ने \$200,000,000 की निजी मुद्रा जारी की। इस तरह चंद लोगों के हाथों में बैंकिंग की ताकत सिमट गई।

यहूदियों को आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं !

यहूदी रुस की ग्रामीण जनता का क्रूर शोषण करते थे। इसलिये जार ने आज्ञा जारी की थी कि यहूदी अपने क्षेत्र (Pale) से बाहर नहीं जा सकते। इसपर अमेरिका के यहूदी बैंकर्स ने मांग की कि अमेरिका रुस के खिलाफ फौरन युद्ध छेड़ दे और रुस को अपने आदेश को वापस लेने पर मजबूर करे। अमेरिकी अध्यक्ष Taft ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब यहूदियों ने रिपब्लिकन पार्टी को अगले चुनाव में विभाजित कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार डेमोक्रेट वुडरू विल्सन (Woodrow Wilson) को विजयी बनाया। संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंकर्स अपने मकसद के लिये भारी तादाद में गैर-यहूदी एजेन्ट खरीद सकते हैं।

अमेरिका का फेडरल रिजर्व !

जेकिल आईलैंड क्लब हॉटेल के कमरे में हुई कॉन्फ्रेंस में वारबर्ग (Warburg) ने नेशनल रिजर्व बिल या फेडरल रिजर्व बिल लाने का प्रस्ताव किया। कर्जों के सूद के भुगतान की गॅरन्टी सरकारी टॅक्स था। षडयंत्र के तहत अमेरिकन कॉंग्रेस ने फेडरल रिजर्व एक्ट को सन 1913 में क्रिसमस की छुट्टीयों के दौरान तब पास किया जब इस बिल का विरोध करने वाले अधिकांश सदस्य छुट्टी पर अपने घर गए हुए थे। बैंकर्स के खासमखास अध्यक्ष वुडरू विल्सन (Woodrow Wilson) ने इस बिल की मंजूरी पर हस्ताक्षर किये। वास्तव में फेडरल रिजर्व पर निम्नलिखित बैंकों की मिल्कियत है :- Rothschild Bank of London, Warburg Bank of Hamburg, Rothschild Bank of Berlin, Lehman Brothers of New York, Lazard Brothers of Paris, Kuhn Loeb Bank of New York, Israel Moses Seif Banks of Italy, Goldman, Sachs of New York, Warburg Bank of Amsterdam, Chase Manhattan Bank of New York. अमेरिका के अध्यक्ष सात में से सिर्फ दो सदस्यों को फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर 14 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करते हैं। यह दो लोग भी बैंकर्स के ही आदमी होते हैं।

बैंकर्स ने ही शेअर बाजार का आर्थिक संकट पैदा किया था। इस नियोजित आर्थिक संकट के कुछ हफ्ते पहले ही योजना के मुताबिक 3 बिलियन डॉलर की संपत्ति

चंद लोगों के हाथों में सिमटती चली गई थी। बैंकर्स ने क्रॉश के ठिक पहले भारी तादाद में सोना खरीदकर उसे यहूदी बैंकरों के मुख्यालय भेज दिया था। सन 1974 में न्यू यार्क पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि रॉकफेलर परिवार फेडरल रिजर्व को अपना माध्यम बनाकर Fort Knox के सोने को बहुत ही कम मुल्य पर यूरोप के अज्ञात शेअर बाजारियों (speculators) को बेच रहा है। इसके तीन दिन बाद ही नेल्सन रॉकफेलर की सचिव Louise Auchincloss Boyer रहस्यमय तरीके से न्यू यार्क में बिल्डिंग के दसवें मंजिल स्थित अपने फ्लॉट की खिड़की से गीर कर मर गई। अमेरिकी सरकार ने अफवाहों पर विराम देने के लिये Fort Knox में रखे सोने का ऑडिट भी नहीं कराया। सन 1982 में अध्यक्ष रीगन के "गोल्ड कमीशन" ने अमेरिकी कॉंग्रेस को बताया कि अमेरिका की ट्रेजरी के पास खुद का कोई सोना नहीं है। Fort Knox में रखा हुआ सोना अब राष्ट्रीय कर्ज के एवज में फेडरल रिजर्व का है।

विश्व युद्धों का कारण निजी केन्द्रिय बैंक !

निजी केन्द्रिय बैंक के गठन से लेकर विश्वयुद्ध के होने के बीच तीन चरण हैं। पहले चरण में केन्द्रिय बैंक देश को अपने कर्ज में जकड़ लेता है। दूसरे चरण में जब लोग कर्जा लेने की हालत में नहीं होते तब केन्द्रिय बैंक सरकारों को कर्जा लेने पर बाध्य करते हैं। तीसरे चरण में जब जनता और सरकार दोनों ही कर्जा लेने की हालत में नहीं होते तब दूसरे देशों के खिलाफ युद्ध कर उनकी संपत्ति से घाटा पूरा करने की कोशिश की जाती है। सन 1907 के आर्थिक संकट के बाद पहला विश्व युद्ध हुआ। सन 1929 के आर्थिक संकट के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ। सन 2008 के आर्थिक संकट के बाद से अब तक तिसरा विश्वयुद्ध जारी है।

पहले विश्वयुद्ध के जरिये यहूदी बैंकर्स ने जर्मनी को गुलाम बनाया !

जर्मनी एक मुख्य शक्ति था। निजी केन्द्रिय बैंक पर सख्त नियंत्रण होने से मुद्रा स्थिरता पर नियंत्रण था। सरकारी नियंत्रण में निवेश को आंतरिक आर्थिक विकास के लिये सुनिश्चित किया गया था। इस वजह से बैंकर्स जर्मनी से नफरत करते थे तथा उसे तबाह-बर्बाद करना चाहते थे।

सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरु हुआ। युद्ध जितने के लिये कोई भी देश चाहे जितना कर्जा लेने पर आमादा रहता है। युद्ध के दोनों ही पक्षों को बैंकर्स ने कर्जा दिया। लेकिन बैंकर्स जिसे हराना चाहते थे उसे सिर्फ उतना ही कर्जा देते थे जिससे उसे जितने की आशा बनी रहे। कर्ज इस शर्त पर दिये जाते थे कि जितने वाला मुल्क हारने वाले मुल्क के सारे कर्ज चुकाने के लिये बाध्य होगा। रोथसचिल्ड परिवार सदस्यों ने जर्मनी, ब्रिटीश तथा फ्रेंच सरकार को कर्जा दिया। सन 1915 में जे.पी. मार्गन युद्ध दरत ब्रिटीश तथा फ्रेंच दोनों के लिये "युद्ध साहित्य बोर्ड" का बिक्री प्रतिनिधि था। अध्यक्ष वुडरु विल्सन ने बैंकर बर्नार्ड बरुच (Bernard Baruch) को युद्ध उद्योग बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया। इतिहासकार जेम्स परलॉफ (James Perloff) के मुताबिक

बनार्ड बरुच तथा रॉकफेलर दोनों को ही प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 200 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ। हजारों लोग जो युद्ध में देश के नाम पर मरते हैं वे बैंकर्स के फायदे के लिये अपनी जान देते हैं।

जर्मनी को पराजित कर उसके औद्योगिक साम्राज्य को धरायाशी किया गया। Versailles के समझौते के तहत जर्मनी को आदेश दिया गया कि वह विजेता देशों को युद्ध का खर्च अदा करे जबकि जर्मनी ने युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। अदा किया जाने वाला युद्ध का खर्च जर्मनी की कुल चल अचल संपत्ति की कीमत से तीन गुना ज्यादा का था।

हिटलर का उदय !

जर्मनी के अपमान से संतप्त जनता ने हिटलर को बागडौर थमाई। हिटलर ने सरकारी मुद्रा जारी की। इस कदम से जर्मनी का तेजी से विकास होने लगा और जल्द ही उसने अपने उद्योगों को दोबारा से खडा किया। मीडिया ने इसे "जर्मन आश्चर्य" करार दिया। टाईम पत्रिका ने हिटलर को सन 1938 का "मैन ऑफ द यीअर" करार दिया। बाढ नियंत्रण, सरकारी इमारतों तथा लोगों के घरों की मरम्मत, नई इमारतों का निर्माण, सडके, पुल, नहरें तथा बंदरगाह इ. प्रकल्प बनाये गए। लाखों लोगों को काम दिया गया। सरकारी खजाने के प्रमाणपत्र (Treasury Certificates) जारी किये गए। प्रमाणपत्र बांड थे तथा सरकार धारक को ब्याज अदा करती थी। इन प्रमाणपत्रों को विदेशी मुद्रा बाजार में बेचा या खरीदा नहीं जा सकता था इसलिये वे बैंकर्स की पहुंच के बाहर थे और उनका मुल्य स्थिर था। मजदूर इनसे अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। जर्मनी का विश्व स्तर पर आर्थिक बहिष्कार किया गया था। जर्मनी ने देशों के बीच जरूरत की चीजों की अदलबदली कर विदेशी व्यापार को अंजाम दिया। इससे न ही कोई कर्जा हुआ और न ही कोई घाटा। जैसे ही हिटलर ने बैंकर्स के समुह को अलविदा कह दिया था जर्मनी का अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ। मात्र दो सालों में ही जर्मनी की बेरोजगारों की समस्या हल हुई। उस वक्त लाखों लोग अमेरिका तथा पश्चिमी देशों में बेरोजगार थे और सरकारी मदद से गुजारा कर रहे थे।

जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन ग्रेट ब्रिटेन के लिये खतरा बना। जर्मनी की सरकारी मुद्रा निजी केन्द्रिय बैंकों के लिये खतरा थी। जर्मनी के खिलाफ विश्वयुद्ध छेडने के षडयंत्र बनाए गए।

अध्याय 3

माक्स तथा एंगेल्स बेनकाब !

माक्स तथा एंगेल्स संपन्न परिवारों से थे !

कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 में 5 मई को Trier (प्रुसिया/जर्मनी) में हुआ। मार्क्स का यहूदी नाम Moses था। उसके पिता Hirschel सर्वोच्च न्यायालय में जज थे। Hirschel के पिता कोलोन (Cologne) शहर के प्रसिद्ध मुख्य रँबी थे। मार्क्स के चाचा बेंजामिन फिलिप्स एक बहुत ही धनी बैंकर तथा उद्योगपति थे। कार्ल मार्क्स की दादी Nanette Barent-Cohen प्रसिद्ध धनाढ्य Henriette Barent-Cohen की कजन (cousin) थी जिसने नाथान मेयर रोथ्सचिल्ड से विवाह किया था। तब यहूदियों को कानून के व्यवसाय में प्रवेश की इजाजत नहीं थी इसलिये मार्क्स के पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण कर यहूदी धर्म का पालन गुप्त रूप से जारी रखा था। मार्क्स का बाप्तिस्मा सन 1824 में हुआ। तब उसका नाम कार्ल रखा गया। कार्ल की शिक्षा यहूदी स्कूल में भी हुई जहाँ उसने सीखा कि यहूदियों का लक्ष्य सारी दुनियां पर राज करना है। मार्क्स की माता का परिवार धनी बैंकर्स तथा उद्योगपतियों से था। उसके पिता रँबी थे।

मार्क्स पूंजीपतियों की संगत में रहता था। मार्क्स को उत्तम भोजन तथा फ्रांसीसी शराब की तीव्र चाहत (craving) थी। वह फ्रांसिसी शराब का आयात करता था। उसके परिवार को मंहगी आदतें थी। मार्क्स को शेअर बाजार में भारी नुकसान हुआ। मार्क्स की बिबी Jenny Von Westphalen प्रुसीया के शासक वर्ग की एक शिक्षित baroness थी। एक डांस पार्टी में उसने एक बेहद धनी युवक का विवाह प्रस्ताव मंजूर किया था जिसकी अधिकारिक घोषणा भी कर दी गई थी। उसके पिता ने यह सगाई तोड़ दी ताकि मार्क्स के साथ उसका विवाह किया जा सके। कोई भी यह सवाल नहीं करता कि अगर मार्क्स बेहद गरीब था तो वह प्रुसियन शासक वर्ग की एक उच्चशिक्षित baroness से विवाह करने में कैसे कामयाब हुआ ? यह झुठमूठ प्रचारित किया गया है कि जेनी और मार्क्स बचपन के दोस्त थे। एक सोलह साल की लडकी बारह साल के कार्ल मार्क्स में कैसे रुची रख सकती है ? तब जेनी ने अपनी सगाई दूसरे से क्यों की थी ? जेनी के दादा ब्रुंसविक (Brunswick) के ड्युक (Duke) फर्डिनांड (Ferdinand) के चीफ ऑफ स्टाफ थे। इसके बावजूद इतिहासकार बताते हैं कि मार्क्स गरीबी में जी रहा था, अपने गुजारे के लिये औरों से कर्जे पर निर्भर था। हकीकत यह है कि उन्हें परिवारिक ट्रस्ट द्वारा धन हासिल था। धन की थैली के लिये बस एक खत या फोन कॉल करने भर की देरी थी।

कार्ल मार्क्स के शिक्षक !

यहूदी उद्योगपति का पुत्र मोजेस हेस कार्ल मार्क्स का शिक्षक था। सन 1841 में हेस ने Rheinische Zeitung नामक समाचार पत्र शुरु कर एक साल बाद मार्क्स को उसका संपादक बनाया। हेस ने मार्क्स को Freemasonry संगठन में शामिल कराया। वह मार्क्स को दीशानिर्देश देता था। हेस ने ही मार्क्स को एंगेल्स से मिलाया। हेस का विश्वास था कि अंतर्राष्ट्रियतावाद यहूदिवाद के उद्देश्यों को पूरा करता है। (Moses Hess, "Selected Works", Cologne, 1962.)

मार्क्स के दूसरे गुरु का नाम लेवी बरुच (Levi Baruch) है। बरुच के मुताबिक अगर कोई यहूदी क्रांतिकारी यहूदिवाद को नकारता है तो उसे समाज का विश्वासघाति

माना जाना चाहिये। यहूदी क्रांतिकारियों ने समाजवादी शब्दावली में अपने यहूदीवाद को छुपाये रखना चाहिये। बरुच ने मार्क्स को अपने खत में समझाया कि कैसे सर्वहारा वर्ग की मदद से यहूदियों को सत्ता शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। तलमूद की भविष्यवाणी को साकार करते हुए ऐसी सरकारों का नेतृत्व यहूदी करेंगे जो निजी संपत्ति पर प्रतिबंध लगाकर administrators की हैसियत से चल-अचल संपत्तियों को यहूदियों के हाथों में केन्द्रित कर देंगे। बरुच ने स्पष्ट किया कि यहूदीवाद का मूल उद्देश्य पूरी दुनियां पर राज करना तथा अंततः तलमूद पर आधारित राज्य को कायम करना है। (Salluste, "Les origines secretes du bolchevisme", Paris, 1930, pp. 33-34.)

बकुनीन के मुताबिक मार्क्स की सोच यहूदीवाद से विकसित हुई थी। अपनी किताब God and the State में बकुनिन कहते हैं कि लोगों ने जितने भी ईश्वरों की पूजा की है उन सब में याहवेह (Yahweh) सबसे ज्यादा ईर्षालू, व्यर्थ-घमंडी, क्रूरतम, घोर अन्यायी, खून का प्यासा, सबसे बड़ा तानाशाह तथा इन्सानी आत्मसम्मान और आजादी का घोर विरोधी रहा है। यह जताने के लिये कि यहूदियों का धर्म साम्यवाद का विरोधी है, मार्क्स, Pierre Joseph Proudhon, Francois Marie Charles Fournier इ. यहूदी कम्युनिस्ट, यहूदियों की आलोचना करते थे। सन 1844 में मार्क्स ने अपने लेख "On the Jewish Question" में लिखा कि यहूदियों ने लगभग सारे यूरोप पर अपना नियंत्रण कर लिया है, यहूदियों का इस दुनियां में ईश्वर पैसा है तथा उनका सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय धोखे से भारी व्याज दर पर लोगों से पैसे वसूलना है। यह यहूदियों के धर्म की गहरी बुनियाद है। हर किसी तानाशाह के पीछे हमेशा ही कोई यहूदी नजर आता है। मार्क्स की तरह दिगर कम्युनिस्ट नेता साम्यवाद के तलमूद वाले आधार को छुपाने के लिये यहूदी विरोध का दिखावा करते थे। (Under the sign of Scorpion by Juri Lina)

मार्क्स शराबी, तानाशाह तथा विश्वासघाति था !

Giuseppe Mazzini ने लिखा है कि मार्क्स का दिल इन्सानों के प्रति प्रेम की बजाय नफरत से फट पडता है। कार्ल एक विध्वंसकारी चेतना है। (Fritz Joachim Raddatz, "Karl Marx: Eine Politische Biographie", Hamburg, 1975.) मार्क्स ने एंगेल्स को खत में लिखा था कि कल हमे यह पता चला कि मेरी बिबी के नब्बे साल के चचा का देहांत हो गया। जेनी को £100 या उससे ज्यादा की रकम हासिल होगी अगर बूढ़ा कूत्ता अपनी जायजाद का कुछ हिस्सा अपने हाउसकीपर के लिये नहीं छोडता है। (p.112- RED JENNY A Life with Karl Marx, by H.F. Peters) इससे पता चलता है कि वह अपने रिश्तेदारों के प्रति कैसी भाषा का प्रयोग करता था।

मार्क्स की रातें शराब से सराबोर झगडालू पाटियों भरी होती थी। कॉलोन (Cologne) शहर में शराब में धुत होकर मारपीट करने तथा प्रतिबंधित हथियार (शायद पिस्तोल) रखने के जुर्म में मार्क्स को एक रात जेल में गुजारनी पडी थी। पॅरिस में सारी बैठकें बंद कमरे में ली जाती थी ताकि मार्क्स की चीखने-चिल्लाने की आवाज बाहर ना पहुंच सके। मार्क्स की मार्क्स एंगेल्स इंस्टीटयुट के डायरेक्टर Riazanov

ने स्वीकार किया है कि मार्क्स बेतहाशा शराब पीता था।

प्रुसिया के पूर्व लेफ्टीनंट von Techow ने Vogt के पर्वे में उदघोषित किया है। यह बताया गया कि अगस्त 1850 में वह कम्युनिस्ट लीग के नेता कार्ल मार्क्स से लंदन में मिला और मार्क्स तथा एंगेल्स सहित उनके कुछ मित्रों के साथ अपनी शाम एक शराबखाने में बिताई। मार्क्स पूरी तरह नशे में धुत हो गया। मुझे अफसोस है कि हमारे सामान्य मकसद की खातीर इस आदमी में एक सभ्य दिल नहीं है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो चुका है कि उसकी खुद की बहुत ही खतरनाक निजी महत्वाकांक्षा ने उसके भीतर की अच्छाई को खा लिया है। अपने ही पार्टी के अनुयायी की उपरोक्त आलोचना पढ़कर मार्क्स तिलमिला उठा था।(p.125- RED JENNY A Life with Karl Marx, by H.F. Peters) मार्क्स के सहायक Karl Heinzen के मुताबिक मार्क्स अनियंत्रित रूप से अहंकारी (egoist), झूठा तथा षडयंत्रकारी था जो सिर्फ औरों का शोषण करना जानता था।(Karl Heinzen, "Erlebtes", Boston, 1864.) मार्क्स क्रूर तानाशाही मानसिकता का था।

संगठन को तानाशाह तरीके से चलाने के कारण मार्क्स की हत्या की जानी थी। (Enault, Paris brute par la Commune p. 23; Beaumont Vassy La Commune de Paris, p. 9) लेकिन मार्क्स बचकर लंदन भागने में कामयाब हो गया और लंदन में ही बस गया। (KARL MARX DEBUNKED by Leon Hamilton, Social Justice)

लेनचेन (हेलन डेमुख) 25 साल की सुनहरे बालों वाली दूबली-पतली लडकी थी। वह मार्क्स की बिबी जेनी से 4 साल छोटी थी। लेनचेन को मार्क्स से एक बेटा हुआ। (p.101) जब जेनी ने उससे बच्चे के पिता के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मार्क्स ने बताया कि शायद बच्चे का बाप एंगेल्स था। उसने एंगेल्स को पार्टी के हितों का हवाला देते हुए कहा कि वह कबूल कर ले की वह लेनचेन के बच्चे का पिता है। एंगेल्स तैयार हुआ लेकिन उसने साफ कहा कि उसका इस बच्चे से कोई सारोकार नहीं होगा। बच्चे को एक इंग्लिश परिवार को गोद में देना तय हुआ। लेनचेन की मर्जी के खिलाफ किये गए इस फैसले से उसके दिल पर क्या बिती होगी इसका पता उसकी वसीयत से पता चलता है कि वह अपने बच्चे से कितना प्यार करती थी। जब जेनी को विश्वास हो गया कि लेनचेन के बच्चे का पिता मार्क्स ही है तो उसे बडा आघात लगा। (p.104-06 - RED JENNY A Life with Karl Marx, by H.F. Peters)

मार्क्स तथा उसकी बिबी जेनी के बीच का रिश्ता बिल्कूल ठिक नहीं रहा था। जेनी ने मार्क्स को दो बार छोड़ दिया लेकिन अंततः हर बार वह वापस आई। जब जेनी की मौत हुई मार्क्स उसकी अंतिम क्रिया के वक्त भी मौजूद नहीं था।(Marx and Satan By Richard Wurmbrand)

कम्युनिस्ट इंटरनॅशनल के सचिव Guillaume के मुताबिक एंगेल्स धनी पूंजीपति था जो औरतों को मशीन तथा तोपों का चारा (machine fodder and cannon fodder) समझता था।(KARL MARX DEBUNKED by Leon Hamilton, Social Justice) एंगेल्स के कई औरतों के साथ संबंध थे। सन 1840s के दशक में एंगेल्स ने

मेरी बर्नस नामक स्त्री के साथ लंबे अर्से तक लैंगिक संबंध कायम रखे। मेरी बर्नस की मौत के बाद उसने उसकी बहन लिझी बर्नस से लैंगिक संबंध कायम किये। उससे तब विवाह किया जब वह अपनी मृत्युशैय्या पर पडी थी। (MARX, ENGELS, AND THE ABOLITION OF THE FAMILY by RICHARD WEIKART, History of European Ideas, Vol. 18, No. 5, pp. 657-672, 1994 0191-6599 (93) E0194-6 _ . Copyright c 1994 Elsevier Science Ltd Printed in Great Britain)

माक्स गैरयहूदी जातियों से नफरत करता था !

माक्स जर्मनी के लोगों से नफरत करता था। वह जर्मनी के लोगों को मूर्ख तथा संकीर्ण राष्ट्रवादी मानता था। माक्स के मुताबिक रूसी नीच लोग थे। वह स्लाव लोगों को वांशिक गटर (ethnic sewer) कहता था। (New York Times, 25th of June 1963.) माक्स की नजर में स्लाव लोग निरुपयोगी (ethnic trash) थे। माक्स तथा एंगेल्स रूसी तथा स्लाव जनता को जंगली (völkerabfall) मानते थे। माक्स ने 1848 के नये साल के राउंडअप (roundup "the Slavic riffraff") में जिसमें रूसी, चेक, तथा क्रोट लोगों का भी समावेश है में लिखा कि यह पिछड़ेपन की ओर अग्रेसर वंशों के लिये इसके सिवा कुछ नहीं बचा है कि वे वैश्वीक इन्केलाबी तुफान में नष्ट कर दिये जाये। आने वाला विश्व युद्ध न सिर्फ प्रतिक्रियावादी वर्गों तथा राजशाही को बल्कि समूचे प्रतिक्रियावादी लोगों को दुनियां से नष्ट कर देगा और यह विकास होगा। माक्स मजदूरों को मूर्ख और गधे तथा किसानों को गुफा में रहनेवाले कहता था। माक्स काले अफ्रीकी वंशीय लोगों को निर्बुद्ध कहकर उनका उल्लेख अपने निजी पत्राचार में निगर (nigger) जैसे अपमानजनक शब्द से करता था। वह उत्तरी अमेरिका में गुलामी प्रथा जारी रखने का हिमायती था। प्राउधोन (Proudhon) से माक्स इस बात पर लड पडता था कि उत्तरी अमेरिका जैसा प्रगतिशील देश गुलामी प्रथा के बिना patriarchal देश में तब्दिल हो जाएगा। अगर हम दुनियां के नक्शे से उत्तरी अमेरिका को हटा दें तो हमें अराजकता - आधुनिक व्यापार तथा नागरी विकास (civilization) का पूरा विनाश नजर आएगा। अगर हम गुलामी प्रथा को खत्म कर दें तो दुनियां के नक्शे से अमेरिका का नामोनिशान मिट जाएगा। (Marx and Satan By Richard Wurmbrand) माक्स की विभिन्न वांशिकताओं के प्रति नफरत उसके तलमूद की शिक्षा में विश्वास होना साबित करती है।

माक्स षडयंत्रकारी और झूठा था !

खुद इंटरनेशनल के सचिव Guillaume के मुताबिक इंटरनेशनल का निर्माण माक्स ने नहीं किया था। सन 1862 से 1864 के दौरान वह इंटरनेशनल से अलिप्त था। उसने इंटरनेशनल में तब प्रवेश किया जब इंग्लीश और फ्रेंच मजदूरों ने उसका विकास किया। माक्स जर्मन वर्कर्स एजुकेशनल असोसिएशन में पहली बार कुछ मजदूरों से मिला। ये मजदूर शिक्षित थे तथा उन्होंने अपने अनुभवों से मजदूरों के संघर्षों के बारे में राजनीतिक समझ हासिल की थी। वे माक्स के विचारों को नापसंद करते थे।

मार्क्स ने यहूदी मजदूरों तथा बुद्धिजीवियों की मदद से इंटरनेशनल पर अपना नियंत्रण कायम किया तथा इन मजदूरों को इंटरनेशनल के उच्च पदों से बाहर किया। दिखावे मात्र के लिये कुछ मजदूरों को कुछ कमिटियों में जगह दी। तब इंटरनेशनल का नेतृत्व मध्यमवर्गीय यहूदी सिधान्तकारों का था जो मजदूर वर्ग के हितों के विरोधी थे।

मार्क्स ने Neue Rheinische Zeitung में बकुनीन पर झूठमूठ आरोप लगाया कि वह जार का एजेन्ट था। आरोप झूठा साबित होने पर मार्क्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी मार्क्स अपने साथियों के माध्यम से इस आरोप को दोहराता रहा। इन सभी षडयंत्रों तथा दुष्प्रचार के बावजूद बकुनीन को अभूतपूर्व जनसमर्थन हासिल था। बकुनीन की सफलता मार्क्स के लिये सबसे बड़ा रोड़ा थी इसलिये मार्क्स ने अपनी तिकडमों से इंटरनेशनल को खत्म होने दिया। (Bakunin and Marx: An Unbridgeable Chasm ? by Paul McLaughlin, University of Tartu)

दास कॅपिटल के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वह परले दर्जे का झूठा भी है। Paul Johnson ने अपनी किताब "The Intellectuals" में इस बात को प्रमाणों से साबित किया है। मार्क्स ने जानबूझकर अपने सिधान्तों का समर्थन करने वाली घटनाएं चूनी, घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा और झूठ को शामिल किया। मार्क्स की इस 354 पेज वाली किताब दास कॅपिटल में झूठी जानकारी तथा गलत जानकारी की मात्रा कुल 23 पेज है। जर्मन अर्थशास्त्री Bruno Hildebrand ने मार्क्स को उसके झूठ के बारे में बताया था और किताब की आलोचना की थी। मार्क्स ने जानबूझकर William Gladstone तथा Adam Smith के कथन को गलत ढंग से लिखा था। उसने अधिकृत (official) रिपोर्ट तक को गलत ढंग से लिखा था। कॅम्ब्रीज के दो संशोधकों ने अपने रिसर्च "Comments on the Use of the Blue Books by Karl Marx in Chapter XV of 'Das Kapital'" (1985) में लिखा है कि मार्क्स ने जानबूझकर झूठी जानकारी दी। मसलन मार्क्स ने यह दावा किया कि रेल दुर्घनाओं की ताददाद बढ़ी है और वे आम हो गई हैं जबकि हालत ठिक इसके विपरित थी। (Under the sign of Scorpion by Juri Lina)

मार्क्स-एंगेल्स ने दूसरों के साहित्य को अपना दर्शाया !

मार्क्स ने अपने सामाजिक सिधान्त Condorcet, Saint-Simon, Auguste Comte इ. से लिये। थेसीस-एन्टीथेसिस तथा सिंधेसिस का सिधान्त जिसका उसने व्दंदात्मक भौतिकवाद नाम दिया उसने उसे हेगेल से लिया। साम्यवादी घोषणापत्र पांच साल पहले Victor Considerant' ने लिखे गए Manifesto of Democracy की नकल है। मार्क्स का अतिरिक्त मुल्य का सिधान्त Proudhon के साहित्य से लिया गया है। मार्क्स का "wage slavery" का सिधान्त फ्रेंच क्रांति के वक्त भी जाना जाता था तथा उसे बाद में Vidal तथा Pecquer ने प्रचारित किया था। इन्होंने ही खदानों, यातायात, दूरसंचार इ. के राष्ट्रीयकरण की वकालत की थी। मार्क्स का साम्यवाद Babeuf, Blanc, Cabet तथा Marat द्वारा बताया साम्यवाद है। मार्क्स का अंतर्राष्ट्रियतावाद Weishaupt तथा Cloutz से लिया गया है। "संपत्ति का मूल

स्त्रोत श्रम है” को इंग्लिश दर्शनशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री Locke, Petty, Adam Smith तथा Owen से लिये गए हैं। अतिरिक्त मुल्य के सिद्धान्त को सबसे पहले Owen ने रखा था तथा Chartists आन्दोलन ने उसे विकसित किया था। मार्क्स ने लिखना शुरू करने के सात साल पहले से ही यह सिद्धान्त प्रसिद्ध किये जा चुके थे। विरासत में जायदाद या धन इ. को प्राप्त करने पर प्रतिबंध, विवाह-संस्था, परिवार, देशभक्ति के विध्वंस, धर्म का खात्मा, स्त्रियों के कम्युनिस्ट, सभी बच्चों की सामाजिक शिक्षा तथा लालनपालन इ. सारी बातें पहले ही “इल्युमिनेंटी” संगठन द्वारा पेश की जा चुकी थी।

मार्क्स ने अपने नारे तक दूसरों से लिये थे। मजदूरों की कोई पितृभूमि नहीं होती तथा “मजदूरों को जंजीरों के सिवा खोने के लिये कुछ नहीं है” यह नारा Jean-Paul Marat का था। मार्क्स ने “धर्म यह लोगों के लिये अफीम है” यह नारा Heinrich Heine से लिया। सबसे पहले Karl Schapper ने “दुनियां के मजदूरों एक हो” का नारा दिया। “सर्वहारा वर्ग की तानाशाही” का नारा भी मार्क्स ने Louis Blanqui से लिया था। सन 1841 में Clinton Roosevelt ने Weishaupt की शिक्षा पर आधारित “The Science of Government, Founded on Natural Law” नामक किताब प्रकाशित की। छह साल बाद मार्क्स ने Roosevelt के सिद्धांतों का उपयोग कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टों में किया।

मार्क्स-एंगेल्स को बहुत कम लोग जानते थे !

मार्क्स के साहित्य से अधिकांश तत्कालीन नेता अनभिज्ञ थे। उस वक्त धनाढ्य जर्मन यहूदी Ferdinand Lassalle तथा Friedrich Albert Lang प्रसिद्ध थे। सन 1867 के सितंबर में प्रकाशित Das Kapital का पहला भाग (volume) पूरी तरह अनाकलनीय था। मार्क्स तथा उसके साथियों ने अलग अलग नामों से खुद ही इस किताब के रिव्यू लिखकर विभिन्न अखबारों तथा पत्रिकाओं में भेजे थे। जेनी ने खुद भी अपने पति की किताब को पूरजोर तरीके से प्रचारित किया। इन प्रयासों के बावजूद पूरे साल में मात्र दो सौ किताबों की ही बिक्री हो सकी। (p. 147-48, 152-RED JENNY A Life with Karl Marx, by H.F. Peters) मार्क्स की दास कैपिटल इतनी रुक्ष और उबाउ है कि उसे पढ़ पाना मुश्किल है। मार्क्स के साथ लगभग 18 साल से पार्टी में काम कर रहे उनके दामाद तक ने यह कबूल किया कि दास कैपिटल उसकी समझ से बाहर है। (KARL MARX DEBUNKED by Leon Hamilton, Social Justice) लोगों ने न ही मार्क्स के विचारों की आलोचना की और ना ही उनका समर्थन किया। जब सन 1883 में मार्क्स की मौत हुई तब चंद अखबारों ने चंद लाईनों में लिखा की कई किताबों के लेखक कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई है। (Marxism Unmasked: From Delusion to Destruction By LUDWIG VON MISES) जब मार्क्स का मार्च 14, 1883 को देहांत हुआ तब सिर्फ छह लोग उसकी अंतयात्रा में शामिल थे। (<http://antnewworldorder.blogspot.in/Silence is Betrayal Who was Karl Marx.html>)

मार्क्स-एंगेल्स का विरोधाभासी व्यवहार !

सन 1865 में कार्ल मार्क्स ने इंटरनॅशनल कमिटी में Value, Price, and Profit नामक लेख पढा। उसने आपत्ति जतायी कि मजदूर मौजूदा पूंजीवादी शासन-व्यवस्था की चौखट के भीतर रहकर ही अपनी हालत को सुधारना चाहते हैं। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों ने समाजवादी इन्केलाव के लिये काम करना चाहिये। सर्वहारा मजदूर वर्ग से नहीं होने के बावजूद मार्क्स सर्वहारा वर्ग की युनियनों के मतों से असहमत होकर उन्हें समझा रहे थे कि मजदूर कैसे गलत हैं और मजदूरों के हित में क्या है। यहां मार्क्स का वर्ग-चरित्र का सिद्धान्त खुद ब खुद टूट जाता है। इस सिद्धान्त के मुताबिक एक व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन संपूर्ण वर्ग अपने हितों को लेकर कतई गलत नहीं हो सकता। मार्क्स ने अपने राजनीतिक जीवन के दूसरे हिस्से में कहा कि पूंजीवाद अपनी परिपक्वता के बाद बिना सशस्त्र इन्केलाव के समाजवादी व्यवस्था में बदल जाएगा। तब मजदूर संगठन पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ने के संघर्षों की हिमायत कर रहे थे। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद को परिपक्व होने दे, उसे सशस्त्र संघर्षों से उखाड़कर फेंकने की कोशिश ना करे। मार्क्स तथा एंगेल्स ने पूरा जोर लगा दिया कि इंटरनॅशनल के सभी संगठन संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने। सन 1872 की हेग में हुई कॉंग्रेस में मार्क्स तथा एंगेल्स ने इंटरनॅशनल को चुनावी मशीनरी में तब्दिल कर दिया।

अलबर्ट कॅमस (Albert Camus) ने अपनी किताब The Revolted Man में कहा है कि मार्क्स तथा एंगेल्स के कुल 30 ग्रंथों (volumes) को जानबूझकर प्रकाशित नहीं किया गया और न ही उनके बारे में कभी कुछ कहा गया। मार्क्सो की मार्क्स इंस्टीटयुट के उपसंचालक (vice director) Professor M. Mtchedlov ने जवाबी पत्र में लिखा कि कुल सौ ग्रंथों में से सिर्फ 13 ग्रंथ ही प्रकाशित हुए हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध की वजह से इन ग्रंथों का प्रकाशन नहीं हुआ। यह पत्र सन 1980 में यानी विश्व युद्ध खत्म होने के 35 साल बाद लिखा गया था। तब सोवियत संघ का प्रकाशन विभाग इन ग्रंथों के प्रकाशन के लिये सक्षम था। इससे यह साबित होता है कि सोवियत संघ ने मात्र 13 ग्रंथों को ही प्रकाशित करना मुनासिब समझा क्योंकि बाकी ग्रंथों में मार्क्स के विचार विरोधाभासी, अनुपयुक्त तथा शायद कई माईनों में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले थे।

मार्क्स शैतान-उपासक था !

मार्क्स शैतान में विश्वास रखता था इसलिये ईश्वर से नफरत करता था। मार्क्स ने अपनी कविता "Der Spiel-mann" में खुद का शैतान के साथ समझौता होने की बात कही है :-

That art God neither wants nor wists,
It leaps to the brain from Hell's black mists.
Till heart's bewitched, till senses reel:
With Satan I have struck my deal.

मार्क्स ने अपनी अन्य कविता में लोगों को बहलाकर नर्क में शैतान के पास ले जाने का वादा किया है। यह शब्द शैतान-उपासक जॅकोब फ्रंक द्वारा लिखे शब्दों को प्रतिध्वनित करते है। मार्क्स के पिता फ्रंकिजम के संपर्क में थे तथा उन्होंने ही शायद अपने बच्चों को इस में दीक्षित किया था। (Under the sign of Scorpion by Juri Lina) मार्क्स Joana Southcott द्वारा संचालित शैतानवादी चर्च में शामिल हुआ था। मार्क्स के आरंभिक लेखों में "Oulanem" का उल्लेख है जो शैतानी उपासना की पूजा-विधि के वक्त उपयोग में लाया जाने वाला शैतान का नाम है। ([http://antnewworldorder.blogspot.in/Silence is Betrayal Who was Karl Marx.html](http://antnewworldorder.blogspot.in/Silence%20is%20Betrayal%20Who%20was%20Karl%20Marx.html)) मार्क्स के बेटे एडगर (Edgar) ने अपने पिता मार्क्स को अपने पत्र की शुरुआत "मेरे प्यारे शैतान" (My dear devil) कहकर की है। यह पत्र 31 मार्च 1854 को लिखा गया था।

जेनी ने मार्क्स को अगस्त 1844 में लिखे अपने पत्र में लिखा : Your last pastoral letter, high priest and bishop of souls, has again given quiet rest and peace to your poor sheep. मार्क्स ने धर्म को नकारा है तब मार्क्स की बिवी मार्क्स को किस धर्म का उच्च पूजारी तथा बिशप कहती है ? यकीनन वह शैतान उपासक धर्म की बात करती है।

मार्क्स की मौत की खबर सुनकर मार्क्स का शिष्य अमेरिकन कमांडर Sergius Riis मार्क्स के लंदन स्थित घर पहुंचा। वहां हेलन डीमुथ ने बताया कि बीमार मार्क्स अकेला जलती मोमबत्तियों की कतार के सामने बैठकर प्रार्थनाएं करता था। उसके माथे पर पट्टी लपेटी होती थी। यहूदी जलती मोमबत्तियों के आगे प्रार्थनाएं नहीं करते। तब क्या यह कोई तांत्रिक विधि थी ? मार्क्स के अभ्यासकक्ष में झेउस (Zeus) की मूर्ति थी। ग्रीक कथाओं में झेउस ईश्वर विरोधी तथा क्रूर था। उसने पशु का रूप लेकर सारे यूरोप को बंदी बनाया था।

अध्याय 4

मार्क्सवाद धोखा-छलावा है !

संक्षेप में मार्क्स का सिधान्त !

1. इतिहास का आर्थिक दृष्टीकोण से स्पष्टीकरण : मानव इतिहास का निर्धारण आर्थिक घटकों से हुआ है, जो उत्पादन के साधन तथा उसके वितरण को नियंत्रित करते है। मार्क्स का सामाजिक विकास :-आदिम साम्यवाद > गुलामी > सामंतवाद > पूंजीवाद > समाजवाद > साम्यवाद.

2. वर्ग-संघर्ष (The class struggle) : शोषक तथा शोषित वर्ग के बीच सतत संघर्ष।

3. अतिरिक्त मुल्य का सिधान्त : मुनाफा श्रम से निर्मित है। यही अतिरिक्त मुल्य है, जिसका बहुत नगन्य हिस्सा मजदूरों को मिलता है।

4. समाजवाद की अनिवार्यता : पूंजीवाद के विकास में उसके विध्वंस के बीज छुपे हैं। जैसे की अतिउत्पादन, बेरोजगारी इ.। इसलिये पूंजीवाद के बाद समाजवाद का आना लाजमी है।

5. सशस्त्र क्रांति : जब मजदूरों तथा पूंजीपतियों के बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ जाती है तो मजदूर वर्ग सशस्त्र बगावत कर देता है और मजदूर वर्ग की तानाशाही को कायम करता है। (अपने राजनीतिक जीवन के आखरी हिस्से में मार्क्स ने इंग्लंड जैसे पूंजीवाद में परिपक्व हो चुके देशों में संसदीय तरिकों से शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद कायम होने की वकालत की।)।

6. अंतर्राष्ट्रियतावाद (Internationalism) : दुनियां के मजदूरों एक हो।

7. मजदूरों का वेतन :- सभी को उसकी क्षमता के मूतबिक (समाजवाद) से सभी को उनकी जरूरतों के मुताबिक (साम्यवाद) वाली व्यवस्था में रुपांतरण होगा।

आदीम साम्यवाद !

उत्तरी अमेरिका की Iroquois राष्ट्रीयता के साम्यवादी स्वरुप का Lewis Henry Morgan ने वर्णन किया है। मार्क्स-एंगेल्स ने मॉर्गन से प्रेरणा लेते हुए कहा कि hunter-gatherer परंपरागतत रूप से आदिम साम्यवाद का पालन करते थे जिसमें उत्पादन के साधनों पर सभी का हक होता था तथा सभी को अपनी जरूरतों के मुताबिक खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। समाज के सदस्यों के बीच समानता के संबंध थे। मार्क्स के आदिम साम्यवाद को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिये और न ही उनका आदर्शीकरण करना चाहिये। इन टोलियों में पुरुषों का स्तर उंचा होता था तथा वे औरतों पर नियंत्रण रखते थे। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों में ही महत्व के मुताबिक श्रेणियाँ होती थी। कुछ मजबूत, आकर्षक अल्फा पुरुषों के अथवा आकर्षक स्त्रियों के लिये स्वाभाविक रूप से ज्यादा महिलाएं/ पुरुष उपलब्ध थे। इन टोलियों में निजी संपत्ति थी जैसे कि उनके कपडे, औजार, गहने, घरेलू वस्तुएं इ. जो किसी ने खुद तैयार किये है या ये चिजें भेंट में या सामान की अदला बदली में मिली है। वहीं वस्तुएं सामुहिक मिल्कियत की थी जिसे सभी ने अपने श्रम से तैयार किया है। अपने स्तर तथा वर्चस्व को लेकर भी उनके बीच संघर्ष होते थे।

जो आदिम टोलियाँ समानता के सिधान्तों का पालन करती थी उसकी मुख्य वजह आर्थिक घटक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक घटक थे :- Peter Gray Ph.D के मुताबिक बच्चों सहित लोग 20 से 50 लोगों के छोटे समूहों में रहते थे। इन समूहों का कोई मुखिया नहीं होता था। सारे निर्णय आपस में सलाह मशवरा कर लिये जाते थे।

1. ये आदिम टोलियाँ "विरुद्ध-वर्चस्व" (reverse dominance) सिधान्त का पालन करती थी। अगर कोई व्यक्ति दूसरों पर हावी होने की जरा सी भी कोशिश

करता या अन्यो के प्रति जरूरी आदर जताने में कोताही बरतता तो समुह के वरिष्ठ सदस्य उसका मजाक बनाते थे। इससे भी अगर उसके व्यवहार में सुधार नहीं होता तो समुह के सदस्य यह मानकर चलते थे कि जैसे समुह में उसका अस्तित्व है ही नहीं। इस से वह व्यक्ति सुधर जाता था क्योंकि कोई भी बिना समुह के अकेले नहीं रह सकता। या फिर उसे उस टोली को छोड़कर जाना पड़ता।

2. समानता के सिद्धान्त का विकास होने की वजह खेलकूद भरे माहौल में बच्चों की परवरीश थी। मसलन अलग आकार के दो बंदर जब आपस में खेलते हैं तो बड़े आकार का बंदर खुद को जानबूझकर कमजोर कर लेता है तथा ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे छोटे आकार का बंदर डर जाये या निराश हो जाये। क्योंकि ऐसा होते ही खेल वहीं रुक जाता है और जोर आजमाईश (लडाई) बन जाता है। वर्चस्ववृत्ति का दमन करके ही खेदकूद की भावना का विकास होता है इसलिये उनकी हर सामाजिक आंतर्क्रियाओं में खेलकूद का भाव होता था।

3. इन टोलियों में समानता, परस्पर विश्वास, परस्पर स्निग्धता इ. की भावना का विकास बच्चों के पालन पोषण के तरिकों में दिखाई देता था। वे बच्चों की मूल प्रवृत्तियों (instincts) का आदर करते थे। वे बच्चे को उसके खुद के खेल और खोज के माध्यम से सीखने का मौका देते थे। इसलिये वे न ही बच्चों को कोई शारीरिक सजा देते थे और शायद ही कभी उसकी आलोचना करते थे। इसलिये बच्चे शायद ही कभी रोते थे क्योंकि रोने या चीढ़ने की कोई वजह ही नहीं होती थी। कभी किसी बच्चे पर चिल्लाकर नहीं बोला जाता था। बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक खेलने की पूरी आजादी थी। बच्चों को निरुत्साहित नहीं किया जाता था। जब वे यौवनावस्था पर आ जाते तब ही उन्हें प्यार से समझाया जाता था। इसलिये जैसा बर्ताव इन बच्चों के साथ अबतक होता रहा ये बच्चे भी वैसा ही व्यवहार दूसरों से करने की प्रवृत्ति को खुद में विकसित कर लेते थे। ([https://www.psychologytoday.com/How Hunter-Gatherers Maintained Their Egalitarian Ways _ Psychology Today](https://www.psychologytoday.com/How-Hunter-Gatherers-Maintained-Their-Egalitarian-Ways)) मनोवैज्ञानिक सामाजिक-सांस्कृतिक परवरीश का कितना महत्व है यह इस बात से ही समझा जा सकता है कि अकाल इ. से आई भूखमरी के हालातों में कुछ ही लोग मानवमांस-भक्षण करते हैं जबकि बहुसंख्य लोग भूख से मरना पसंद करते हैं।

राज्य

राज्य का उगम :- मार्क्स-एंगेल्स के मुताबिक आदिम समाज में राज्य का उगम समाज के सामुहिक हितों की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने के मकसद से तथा बाद में सत्ताधारी वर्ग के राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर की रक्षा करने हेतु हुआ है। मार्क्स-एंगेल्स की यह बात गलत है। आदिम राज्य लडाकू लोगों की टोली मात्र था जिसका अपना मुखिया होता था। वह एक सैनिकीय संस्था रही है जिसका मकसद जीतना तथा लूटना रहा है। जब यह टोलियां जमींदारों के रूप बसने लगी तब राज्य विभिन्न रूपों में आकार लेने लगा और जमींदार, राजा इ. के मरने के बाद भी राज्य

का अस्तित्व एक संस्था के रूप में कायम रहा।

लैटिन अमेरिका में स्पॅनिश तथा पुतुर्गिज आक्रमणकारियों (conquistadors) ने वहां के मूलनिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया, नागरी आबादी को लूट लिया और ताकत के बल पर वहां सामंतवादी व्यवस्था कायम की। इस परिवर्तन में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन इ. का कोई योगदान नहीं था। अपने सैनिकों तथा अफसरों को जमीन देने के लिये उन्होंने जीते हुए क्षेत्र की सामाजिक संरचना तक बदल दी। टर्कीश सर्बीया में इकलौता वर्ग सिर्फ अफसरशाही था जो सरकार पर नियंत्रण करता था। इस राज्य संस्था का इकलौता मकसद नौकरशाही के ऐशोआराम के लिये सर्बीया के लोगों का दमन शोषण करना था। न सिर्फ स्पेन तथा फ्रांस बल्कि फ्लान्डर्स (बेल्जियम), जर्मनी, रूस तथा दिगर उत्तरी युरोपियन देशों तथा इटली में राज्य संस्था के उगम का कारण सैन्य तथा राजनेता थे न कि उत्पादन के साधनों में होने वाला परिवर्तन।

राज्य के कार्य :- कम्प्युनिस्ट मॅनीफेस्टो के मुताबिक आधुनिक राज्य की कार्यसंस्था (executive) मात्र एक कमिटी होती है जो बुर्जुआ वर्ग के सामान्य कामकाजों का व्यवस्थापन करती है।

मार्क्स की उपरोक्त बात गलत है। राज्य संस्था खुद एक वर्ग है। राज्यसंस्था सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक असमानता की निर्माणकर्ता भी है। राज्यसंस्था का मतलब वर्चस्व है और सभी प्रकार का वर्चस्व जनता पर पूरा नियंत्रण चाहता है ताकि चंद शोषक जनता का शोषण कर सके। यह सामाजिक असमानता को राजनीतिक दमन से कायम रखती है। राज्य संस्था एक परजीवी संस्था है जो लोगों के शोषण पर जीवित रहती है। सेना की ताकत के बिना राज्य संस्था खुद को लोगों के गुस्से से सुरक्षित नहीं रख सकती। राज्यसंस्था तानाशाही की ओर कितना बढ़ेगी यह लोगों के चरित्र, संस्कृति तथा राजनीतिक हालातों पर निर्भर करता है।

उदावादी लोकतांत्रिक राज्य :- उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य ओढा गया लबादा मात्र है। उदाहरण के लिये भारत के शोषक वर्ग ने इस सबब पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कि गरीबों को स्वरोजगार के लिये आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन उनका असली मकसद बैंकों की पूंजी को अपनी पसंद के उद्योगपति इ. को देना था। सरकार उनका कर्ज माफ करती है और बैंक के घाटे की भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी। कईयों को विदेश भागने में मदद दी जाती है। जबकि गरीब किसानों, मजदूरों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को बैंक की किरतें न चुकाने पर बैंक उनकी संपत्ति को निलाम करती है। किसानों की फसल उजाड़ी जाती रही है, उन्हें आत्महत्या लिये मजबूर किया जाता रहा है। चुनाव हारने के डर से किसानों का माफ किया जाने वाला कर्ज उद्योगपतियों के माफ किये गए कर्जों की तुलना में उंट के मुंह में जीरे जैसा होता है। कल्याणकारी राज्य का ढोंग इस पर निर्भर है कि सरकार कितनी कमजोर और जनता कितनी जागरुक तथा संघर्षशील है। जब जनता पर सरकारों का पूरा नियंत्रण होता है, वह जनता का निर्मम शोषण करती है।

अपने कदमों को कानूनी तथा नैतिक औचित्य (legitimacy) प्रदान करने के

लिये राजनेताओं द्वारा जनमत संग्रह किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में अक्सर ही जनमत संग्रह किया जाता है। इसके बावजूद वह यूरोप का सबसे बड़ा संकीर्णतावादी राष्ट्र है। जनमत संग्रह में राजनेता बहस के नियम खुद तय कर लोगों को उस दिशा में निर्देशित करते हैं। इसलिये जनमत संग्रह के बावजूद जनता शोषकों के चंगुल में दबी रहती है। कानून जटील, अमूर्त तथा विशेषताएं लिये हुए होते हैं। सही निर्णय के लिये खुद को शिक्षित करने के लिये जो साहित्य, समय, चर्चा इ. की सुविधाएं मिलनी चाहिये वे सब उन्हें हासिल नहीं होती। इसलिये आम लोग उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते।

क्या मार्क्सवादी राज्य इससे भिन्न है :- कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो सिर्फ औद्योगिक मजदूरों को ही क्रांतिकारी वर्ग मानता है। यह नये किस्म का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग (aristocracy) है। लाखों-करोड़ों की तादाद वाला सर्वहारा वर्ग मार्क्सवादी राज्य में खुद को इस विशेषाधिकार प्राप्त मजदूरों के अधिन जाएगा। मार्क्स के मुताबिक जनता का व्यवस्थापन अनिवार्य रूप से लोगों द्वारा चुने जाने वाले चंद लोगों का होगा। यानी प्रत्यक्ष सत्ता का अधिकार इन औद्योगिक मजदूरों के हाथों से छीनकर उसे कम्युनिस्ट पार्टी के नौकरशाहों के हाथों में यह कहते हुए सौंप दिया जायेगा कि वे मजदूरों के अग्रणी दस्ते हैं। लेनिन, ट्राट्स्की इ. सभी कम्युनिस्ट नेता अर्धबुर्जआ थे। उनमें से कोई भी मजदूर नहीं था। अगर कुछ मजदूर, नेता बन भी जाये तब वे सत्ता पर काबिज होते ही मजदूर नहीं बल्कि शासकों की श्रेणी में आ जाएंगे। तब वे शासकों की नजर से देखेंगे। तब वे मजदूरों का नहीं बल्कि खुद का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही मानव स्वभाव है। इसलिये मार्क्स का राज्य मजदूरों की नहीं बल्कि कम्युनिस्ट नौकरशाहों की तानाशाही है।

मार्क्स बहुत ज्यादा केन्द्रित तथा ताकतवर राज्य की हिमायत करता है। मार्क्स का कथित राज्य इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वह लोगों पर राजनीतिक सत्ता कायम करे बल्कि वह चाहता है कि राज्य की सारी संपत्ति, खेती, सारे निर्माण कार्य, सारे उद्योग, सारा व्यापार सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों में केन्द्रित रहे और वही राज्य का इकलौता बैंकर रहे। मालिक, संगठक, दिशानिदेशक, आर्थिक सहायता करने वाला (financier), श्रम तथा अर्थतंत्र को वितरित करने के अधिकार से संपन्न केन्द्रिकृत सरकार का मतलब निरंकुश रूप से काम करने वाली संस्था है। मार्क्सवादी क्रांति निजी चल-अचल संपत्ति को समाप्त नहीं करती बल्कि सिर्फ उसको पार्टी नौकरशाहों के हाथों में स्थानांतरित करती है। तब पार्टी के नौकरशाह देश की चल-अचल संपत्ति को मनमाने तरीके से लूटने के लिये आजाद होते हैं।

यह नये हुक्मरानों के तहत सैनिक तानाशाही है जो खेतिहर मजदूरों को सेना जैसे अनुशासन से नियंत्रित करेंगे। मार्क्स के मुताबिक मजदूरों की युनियन नहीं होगी क्योंकि मजदूरों के हित व्यवस्थापन के हितों से अलग नहीं होंगे। यानी मजदूरों को क्या चाहिये और क्या नहीं चाहिये यह सब कुछ तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नौकरशाहों को होगा। कथित समाजवादी पोलंड के मजदूर फॅक्टरी की नौकरशाही के तहत खुद को लूटा हुआ महसूस करते थे। इसलिये उन्होंने औद्योगिक हड़तालें की। कथित समाजवादी देशों में नौकरशाहों की आमदानी तथा मजदूरों की

आमदानी में बहुत बड़ी खाई है। इसलिये अगर राज्य का अस्तित्व है तो यकीनन वहां सर्वोच्चता भी होगी इसलिये वहां गुलामी भी होगी। बिना लोगों की स्वतंत्रता के आर्थिक समानता और न्याय हासिल होना मात्र एक भ्रम है। स्वतंत्रता के बिना समानता एक खतरनाक विरोधाभासी कल्पना है, बिना स्वतंत्रता के समाजवाद खतरनाक किस्म की तानाशाही है। इसलिये कुछ अर्से के कथित इन्केलाबी उन्माद के बाद जनता खुद को गुलामों तथा शाषितों-पीडितों के रूप में पाएंगी।

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मतलब राष्ट्रवाद को नकारना यानी अंततः राज्य को नकारना है। इसलिये मार्क्स तथा उसके साथियों ने कम्युनिस्ट मनिफेस्टों में राज्य के नियम को शामिल कर तार्किक रूप से इंटरनेशनल को खत्म कर दिया है। वे इस विरोधाभास को जानते-समझते हैं इसलिये यह दलील देते हैं कि राज्य की यह तानाशाही तत्कालीन और अस्थायी है। राज्य का मकसद लोगों को शिक्षित करना, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टी से उस अवस्था तक उंचा उठाना है ताकि राज्य व्यवस्थापन की जरूरत ही ना रहे। तब राज्य व्यवस्था अपने आप खत्म होगी।

कम्युनिस्ट राज्य अगर सचमूच में लोगों की सरकार है तो उसने खुद को खत्म क्यों कर लेना चाहिये ? और अगर लोगों के हित में उसका खत्म होना जरूरी है तो फिर किस तरह वे उसे लोगों की सरकार कह सकते हैं ? वह लोगों के कंधों पर लगाया गया जूआ (yoke) मात्र है क्योंकि वह एक ओर तानाशाही को तो दूसरी ओर गुलामी को जन्म देता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि यह सरकारी जुआ, यह सरकारी तानाशाही लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिये जरूरी कदम है। इसलिये जनता को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिये उन्हें सबसे पहले गुलाम बनाया जाना जरूरी है। यह मक्कारी भरी दलील है। तानाशाही का मकसद खुद को कायम रखना होता है, खुद को खत्म करना नहीं। इसलिये मार्क्सवादी राज्य बेहद राजतंत्रीय, तानाशाह तथा घमंडी होगा। यह राज्य मजदूरों तथा सर्वहारा वर्ग के लिये सेना की छावनियों (barracks) जैसा होगा जहा तयशुदा वक्त पर लोग जागते, काम करते और सोते हैं।

मार्क्स के मुताबिक समाजवाद की अवस्था में हर किसी को उसके श्रम के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। यह कौन तय करेगा कि लोगों के श्रम का मुल्य कितना है ? साम्यवाद की अवस्था हर किसी को उसकी जरूरत के मुताबिक परिश्रमिक मिलेगा। यह कौन तय करेगा कि लोगों की जरूरतें क्या हैं ? इन बातों का जबाब देने से बचने के लिये मार्क्स ने राज्यसंस्था अपने आप नष्ट होगी (withering away of the state) जैसी बेतुकी दलिलें दी।

मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद !

कम्युनिस्ट मनिफेस्टों के मुताबिक संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। उपरोक्त कथन गलत है :- ईसाइयों तथा मुस्लिमों के बीच हुए धर्मयुद्धों में; या लैटिन अमेरिका को स्पेन द्वारा जितने में; सीसीली के कब्जे में तथा इटली, फ्लॉडर्स, फ्रांस के एक हिस्से तथा स्पॅनिश सेना इ. में वर्गयुद्ध की भूमिका न के बराबर थी। इस युद्ध

में स्पेन की जनता ने राजाओं का साथ दिया था। दसवीं से लेकर सोलहवीं शताब्दी के दौरान हुई इन लड़ाईयों में धार्मिक तथा वांशिक कारण सबसे ज्यादा प्रबल रहे हैं। (La Falacia del Marxismo, pp 121-2) मार्क्स अपने सिद्धान्त को अंतिम सत्य मानकर चलता है कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक घटकों से ही इतिहास में परिवर्तन होता है तथा होने वाला परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है।

जबकि कई आर्थिक घटनाएं एकदूसरे को प्रभावित करती हैं इसलिये एक दूसरे का कारण होती हैं। जैसे लोगों की कलात्मक रुची में परिवर्तन, राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन, सामाजिक प्रथा-परंपराओं में परिवर्तन, यहां तक कि धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन होने से किसी वस्तु का उपयोग तथा फलस्वरूप उसका उत्पादन प्रभावित होता है। मानव इतिहास में कारण तथा परिणाम न सिर्फ एकदूसरे को प्रभावित करते हैं बल्कि वे एक दूसरे का कारण या परिणाम भी बन जाते हैं। इतिहास के कोई नियम ही नहीं है। (A Critique of Marxism by Sam Dolgoff) सोवियत युनियन का अस्तित्व मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त को नकारता है क्योंकि वहां पूंजीवाद का चरम सीमा पर विकास ही नहीं हुआ था और न ही वहां मजदूर वर्ग बड़ी तादाद में था। यही बात चीन पर लागू होती है। मार्क्स इस बात को नहीं समझ सका कि उत्पादन के भौतिक साधन जैसे कि औजार, मशीनें इ. भी वस्तुतः मानवी दिमाग की उपज हैं। हमारी कल्पनाएं ही हमें जानवरों से अलग करती हैं। हकीकत यह है कि कल्पनाओं ने इतिहास को आकार दिया है।

मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा आर्थिक विकास की अवस्थाओं का इकलौता मकसद इस हकीकत को छुपाना था कि इल्युमिनेंटी यहूदी बैंकिंग समुह बहुतांश देशों के संसाधनों को नियंत्रित करती है तथा वे ही अबतक हुए अधिकांश युद्धों के लिये जिम्मेदार हैं। वे ही देशों को गुलाम बनाकर लोगों के हर तरह के दमन और शोषण का कारण बनते रहे हैं।

ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धान्त प्रतिक्रांतिकारी है !

कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो के मुताबिक बुर्जुआ वर्ग बड़े पैमाने पर उद्योग लगाता है; यह मजदूरों के खुद के हितों में है कि वे पूंजीपतियों को सत्ता हासिल करने में मदद करें तथा जब पूंजीवाद का चरम सीमा पर विकास हो जाएगा तभी सशस्त्र क्रांति के जरिये पूंजीपतियों को उखाड़ फेंके। यानी तब तक मजदूरों ने पूंजीवादी शोषण को अपनी वैज्ञानिक नियति मान कर चुपचाप सहन करना चाहिये। इसतरह मार्क्स का आर्थिक निर्धारण (Economic Determinism) सिद्धान्त लोगों की क्रांतिकारी उर्जा को खत्म कर देता है। मजदूरों को पूंजीवाद को कबूल करने तथा शासकों के गुलाम बनने के लिये अभिसंधित (condition) करता है। मार्क्स ने The Neue Rheinische Zeitung (Feb. 14 1849, -edited by Marx) में घोषित किया कि "स्लाव लोगों का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि इसका आसान कारण यह है कि वहां आजादी के लिये आवश्यक राजनीतिक तथा औद्योगिक हालात नहीं हैं। ... हेकड चेक तथा स्लोवाक लोगों ने जर्मन पूंजीपतियों का शुकुगुजार होना चाहिये कि उन्होंने व्यापार, उद्योग, कृषि विज्ञान

तथा शिक्षा लाकर उन्हें सुसंस्कृत बनाने का कष्ट किया टेक्सास तथा कॅलिफोर्निया को क्या हासिल हुआ होता अगर वे आलसी मेक्सिकन लोगों के हाथों में होते ?” उपरोक्त उध्दहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो क्रांतिकारी गुलामी तथा वांशिक दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जो पूंजीपतियों से सहयोग करने से इन्कार करते हैं, जो युध्द तथा सैन्यवाद के खिलाफ हैं, जो साम्राज्यवादी चंगुल से अपने देश को छुड़ाने में संघर्षरत हैं मार्क्स के मुताबिक वे व्दंदात्मकता के अनुसार प्रतिक्रांतिकारी हैं क्योंकि वे अपने शोषकों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं जो उनके लिये अप्रत्यक्ष रूप से समाजवाद का रास्ता साफ कर रहे हैं।

एंगेल्स के मुताबिक ग्रीस में गुलामी प्रथा को अपनाया जाना एक प्रगतिशील कदम था। वह गुलामी प्रथा ही थी जिसकी वजह से कृषि तथा उद्योगों का विकास संभव हो पाया तथा उसी की बदौलत हेलेनिजम जो पूरातल काल का फूल है विकसित हो सका। गुलामी के बिना न ही ग्रीक राज्य होता, न ही कला तथा विज्ञान होता; बिना गुलामी प्रथा के कोई रोमन साम्राज्य नहीं होता; बिना हेलेनिजम तथा रोमन साम्राज्य के कोई यूरोप नहीं होता। ... बिना पूरातन गुलामी संस्था के आधुनिक समाजवाद नहीं होगा (Anti-Duliring , p. 203) मार्क्स के मुताबिक अमेरिका में गुलामी का होना एक जरूरत है। दिगर चीजों की तरह गुलामी यह आर्थिक श्रेणी है। गुलामी यह उद्योगों के लिये उतनी ही जरूरी है जितनी कि मशीने तथा पूंजी ... बिना गुलामी प्रथा के आपके पास कोई कपास नहीं होगा, बिना कपास के कोई आधुनिक उद्योग नहीं होंगे ... गुलामी संस्था के बिना उत्तरी अमेरिका जो सभी देशों में प्रगतिशील है एक आदिम मुल्क में तब्दिल हो जाएगा। आप गुलामी संस्था को खत्म कर दे और आपने राज्यों के नक्शे से अमेरिका को मिटा दिया है। उपरोक्त दलीलें पढने के बाद यह सवाल पैदा होता है कि वह देश कितना प्रगतिशील है जिसका खुद का अस्तित्व ही गुलामी संस्था पर टिका है ? आर्थिक नियतिवाद (economic determinism) के मुताबिक मार्क्सवादी कहेंगे कि “क्योंकि युध्द व्दारा युध्दबंदियों को गुलाम बनाये जाने से मजदूरों की कमी पूरी होती है इसलिये युध्द आवश्यक तथा फायदेमंद है।

परिवार !

एंगेल्स के मुताबिक परिवार में पति की हैसियत एक बर्जुआ शोषक की तथा विबी-बच्चों की हैसियत सर्वहारा शोषित की होती है। औरतों की मुक्ति तभी मुमकिन है जब औरतें औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा लें तथा घरेलू कामकाज से उन्हें मुक्ति मिले। इसके लिये परिवार-संस्था को नष्ट करना जरूरी है। (p.39, Origin of the Family, Private Property, and the State by Friedrich Engels) एंगेल्स के उपरोक्त कथन का असली मकसद पूंजीपतियों के लिये सस्ते मजदूर पैदा करना था। उद्योगों में अधिकतर पुरुष काम करते थे। औरतें भारी तादाद में उद्योगों में काम करेगी तो पूंजीपतियों को बेहद सस्ते मजदूर उपलब्ध होंगे। इसी वजह से मार्क्स-एंगेल्स ने औरतों की मुक्ति का ढोंग रचाया था। मार्क्स और एंगेल्स यह समझा रहे थे कि औरतों की मुक्ति के लिये उन्हें पहले औद्योगिक गुलाम बनना जरूरी है। औद्योगिक गुलाम बनने के बाद

भी उनकी फौरन मुक्ति नहीं होगी बल्कि औरतों को अपनी मुक्ति के लिये साम्यवादी व्यवस्था कायम होने का इन्तेजार करना पड़ेगा जब सारे घरेलू कामों को सामाजिक उद्योग में बदल दिया जाएगा। तबतक औरतों को घरेलू कामों के अलावा उद्योगों में गुलामों की तरह काम करना होगा।

क्योंकि धर्म और समाज परिवार संस्था को एक पवित्र संस्था मानता है इसलिये औरतें आसानी से तबतक उद्योगों में गुलाम बनना मंजूर नहीं कर सकती जबतक खुद परिवार संस्था ही ध्वस्त ना हो जाये। इसलिये मार्क्स एंगेल्स ने एकनिष्ठ विवाह संबंधों को अवैज्ञानिक तथा दमनकारी करार दिया। परिवार संस्था को नष्ट करने के लिये स्त्रियों के तथा समलैंगिकों के आन्दोलनों का निर्माण किया गया। चाहे औरत औरत से विवाह करे या आदमी आदमी से दोनों ही अवस्थाओं में परिवार संस्था नष्ट होती है (क्योंकि इन विवाहों से बच्चे पैदा नहीं हो सकते) और उद्योगों को भारी तादाद में स्त्री-पुरुष गुलाम मजदूरों के रूप में उपलब्ध होते हैं।

एंगेल्स के मुताबिक स्त्री-पुरुष के बीच सच्चे प्रेम संबंध सिर्फ मुक्त अनैतिक संबंधों में ही मुमकिन होते हैं। (Origin of the Family, Private Property, and the State by Friedrich Engels) इसतरह मुक्त यौन संबंधों के जरिये मार्क्स तथा एंगेल्स परिवार-संस्था को नष्ट कर पूंजीपतियों के उद्योगों के लिये मजदूर जुटाना चाहते थे। परिवार संस्था के विध्वंस की वकालत मार्क्स का एक ढोंग-पाखंड मात्र था क्योंकि उसने अपने खुद के परिवार को भंग नहीं किया था।

मार्क्स एंगेल्स के मुताबिक क्योंकि बाप एक बुर्जुआ शोषक की तरह होता है बच्चों की सही परवरीश मां-बाप से अलग समाज द्वारा चलाये जाने वाले कम्युन में ही हो सकती है। मार्क्स ने अपने बच्चों को अपने निर्णय तक लेने की कभी आजादी नहीं दी। मार्क्स ने अपनी बेटी के जीवन में हर बार दखलंदाजी की। जब Paul Lafargue मार्क्स की बेटी Laura से विवाह करना चाहता था तो मार्क्स ने उसे अपनी बेटी से दूर रहने की धमकी दी और कहा कि सबसे पहले वह यह साबित करें कि वह अपनी भावी पत्नि को सभी सुविधाएं दे सकता है। मार्क्स ने अपनी बेटी Eleanor के Prosper Lissagaray के साथ के प्रेम संबंधों को नकार दिया। अपनी बेटी की मिन्नतों के बावजूद मार्क्स ने उनकी हो चुकी सगाई को मानने से भी इन्कार कर दिया।

मार्क्स अपनी बिबी-बेटियों को मुक्त यौन संबंधों की आजादी कतई नहीं देना चाहता था। मुक्त यौन संबंधों की हिमायत मात्र औरतों के लिये थी। मार्क्स-एंगेल्स ने कभी मुक्त यौन-संबंधों वाले कम्युनिस्ट स्थापित नहीं किये जहां सारे परिवारों के स्त्री-पुरुष मुक्त यौन संबंध निभाते हैं। हमारी जानकारी में किसी भी देश की किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्क्स के समय से लेकर अब तक कभी भी ऐसे कम्युनिस्टों को कायम नहीं किया है। यह है उनकी कथनी और करनी का ढोंग।

वर्ग तथा वर्ग चरित्र !

मार्क्स ने अपने किसी भी ग्रंथ में वर्ग की संकल्पना को स्पष्ट नहीं किया। अगर

मजदूर वर्ग अपने वर्ग के हितों के अनुसार (वर्ग चरित्र के मुताबिक) सोचता है तो उनके बीच गहरे मतभेदों क्यों होते हैं ? मजदूरों के राजनीतिक विचार तथा दृष्टिकोण तय करने में वर्ग की बजाय रंग, वंश तथा जाति की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसी वजह से मजदूरों का एक तबका पूंजीपतियों के साथ मिलकर मजदूरों के दूसरे समुदाय के विरोध में उठ खड़ा होता है।

हर तरह के शोषण की जड़ में इन्सान का आलस, लालच, ईर्ष्या तथा नफरत होती है। यह सारी प्रवृत्तियाँ समाज के हर वर्ग में पायी जाती हैं। हर समाज में स्वार्थी, आलसी, लालची, ईर्षालू और नफरत से भरपूर लोग होते हैं और मौका मिलते ही किसी का भी शोषण करने से नहीं चूकते।

अतिरिक्त मुल्य का सिद्धान्त !

इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि पूंजीपतियों को मिलने वाले लाभ का न्यायपूर्ण ढंग से बँटवारा होना चाहिये। अगर सारा मुनाफा सिर्फ मजदूरों के श्रम से पैदा हुआ है तब मजदूरों को यह नैतिक अधिकार है कि वह सारा मुनाफा खुद रख ले। दूसरे लोग जैसे कि तकनीशियन, निरिक्षक, मॅनेजर तथा खुद पूंजीपति इ. को मुनाफे में कोई हिस्सा ही ना दिया जाये। क्या ऐसा करना तर्कसंगत लगता है ? मार्क्सवादी यह दलील देते हैं कि मशीन के सामने अगर कच्चा माल रख दिया जाये तो क्या पक्की वस्तुएं बन जाएगी ? इसलिये सारे मुनाफे पर मजदूरों का हक है। इसी तर्क के मुताबिक अगर यह कहा जाये कि बिना, मशिनरी, बिना पूंजी के क्या मजदूर खुद पक्की वस्तुएं पैदा कर सकते हैं ? इसलिये पूंजी, तकनीकी कौशल्य, मशीनें, मॅनेजर, मजदूर इ. सभी के संयुक्त प्रयास से ही मुनाफा पैदा होता है। इसलिये मुनाफे में सभी का न्यायोचित हिस्सा है।

आज कई कंपनियों में सारा काम रोबोट की मदद से किया जाता है। इन्सानों की उसमें कोई भूमिका ही नहीं होती। जी.पी.एस. से सज्जीत बसे, टॅक्सियां इ. का चलन भी हो रहा है जो बिना किसी ड्रायवर तथा कंडक्टर के खुद चलती हैं, अपने आप लोगों को टिकट देती हैं, लोगों का गंतव्य स्थान आते ही रुक जाती हैं इ. तब आप इसका मुनाफा किसे देंगे ?

मार्क्स के मुताबिक वस्तु का मुल्य उसमें लगे श्रम की मात्रा के मुताबिक तय होता है। अगर आप हिरे, तथा कपास के उत्पादन में लगे श्रम का तथा हिरे व कपास की कीमत का तुलनात्मक विचार करे तो मार्क्स के सिद्धान्त की व्यर्थता अपने आप साबित हो जाती है। वस्तु का मुल्य कई घटकों पर निर्भर करता है जैसे वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की बाजार में उपलब्धता, उत्पाद फॅशन या तकनीक के हिसाब से पुराना तो नहीं हो गया है ? इ. घटक वस्तु के मुल्य का निर्धारण करते हैं।

मार्क्स के अतिरिक्त मुल्य के झूठे सिद्धान्त को इसलिये जोरशोर से प्रचारित किया गया ताकि सबसे बड़ा विलेन पूंजीपतियों को करार देकर असली विलेन जो इल्युमिनेंटी का यहूदी बैंकिंग समूह है को पूरी तरह से छूपाया जा सके। मार्क्सवाद को

प्रचारित-प्रसारित करने का असली मकसद ही यहूदी बैंकरों के असिमित दमन-शोषण को छुपाना तथा उन्हें उनके फायदे की निरंकुश कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था प्रदान करना था।

अंतर्राष्ट्रीयतावाद !

यहूदी बैंकर्स सारे मुल्कों को अपने आर्थिक हितों के मुताबिक नियंत्रित करना चाहते थे। "वैश्विक स्तर के नियम-कानून लागू करके ही" यह मुमकिन हो सकता है। इसलिये "वैश्विक सरकार" कायम करना जरूरी था। इसलिये उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद को प्रचारित किया। जबकि लोग अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा के लिये संघर्ष कर रहे थे। राष्ट्रीयता के नियम के मुताबिक हर भाषिक, जातीय, वांशिक समूह अपनी एक अलग राष्ट्रीयता रखता है। इसलिये उनका अपना अपना राज्य होना चाहिये। इसी राष्ट्रीयता की भावना से सारे यूरोप में संघर्ष चल रहे थे।

सन 1848 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टों में घोषित किया कि पूंजीवाद सारी राष्ट्रीय विशेषताओं को नष्ट करते हुए उन्हें समान आर्थिक प्रणाली में कर एकत्रित कर रहा है। मार्क्स पूरी तरह से गलत था क्योंकि सन 1848 में एक औसत आदमी को अफ्रीका तथा एशिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मार्क्स तथा एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टों में घोषित किया कि आधुनिक उद्योगों ने इंग्लंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इ. के मजदूरों के राष्ट्रीय चरित्र के हर पहलु को खत्म कर दिया है। मार्क्स गलत था क्योंकि मजदूर अपने राष्ट्रीय चरित्र तथा उसमें पाये जाने वाले नियम, कानून, धर्म तथा प्रवृत्तियों इ. का बड़ी शिद्दत से पालन करते थे।

सर्वहारा वर्ग और क्रांति !

मार्क्सवाद का औद्योगिक मजदूरों से ही वास्ता है क्योंकि उन्ही को हथियार बनाकर चयनात्मक तरीके से खास उद्योगों में अशांती पैदा कर उन्हें यहूदी बैंकरों के कर्ज में डूबोया जा सकता है।

मार्क्स के मुताबिक शहरी उद्योगों का संगठित मजदूर वर्ग ही समाज में मुख्य क्रांतिकारी तबका है। विकसित औद्योगिक देशों के मजदूरों को क्रांति करने में कोई रुची नहीं है क्योंकि अविकसित देशों में माल बेचकर हुए मुनाफे में से उन्हें बेहतर तनखाह हासिल होती है। जबकि मार्क्स ने जोर देकर इन्ही विकसित देशों में क्रांति होने की बात कही थी जो कभी नहीं हो सकी। मार्क्स के मुताबिक संगठित मजदूर वर्ग ही पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकेगा जब पूंजीवाद की चरम अवस्था में मजदूरों की गरीबी चरम सीमा पर पहुंचेगी। चरम शोषण और गरीबी क्रांति की गॅरन्टी नहीं है। चरम गरीबी में लोग हताश हो जाते हैं अगर उन्हें इससे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मार्क्स ने क्रांति के मनोवैज्ञानिक कारणों को बिल्कूल ही नकार दिया है। क्रांति उन लोगों के लिये बिल्कूल नामुमकिन है जिन्होंने स्वतंत्रता की आदत तथा चाह छोड़ दी है। सच्ची क्रांति लाने के लिये यह जरूरी है कि 1) शहरी, ग्रामीण, संगठित तथा

असंगठित सभी मेहनतकश शोषित दमित लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी होनी चाहिये। 2) इन लोगों में अपनी मौजूदा लाचार अवस्था को लेकर तीव्र नापसंदगी तथा नफरत का जजबा होना चाहिये। 3) उनमें यह पूरा विश्वास पैदा होना चाहिये कि वे अपने हालातों को अपने संयुक्त प्रयास से बदल सकते हैं। 4) किस प्रकार की समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं इसकी पूरी पूरी जागरुकता होनी चाहिये। 5) शोषित-दमित जनता का होने वाली क्रांति पर पूरा पूरा नियंत्रण होना चाहिये। उपरोक्त पांचों शर्तों को पूरा किये बगैर समतामूलक समाज कायम करने वाली क्रांति का होना नामुमकिन है। इन शर्तों के बिना एक शोषक के हाथ से दूसरे शोषक के हाथों में सत्ता परिवर्तन मात्र होगा। मार्क्स क्रांति की हिमायत सिर्फ इसलिये करता था ताकि पूंजिपतियों के हितों में मजदूर वर्ग सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंके और पूंजीवाद को मजबूत बनाये। जब सामंतवाद को मजदूरों की सहायता से नष्ट करने का पूंजीपतियों का मकसद पूरा हुआ तब मार्क्स ने दलील दी की पूंजीवाद की चरम अवस्था में शांतिपूर्ण तरिकों से यानी संसदीय तरिकों से पूंजीवाद का समाजवाद में रूपांतरण हो जाएगा। इसलिये मार्क्स ने क्रांति के सिद्धान्त को त्याग कर मजदूरों को संसदीय प्रणाली में हिस्सा लेने को कहा।

अध्याय 5

मार्क्स-एंगेल्स यहूदी बैंकर्स के एजेन्ट थे !

मार्क्स ने जासूस के रूप में कार्य किया !

मार्क्स की बिबी जेनी का भाई Ferdinand von Westphalen प्रुसिया की पुलिस का प्रमुख था। Ferdinand बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क का संचालन करता था। Wolfgang Waldner के मुताबिक आरंभिक अवस्था में मार्क्स प्रुसिया की सरकार के लिये जासूसी करता था।

पॉल जॉन्सन (Paul Johnson) के मुताबिक मार्क्स ने अपने राजनीतिक प्रतिव्दंदीयों तथा अपने शत्रुओं की इकट्टा की हुई जानकारी पुलिस को सौंप दी। (Under the sign of Scorpion by Juri Lina) जर्मनी के अखबार Reichsruf (January 9, 1960) ने प्रकाशित किया कि ऑस्टीयन चांसलर Julius Raab ने निकिता ख्रुश्चेव को मार्क्स का लिखा हुआ पत्र दिया। पत्र से स्पष्ट होता था कि मार्क्स आस्ट्रीया की पुलिस के लिये क्रांतिकारियों पर जासूसी करता था। जासूस के तौर पर मार्क्स ने अपने लंदन निष्काषण के दौरान बाकी क्रांतिकारियों की जानकारी दी थी। इसमें लंदन, पॅरिस तथा स्विट्झरलैंड के निष्काषित क्रांतिकारियों की जानकारी थी। इन में से एक का नाम Ruge था जो खुद को मार्क्स का बहुत करिबी दोस्त मानता था। यह पत्र संयोगवश गोपनीय रिकार्ड विभाग (archive) में मिला था। (Marx and Satan By Richard Wurmbrand)

Vogt ने 200 पेज की My Suit Against the 'Allgemeine Zeitung' नामक किताब लिखी। उनके अनुसार कार्ल मार्क्स पुलिस में खबर करने की धमकी देकर जर्मनी के मजदूर नेताओं से धन की मांग करता था। (p.123-24-RED JENNY A Life with Karl Marx, by H.F. Peters, St. Martin's Press New York, ISBN 0-312-00005-7) जेनी प्रुसिया से निष्काषित कम्युनिस्ट नेता मार्क्स की बीवी थी को प्रुसिया की सरकार ने खास हिज मॅजेस्टी के विशेष आदेश पर Trier के सफर के लिये पासपोर्ट जारी किया। अप्रैल 1856 में मार्क्स ने खत में एंगेल्स को लिखा कि मेरी बिबी को हीज मॅजेस्टी के विशेष आदेश पर पासपोर्ट जारी हुआ है। वह 3-4 माह के लिये पूरे परिवार के साथ Trier जा रही है। (p.113-14- RED JENNY A Life with Karl Marx, by H.F. Peters) मार्क्स प्रुसिया की सरकार का खास एजेन्ट था तभी तो उसकी बिबी को हीज मॅजेस्टी के खास आदेश पर पासपोर्ट हासिल हुआ था।

मार्क्स बैंकर्स का एजेन्ट था !

मार्क्स रोथ्सचिल्ड के लिये काम करता था। दास कॅपिटल में कतई उल्लेख नहीं है कि बैंकर्स मुद्रा छापकर उसे सरकार तथा बैंकों को कर्जों में मुद्रा देकर शुन्य से (out of thin air) धन की निर्मिति कर कर्जों के जरिये तमाम सरकारों को तथा पूंजीपतियों पर नियंत्रण रखते हैं। मार्क्स कैसे अनजान रह सकता है कि अमेरिका के अध्यक्षों सहित अनेक हस्तियों ने बैंकर्स को देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। अमेरिका के अध्यक्षों का बैंकर्स का विरोध करने की वजह से कत्ल किया गया था। मार्क्स ने अतिरिक्त मुल्य के झूठे सिधान्त से पूंजीपतियों को विलेन करार देकर असली विलेन बैंकर्स को छुपाने की कोशिश की है। सारे कम्युनिस्ट साहित्य में आपको कहीं भी रोथ्सचिल्ड अथवा यहूदी बैंकर्स के खिलाफ एक भी शब्द नहीं नजर आएगा।

बकुनिन के मुताबिक मार्क्स का एक पैर बैंकर्स के बीच तथा दूसरा पैर समाजवादी आन्दोलनों में था। बकुनीन ने पहले इंटरनेशनल में सन 1869 में खुलासा किया कि मार्क्स बैंकर रोथ्सचिल्ड का हितैषि है। मार्क्स का समाजवाद जो की एक तानाशाही है, राज्य का पूरी तरह से केन्द्रिकरण चाहता है। जब भी केन्द्रिकृत राज्य होगा वहां केन्द्रिकृत बैंक की जरूरत होगी। और वहां लोगों के श्रम का सौदा करने के लिये परजीवी यहूदी बैंकर्स भी होंगे।

रोथ्सचिल्ड से आर्थिक सहायता हासिल 'Bund der Gerechten' (League of the Just), जो बाद में 'Bund der Kommunisten' (League of the Communists) कहा गया ने मार्क्स को कम्युनिस्ट मेनिफेस्टों लिखने के लिये धन अदा किया था। ([https://www.henrymakow.com/Karl Marx Was Rothschilds' Third Cousin - henrymakow.com.html](https://www.henrymakow.com/Karl%20Marx%20Was%20Rothschilds%20Third%20Cousin%20-%20henrymakow.com.html))

रोथ्सचिल्ड तथा मार्क्स दोनों ही रुस से नफरत करते थे !

रुस पूरी तरह से आत्म निर्भर था। उसका क्षेत्र अतिविशाल था। जार ने रुस में

निजी केन्द्रिय बैंक कायम करने के बैंकर्स के प्रस्ताव को लगातार नामंजूर कर दिया था। जार ने अमेरिका के गृहयुद्ध में अब्राहम लिंकन को मदद देकर अमेरिका को दो परस्परविरोधी देशों के रूप में विभाजित करने की बैंकर्स की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। सारी दुनियां में रुस ही एक ऐसा देश था जिसने यहूदी वर्चस्व के आगे घुटने नहीं टेके थे। यहूदियों के गुप्त संगठनों को देश में गतिविधियों की इजाजत नहीं थी। प्रतिशोध में यहूदी आतंकवादी संगठनों ने कई जार तथा उनके कई उच्च अफसरों का कत्ल किया था। यहूदी रुस को तबाह-बर्बाद करना चाहते थे। इसलिये मार्क्स, एंगेल्स के मन में भी रुस के प्रति बेपनाह नफरत थी। मार्क्स ने अपने अखबार Neue Rheinische Zeitung का इस्तेमाल रुस के खिलाफ युद्ध भडकाने के लिये किया।

मार्क्स का काम मजदूर आन्दोलन को तहस-नहस करना था !

मार्क्स ने जब मजदूरों पर एक शब्द भी नहीं लिखा था तब जर्मनी, फ्रांस, इंग्लंड इ. देशों में मजदूर आन्दोलन तीव्र हो चुके थे। समाजवाद तथा साम्यवाद इस शब्द का उपयोग मार्क्स एंगेल्स के पहले से हो रहा था। लगातार बढ़ते समाजवादी आन्दोलन पूंजीपतियों के लिये खतरा थे। मार्क्स का चचा Benny उद्योगपति था। मार्क्स के रिश्तेदार फिलिप्स परिवार में सभी उद्योगपति तथा बैंकर्स थे। उद्योगपति मजदूरों की ताकत से सामंतवाद को खत्म कर खुद को सत्ताशीन करना चाहते थे। इसलिये मार्क्स ने सन 1848 में मजदूरों में प्रचारित किया कि सामंतवाद को पहले उखाड़ना चाहिये। इसके बाद ही पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकना चाहिये। जब सामंतवाद तथा राजतंत्र पर विजय पाई गई तब मार्क्स ने यह सिधान्त प्रचारित किया कि पूंजीपति वर्ग को तभी उखाड़ फेंका जाना चाहिये जब पूंजीवाद का विकास अपनी चरम सीमा पर पहुँच जायेगा, इसके पहले नहीं। मजदूर पूंजीपतियों को नुकसान ही ना पहुँचा सके इसलिये मार्क्स ने यह कहना शुरु किया कि पूंजीवाद की चरम सीमा पर पहुँचे हुए इंग्लंड जैसे देशों में पूंजीवाद से समाजवाद में रूपांतरण संसदीय प्रणाली के तहत शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, क्रांति करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मजदूरों को संसदीय गतिविधियों में उलझा दिया। इससे यह स्पष्ट है कि मार्क्स पूंजीपतियों का एजेन्ट था और उनके हक में अपने सिधान्तों में बदलाव करता था।

मार्क्स ने मजदूर आन्दोलनों का भीतराघात किया !

मार्क्स को मजदूर आन्दोलनों के टूकड़े टूकड़े करने तथा उसे गलत दिशा देने के लिये प्रशिक्षित किया गया था। बैंकर्स की मदद से मार्क्स की मदद करने के लिये यहूदी मजदूर तथा बुद्धिजीवी मौजूद थे। मार्क्स ने मजदूर आन्दोलन के नेताओं के बीच अनावश्यक विवाद पैदा कर आन्दोलन को सही दिशा में जाने से रोका। आन्दोलन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों की :-

1. मार्क्स को डर था कि बकुनीन को मानने वाले मजदूर पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कारगर कदम उठाएंगे इसलिये उसने यहूदी मजदूरों तथा यहूदी बुद्धिजीवियों

की मदद से षडयंत्रों से इंटरनेशनल पर कब्जा जमाया। उसने इंटरनेशनल को खत्म हो जाने दिया ताकि मजदूरों के लिये कोई अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर सामान्य मंच उपलब्ध ना हो सके।

2. मार्क्स यूरोप के समाजवादियों तथा उदारवादियों की आलोचना कर गैरजरूरी विवादों को हवा देते रहा ताकि वे पूंजीपतियों के खिलाफ कारगर कदम ना उठा सके। मार्क्स का मकसद विवाद पैदा करना, आन्दोलन में भ्रम पैदा करना, तथा गलत सलाह देना था।

3. Bruno Bauer ईसाई धर्म विरोधी लेखों के लिये जर्मनी में प्रसिद्ध था। इसके बावजूद मार्क्स तथा एंगेल्स का आरोप था कि बुनो ईसाई धर्म की कड़े शब्दों में आलोचना नहीं कर रहे हैं। ईसाई धर्म का सुधारक और संत बुनो कहकर मार्क्स तथा एंगेल्स ने उसकी खिल्ली उड़ाई। जर्मनी के नेताओं ने धर्म पर ध्यान केन्द्रित करने से आन्दोलन को बहुत नुकसान पहुंचा था। ईसाई धर्म की आलोचनाओं से आहत मजदूर बड़ी तादाद में आन्दोलन से अलग हो गए थे। इसके बावजूद Bruno Bauer इ. नेता इसी विवाद में उलझे रहे। मार्क्स तथा एंगेल्स ने उल्टे आन्दोलनों की असफलता की वजह ईसाई धर्म की कठोर आलोचना करने में नाकामयाब होना बताया।

4. सन 1849 के August में Willich तथा Karl Schapper ने पूंजीपतियों के खिलाफ सशस्त्र बगावत करने का प्रस्ताव किया। मार्क्स ने इस प्रस्ताव का कडा विरोध किया। उसने दलील दी कि इसे पुलिस द्वारा फौरन कुचल दिया जाएगा। मार्क्स ने कहा कि चंद लोगों के प्रयासों से समाज में परिवर्तन रातो रात नहीं होता। समाज में परिवर्तन लाने के लिये आर्थिक स्थितियों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना तथा सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में क्रांति को आगे बढ़ाना होता है। मार्क्स की उपरोक्त दलीलें गोलमोल और पाखंडी थी। किन आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना है तथा किन सामाजिक अवस्थाओं से क्रांति को आगे बढ़ाना है यह बात मार्क्स ने बिल्कूल स्पष्ट नहीं की। 1) Willich तथा Schapper चंद लोगों के प्रयासों की नहीं बल्कि वे यूरोप के लाखों लोगों की बगावत की बात कर रहे थे। 2) फ्रेंच क्रांति के लिये किसी ने आर्थिक स्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया था और न ही यह क्रांति समाजविकास की विभिन्न ? अवस्थाओं से होकर आगे बढ़ी थी। सन 17 वी शताब्दी में Charles को Cromwell ने अपदस्त किया था वह भी किसी आर्थिक स्थितियों के विश्लेषण इ. के बगैर ही हुआ था।

सन 1848 की क्रांति की बदौलत पूंजीपतियों की मजदूरों पर पकड़ कम हो गई थी। पूंजीपतियों को मजदूरों को कुछ सुविधाएं देने पर मजबूर होना पडा था। पूंजीपति अगर मजबूत होते तो मजदूरों को सुविधाएं कतई ना देते। इसलिये 1850 में किये जाने वाली प्रस्तावित दूसरी क्रांति से मजदूरों को और ज्यादा सुविधाएं हासिल होना लाजमी था। लेकिन मार्क्स एंगेल्स ने इस क्रांति को होने नहीं दिया। सन 1851 में मार्क्स एंगेल्स दलीलें दे रहे थे कि क्योंकि सन 1848 की क्रांति के बाद हालत सुधर गए हैं, इसलिये दूसरी बगावत का यह सही वक्त नहीं है। दूसरी बगावत के लिये मजदूर

नेताओं ने दूसरे आर्थिक संकट के आने तक राह देखनी चाहिये। इसतरह मार्क्स-एंगेल्स यह सुनिश्चित करते रहे कि मजदूरों की क्रांति लगातार टलती रहे।

5. अमेरिकन गृह युद्ध के पहले से New York Tribune मार्क्स के लेखों को प्रकाशित करता था। दरअसल मार्क्स मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच होने वाले गठबंधन को रोकना चाहता था। वह उन अर्धशिक्षित मजदूरों को बरगलाना चाहता था जो ट्रीबून जैसे अखबार पढते थे। जब सन 1861 में इस अखबार से गुप्तचर विभाग का नियंत्रण खत्म हुआ और उसका आदमी Dana न्यू यार्क सन से जुड़ा तब से मार्क्स ने भी न्यूयार्क ट्रीबून में लिखना बंद कर दिया।

6. इस दौर की सबसे बड़ी घटना सन 1871 में हुई क्रांति और पेरिस कम्युन का गठन था। मार्क्स ने Der Burgerkrieg in Frankreich में लिखा कि पेरिस कम्युन से यह स्पष्ट हो चुका है कि मजदूर वर्ग पहले से उपलब्ध बुर्जुआ शासन यंत्रण का इस्तेमाल अपने हक में नहीं कर सकता। वह मजदूर क्रांतिकारी नेताओं को यह जताने की कोशिश कर रहा था कि क्रांति एक बहुत ही जटील प्रक्रिया है जिसे बिना विश्लेषण के अंजाम देना लगभग असंभव है। ([http://www.milesmathis.com/Reading the Signs, by Miles Mathis](http://www.milesmathis.com/Reading%20the%20Signs,%20by%20Miles%20Mathis)) इसतरह मार्क्स मजदूर नेताओं को पूरी तरह से बुद्धिजीवियों के नियंत्रण में लाना चाहता था क्योंकि क्रांति की जटिलताओं को समझने की अक्ल मजदूरों में नहीं है। इसलिये उन्होंने बुद्धिजीवियों को अपना अग्रणी दस्ता मानकर उनके हाथों में संघर्ष के सारे अधिकार देना चाहिये। वे ही मजदूरों के नाम पर क्रांति तय करेंगे तथा मजदूरों के नाम पर शासन करेंगे। बुद्धिजीवी जो अर्ध-बुर्जुआ वर्ग है वह मजदूरों के संघर्ष के सारे फैसले कैसे ले सकता है ? यह मार्क्स ने बताये हुए वर्ग चरित्र के सिद्धांत के खिलाफ है।

1 मई मजदूरों का “शहीदी दिवस” नहीं है !

1 मई इल्युमिनेंटी का स्थापना दिवस है। अमेरिका के शिकागो शहर में सन 1886 में पुलिस तथा मजदूरों के बीच हिंसा भडकाने की साजीश की गई। साजीशकर्ताओं का मानना था कि इस खूनी संघर्ष में बड़ी तादाद में मजदूर हलाक हो जाएंगे और उन्हे 1 मई को मजदूर दिवस के नाम पर इल्युमिनेंटी के जन्म दिवस को मनाना संभव हो सकेगा। लगातार कोशिशों के बावजूद सिर्फ 3 मई को पुलिस ने उन मजदूरों पर गोली चलाई जो काम पर जा रहे मजदूरों पर हमला कर रहे थे। एक मजदूर की मौत हो गई थी तथा तीन लोगों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। इस तरह उन्हे शहीद मजदूर तो मिल गए लेकिन उनकी शहादत 1 मई को नहीं बल्कि 3 मई को हुई थी। इसके बावजूद 3 मई की जगह 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाने लगा।

यहूदी बैंकर्स ने मार्क्सवाद को प्रचारित-प्रसारित किया !

लोकतांत्रिक राज्यों के साधन, संसाधनों तथा संपत्ति को बैंकर्स के नियंत्रण में आसानी से नहीं लाया जा सकता। कदम कदम पर नेताओं को भारी घूस देनी पडती

है। चुनावों में पक्ष-विपक्ष में अपने एजन्टों को जिताने के लिये भारी धन खर्च करना पड़ता है; चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना पड़ता है। विरोधी नेताओं को बदनाम करने के लिये तरह तरह के षडयंत्रों को अंजाम देना होता है, बैंकर्स खुद बेनकाब न हो इस तरह से विरोधी नेताओं की हत्याएं तक करनी होती है। लेकिन मार्क्सवादी तानाशाही शासन व्यवस्था में सरकार पर काबिज कम्युनिस्ट नेताओं के माध्यम से देशों के तमाम साधन संसाधन और संपत्ति को यहूदी बैंकर्स के नियंत्रण में बड़ी ही आसानी से लाया जा सकता है। विरोधी नेताओं को घूस नहीं देनी पड़ती बल्कि उन्हें सीधे मौत के घाट उतारा जाता है। जनता को लाचार और बंधुआ मजदूर बनाया जाता है।

लेकिन लोग समझते हैं कि मार्क्सवाद मजदूरों तथा गरीबों के हितों की विचारधारा है। लोगों में इस सोच को पैदा करने के लिये अरबों रुपये खर्च कर व्यापक पैमाने पर मार्क्सवाद का प्रचार-प्रसार किया गया। यहूदी बैंकर्स ने अपने सारे प्रचारतंत्र को तथा अपनी सारी यंत्रणा को इसमें झोंक दिया।

सन 1880 के बाद से यहूदी बैंकर्स ने विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और इटली में अपनी सारी यंत्रणा को देशों के उच्च वंश, रंग तथा जाति तबकों के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन करने और उन्हें प्रचारित प्रसारित करने में लगा दिया ताकि बैंकर्स के हितों में आम जनता को पार्टी नेतृत्व से दूर रखा जा सके। सन 1889 में उन्होंने कम्युनिस्ट संगठनों की द्वितीय इंटरनेशनल बनाई। इसका मकसद कम्युनिस्ट पार्टियों का दुनियां भर के देशों में विस्तार करना था।

अध्याय 6

रुस में कम्युनिस्ट क्रांति !

क्रांति तथा अंतर्राष्ट्रिय पूंजी एक-दूसरे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है अगर क्रांति के माध्यम से एक निरंकुश केन्द्रिकृत सरकार की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रिय पूंजी को केन्द्रिकृत सरकारों की मदद से व्यापारिक एकाधिकार को कायम करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। वे बिना किसी प्रतिस्पर्धा के देश के बाजार पर कब्जा कर मनमाने तरीके से धन लूट सकते हैं।

रुस में यहूदी संपन्न समुदाय था !

रुस में यहूदी मजदूरों की तादाद यहूदी आबादी का एक प्रतिशत भी नहीं थी। रुस में यहूदी बैंकिंग, शक्कर तथा तेल कारखानों के क्षेत्र में काफी शक्तिशाली थे। यहूदी वकील Dmitri Stasov जो उच्च जमींदार घराने से था, सेंट पीटर्सबर्ग की लायर्स अशोसिएशन का चेअरमन बना। सन 1904 में रुस में कुल 3567 यहूदी कुलीन जमींदार (Jewish nobles) थे। अक्टूबर विद्रोह के पहले 6.1 मिलियन आबादी वाले यहूदियों की 37% आबादी उद्योग तथा व्यापार में लिप्त थी। जार ने मुख्य धारा में

लाने के लिये यहूदियों को राज्य की शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेना अनिवार्य कर दिया था जिसकी बदौलत यहूदी शिक्षित हुए जबकि स्कूलों में दाखिला न मिलने से रुस की बाकी आबादी के अधिकांश बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पडा। युक्रेन के आधे छात्र यहूदी थे। यही वजह थी कि 87% उच्च पदों पर यहूदी थे जबकि उनकी आबादी मात्र 4.2% थी। इन यहूदियों ने उच्च पद पाने के लिये ईसाई धर्म स्वीकार किया था। कई यहूदी सर्वोच्च पदों पर थे जैसे कि Vladimir Sabler (Desyatovsky 1845-1929) सिनेटर तथा न्याय मंत्री था। Boris Sturmer (1848-1917) प्रधानमंत्री तथा आंतरिक मंत्री (Minister of the Interior) था। Nikolai Neklyudov (1840-1896) न्याय मंत्रालय का चांसलर था। सन 1905 के असफल विद्रोह के बाद भी रुस की डूमा में 12 यहूदी सदस्य चुने गए थे।

सन 1905 की कथित क्रांति !

यहूदी जार से नफरत करते थे क्योंकि वे ईसाई थे। यहूदियों की लूट और शोषण से जनता इतनी त्रस्त थी कि कभी कभी उनका गुस्सा हिंसा में बदल जाता था। इसलिये जार ने यहूदियों को Pale नामक यहूदी क्षेत्रों में ही रहने का हुक्म जारी किया। जार अलेक्झांडर द्वितीय ने रुस से गुलामी प्रथा को खत्म कर दिया तथा उन्हें जमीन प्रदान की। यहूदियों के आतंकवादी गुप्त संगठनों की जार तथा उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाईयां जारी थी। इसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रिय यहूदी संगठनों तथा बैंकर्स का पूरा पूरा सहयोग था। यहूदी आतंकवादियों ने जार की हत्या करने की बारबार कोशिश की। अंत में आठवी कोशिशों में वे March 1, 1881 को जार अलेक्झांडर द्वितीय की हत्या करने में कामयाब हुए। इसी दिन जार रुस को नई संवैधानिक सरकार देने वाले थे। अलेक्झांडर तृतीय जार बने। पता चला कि उनको जहर देकर मारा गया। इसके बाद निकोलस द्वितीय रुस के आखरी जार बने।

यहूदी बैंकर्स रुस के दुश्मनों को भारी आर्थिक मदद उपलब्ध करा रहे थे। वे पश्चिमी मुल्कों से आर्थिक मदद पाने की रुस की कोशिशों को लगातार नाकामयाब बनाते रहे थे। वे चाहते थे कि आर्थिक संकट से रुस में क्रांति के हालात पैदा हो जाये। उन्होंने रुस तथा जापान के बीच युद्ध करा दिया। Jacob Henry Schiff ने जापान को \$200,000,000 अमेरिकन डॉलर की आर्थिक मदद की ताकि जापान रुस को परास्त कर सके। सन 1904-1905 के दौरान जापान में रुसी सैनिक युद्धबंदियों को मार्क्सवादी विचारों में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे लौटकर कम्युनिस्ट क्रांति से कम्युनिस्टों को सत्ता दिला सके। हालांकि सन 1905 की बोल्शेविक क्रांति नाकाम साबित हुई इसके बावजूद यहूदी कम्युनिस्टों ने बड़े पैमाने पर खून खराबा किया।

जब जार निकोलस द्वितीय सन 1909 में स्वीडेन की सरकारी यात्रा पर गए थे तब भी उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। उन्होंने Peter Stolypin को April 1906 में अपना आंतरिक मंत्री तथा बाद में रुस का प्रधानमंत्री बनाया। स्टोलिपीन ने लोगों को खेत खरीदने के लिये राज्य से कर्जा देने की योजना लागु की। सन 1907-1914 के बीच बीस लाख लोगों ने खेत खरीदे। किसानों को आयकर से मुक्त

रखा गया। Altai के गांवों में बिजली तथा टेलिफोन की व्यवस्था की गई। स्टोलीपीन ने रुस में स्कूलें तथा अस्पताल बनाये तथा सन 1912 में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इस दौरान किसानों की मिल्कियत में रुस की तीन चौथाई जमीन आई। इन सुधारों के बाद अमेरिका, कॅनडा तथा अर्जेटिना की कुल मिलाकर होनेवाली अनाज पैदावार से ज्यादा अनाज की पैदावार रुस करने लगा। अंततः वह दुनियां की अनाज पैदावार का 40% अनाज पैदा करने लगा। अखबारों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी गई। सभी राजनीतिक दलों को कार्य करने की इजाजत थी। थलसेना तथा नौसेना को आधुनिक बनाया गया। यहूदी कम्युनिस्टों को अहसास हुआ कि अगर स्टोलीपीन के सुधार जारी रहे तो वे रुस में कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिये 1st (14th) of September 1911 के रात नौ बजे प्रधानमंत्री पीटर स्टोलीपीन की यहूदी आतंकवादियों ने जार निकोलस द्वितीय की उपस्थिति में कीव के ऑपेरा में हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल स्टोलीपीन की चार दिन बाद मौत हुई। स्टोलीपीन की इसके पहले दस बार हत्या की कोशिशें हुई थी।

सन 1917 की कथित क्रांति !

यहूदी कम्युनिस्ट नेता ट्राटस्की विएन्ना में बैरोन रोथ्सचिल्ड (Baron Rothschild) के साथ शतरंज खेला करता था। सन 1916 में जॅकोब स्चीफ (Jacob Schiff) ने ट्राटस्की को अमेरिका तलब कर अमेरिका में रह रहे निर्वासित रुसी-यहूदियों को रुस में क्रांति के लिये प्रशिक्षित करने का काम सौंपा। ये निर्वासित अमेरिका के न्यू यार्क शहर में Lower East Side में रहते थे।

धनी व्यापारी अलेक्झांडर पार्वस रुस में बोल्शेविक विद्रोह को कामयाब बनाने के लिये सन 1916 से कार्यरत था। उसने सुनिश्चित किया कि लेनिन को धन की कमी न होने पाये। झाओनिस्ट बैंकर Max Warburg ने रुस में कम्युनिस्ट प्रचार-प्रसार के लिये भारी धन उपलब्ध कराया। उसने सुनिश्चित किया कि उद्योगपति Hugo Stinnes बोल्शेविकों को कम्युनिस्ट साहित्य छापने के लिये दो मिलियन रुबल्स अदा करे। यह रकम दि. 12 अगस्त 1916 को अदा की गई। दिसंबर 1916 में Freemasons संगठन ने जार को सत्ता से बेदखल करने के लिये तीव्र प्रचार प्रसार अभियान चलाया। इन सब में लगने वाले धन की पूर्ति अमेरिका से की गई। लोगों को राजनीतिक हडताल तथा प्रदर्शन करने के लिये उकसाया गया।

ट्राटस्की को न्यू यार्क से अमेरिकन पासपोर्ट से रुस के लिये जहाज से रवाना किया गया। 27 मार्च 1917 को ट्राटस्की अपने 300 प्रशिक्षित यहूदी कम्युनिस्टों के साथ Manhattan के Lower East Side से Norwegian जहाज से सेंट पीटर्सबर्ग के लिये रवाना हुआ। उसे Jacob Schiff ने \$20,000,000 की रकम दी। Rockefeller ने अमेरिकी अध्यक्ष Woodrow Wilson की मदद से ट्राटस्की के लिये अमेरिकन पासपोर्ट बनवाया। उसने ट्राटस्की के साथ अपना खास आदमी Lincoln Steffens भेजा ताकि ट्राटस्की को बिना किसी परेशानी के रुस तक पहुंचाया जा सके। Rockefeller ने ट्राटस्की को \$10,000 की रकम सौंपी। 13

अप्रैल 1917 को जब यह जहाज Halifax में रुका तो कॅनडा की गुप्तचर संस्था के अधिकारियों ने ट्राटस्की तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर उन्हें Nova Scotia में रखा। उन्हें खबर मिली थी कि ट्राटस्की रुस को युद्ध से अलग करना चाहता है जिससे जर्मन सेना रुस से मुक्त होकर कॅनडा पर हमला कर देगी। लंदन से प्रधानमंत्री Lloyd George ने कॅनडा की गुप्तचर संस्था के लिये आदेश जारी किया कि ट्राटस्की को फौरन छोड़ दिया जाये। कॅनडा के मंत्री तथा रॉकफेलर के एजेन्ट Mackenzie King ने खुद दौड़भाग कर ट्राटस्की इ. को आजाद कराया।

लेनिन तथा उसके यहूदी साथी Scandinavia से Petrograd के लिये रेल की बंद बोगी से गए। उन्हें जर्मनी के यहूदी बैंकर Max Warburg ने दस मिलियन डालर का धन दिया था। उनके साथ दो जर्मन अधिकारी भी थे जिन्होंने Rybakov तथा Yegorov जैसे रुसी नाम धारण किये थे। लेनिन को मदद करने में जर्मनी का मकसद रुस के साथ शांति समझौता करना तथा रुस में व्यापार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करना था। Stockholm में उनके साथ तीन और लोग जुड़ गए। एक सुत्र के मुताबिक Parvus भी लेनिन से मिलने Stockholm पहुंचा था।

जर्मनी की सरकार ने लेनिन तथा उसके साथियों के Bern से Stockholm तक के लिये टिकट के पैसे अदा किये थे जबकि रुसी प्रोवेशियल सरकार ने Stockholm से Haparanda तथा वहां से Petrograd के लिये टिकट के पैसे अदा किये थे। लेनिन ने झुठमूठ ही प्रचारित किया था कि सरकार उसे गिरफ्तार कर सकती थी क्योंकि उसके पास विसा नहीं था। जबकि लेनिन तथा उसके साथियों को Stockholm के रुसी कांसुलेट जनरल द्वारा समुह का विसा दिया गया था। यह विसा आज भी Helsinki शहर के रिकार्ड कक्ष में मौजूद है। इसे 13 अप्रैल 1917 को जारी किया गया था। इसमें लेनिन तथा उसके 29 साथियों के नाम हैं। फिनलैंड से लेनिन ने अपना सफर तीसरे दर्जे की टिकट पर किया ताकि लोगों को दिखा सके कि वह कितना गरीब है। वह 16 अप्रैल की रात 11.30 बजे पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रुसी प्रोवेशियल सरकार के प्रतिनिधि Skobelev ने जो रोजगार मंत्री था ने लेनिन का स्वागत किया।

मई महिने में 200 क्रांतिकारियों का और एक समुह L. Martov तथा Pavel Axelrod के नेतृत्व में स्विट्ज़रलैंड से रुस पहुंचा। अमेरिका से हजारों यहूदी क्रांतिकारी रुस आते रहे। इनकी कुल तादाद 25,000 से ज्यादा थी। लेनिन ने अखबार तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की जिनकी कुल तादाद 41 थी जिसमें 17 दैनिक समाचार पत्र थे। सन 1917 के मई माह में प्रावदा का वितरण 3000 प्रतियों से बढ़ाकर 300,000 किया गया। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में मुफ्त में वितरित किया गया। बोल्शेविकों ने 260,000 रुबल्स में छापखाना खरीदा। जनवरी 1917 में यह तय किया गया कि यहूदी त्यौहार पुरीम दिवस के अवसर पर यानी 23 फरवरी (8th of March) को क्रांति की शुरुआत की जाएगी। (Under the sign of scorpion by Juri Lina). इस बार की तलमूद से प्रेरित क्रांति कामयाब हुई। सन 1917 की कथित क्रांति के बाद न सिर्फ जार निकोलस द्वितीय की हत्या की गई बल्कि उनके

परिवार की औरतों तथा बच्चों तक की हत्या की गई।

यहूदी नियंत्रित अमेरिकन मीडिया ने जार निकोलस द्वितीय को खूनी दरिंदे के रूप में प्रचारित किया था। इसलिये अमेरिकी जनता जार का तख्ता पलटने से खुश थी। जार निकोलस द्वितीय ने पांच विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी तथा बाकी लोगों को साईबेरिया में निष्काषित किया गया था। इसलिये उनकी आज तक “the policeman of Europe” तथा “the bloodthirsty hangman.” कहकर भर्सना की जाती रही है। सन 1826 से 1904 के बड़े कालखंड में मात्र 467 हत्यारों को मौत की सजा दी गई थी। (Professor Vittorio Strada's article "Death Penalties and the Russian Revolutions", Obozreniye, No. 14, p. 25, Paris, 1984.) इसकी सालाना औसत तादाद प्रति वर्ष 6 मृत्युदंड होती है। इसी कालावधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में Wounded Knee नामक जनसंहार में सरकारी सैनिकों ने 29 दिसंबर 1890 को 300 निहत्थे इंडियनों को जिनमें बच्चे, बूढ़े तथा औरतें भी शामिल थी को निर्ममता से हलाक कर दिया था।

बैंकर्स तथा बोल्शेविकों ने रुस से बेपनाह दौलत हासिल की !

यहूदी बैंकर्स को अपने निवेश से कई कई गुना धन हासिल हुआ। बैंकर Jacob Schiff ने ट्राटस्की को 20 मिलियन डॉलर दिये थे। इतिहासकार गरी अलेन (Gary Allen) के मुताबिक सन 1918 से 1922 के दौरान 600 मिलियन रुबल अमेरिका भेजे गये। दि. 23 अगस्त 1921 के न्यू यार्क टाइम्स के मुताबिक सन 1921 की पहली छमाही में ही बैंकिंग हाउस Kuhn, Loeb and Co. को रुस की लूटी गई दौलत से 102290000 डॉलर का मुनाफा हुआ।

अक्टूबर 1918 में बर्लिन के यहूदी बैंकर्स को रुस से सोने से भरे 47 बक्से भेजे गए जिसमें 3125 किलो सोना 191 छडों में भेजा गया था। साथ ही 50000 जर्मन मार्क्स तथा 300000 जार के रुबल्स भी हस्तांतरित किये गए थे। सन 1917 की शरद ऋतु में यहूदी बैंकर Mendelssohn ने बर्लिन में रुस से चुराया हुआ 50 676 किलो सोना तथा 113636 रुबल्स जिनकी कीमत 48819 किलो सोने के बराबर है हासिल किया। इस पर Mendelssohn के खुद के हस्ताक्षर हैं। 93.5 टन सोना Brest-Litovsk समझौते के मुताबिक जर्मनी भेजा गया। Oleg Platonov के मुताबिक सोने की यह तादाद 245.5 टन थी। लोगों से यह बात भी छुपाई गई थी।

रूसी इतिहासकार Dmitri Volkogonov ने कम्युनिस्ट पार्टी के रिकार्ड्स (archives) में पाया कि सिर्फ जार की निजी संपत्ति सोने की शक्ल में 475 मिलियन रुबल की तथा जवाहरातों की शक्ल में 7 मिलियन थी। (Dagens Nyheter, 31st of August 1992.) बोल्शेविक आर्थिक विभाग Goskhran ने इन सब पर कब्जा किया। इतिहासकार Igor Bunich के मुताबिक लेनिन तथा ट्राटस्की ने इस संपत्ति को अपने पास रखा। सोने को गुप्त रूप से रुस से बाहर भेजा गया और उनके दुनिया के दिगर निजी बैंक खातों में जमा किया गया। जार के रुस की खानों में हर वर्ष 30 टन सोने

की पैदावार होती थी।(Under the Sign of the Scorpion, p. 237)

सन 1920 में प्रोफेसर Lomonosov के नियंत्रण में जार के सोने को अमेरिका निर्यात किया गया। इसमें Jacob Schiff की बैंकिंग कार्पोरेशन Kuhn, Loeb & Co से तथा यहूदी बैंकर Olof Aschberg (Nya Banken) से स्विडन में मदद ली गई। तीन जहाजों में कुल 540 सोने से भरे बक्से इस्टोनिया रिपब्लिक के Tallinn हार्बर से भेजे गए।(U.S. State Department Decimal File, 861.51/837, 4th of October 1920.) हर बक्से में भरा सोना 60000 रुबल के मुल्य का था। कुल सोने का मुल्य 32.4 मिलियन था। बोल्शेविकों ने इस्टोनिया के Harju बैंक का इस्तेमाल धन के स्थानांतरण के लिये किया। इतिहासकार Igor Bunich के मुताबिक अंततः बोल्शेविकों ने भेजा सारा सोना अमेरिका पहुंचा। इस दौरान Kolyma सोने की खदान में ही 600000 से ज्यादा खान मजदूर जरूरत से ज्यादा काम कराये जाने से दम तोड़ गए। (Gary Allen, "Say 'NO!' to the New World Order", California, 1987, p. 22.)

बोल्शेविकों ने 7.5 बिलियन रुबल मुल्य का सोना मात्र चर्चों से इकट्ठा किया। जार तथा धनी वर्ग के जवाहरात तथा कलाकृतियों को Armand Hammer द्वारा अमेरिका के धनी लोगों के बीच बेचा गया।(Everything according to Svenska Dagbladet, 30th of March 1987.) इसके बदले खाने की चिजें मंगाई जाती थी। रुस के सारे अमूल्य जवाहरात जो चर्चों से लूटे गए थे Armand तथा उसके भाई Victor Hammer के हाथों में पहुंचे। जब भी Hammer अपने निजी विमान से मास्को आता तो उसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी। वह कस्टम प्रक्रिया से भी मुक्त था। न्यू यार्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा कि ऐसा लगता है कि रुस में बोल्शेविक क्रांति एक बहुत बड़ी आर्थिक कार्रवाई थी जिसका मकसद रुस से विशाल धनराशी को यूरोप तथा अमेरिका के बैंकों तक पहुंचाना है। बोल्शेविकों ने क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल बनाये थे जिनका मकसद रुस की संपत्ति को "राष्ट्रीयकरण" के माध्यम से लूटना था। बोल्शेविकों ने ज्यादा से ज्यादा निजी संपत्ति को कब्जे में करना शुरू किया। उन्होंने निजी व्यापार को भी प्रतिबंधित कर दिया।

रुस में यहूदी कम्युनिस्ट नौकरशाही ऐशो-आराम में रहती थी !

रुस की नई कम्युनिस्ट सरकार में 388 में से 371 सदस्य यहूदी थे। इन 371 यहूदी सदस्यों में से 265 सदस्य अमेरिका के न्यू यार्क शहर के लोअर इस्ट साइड से थे। ये सब रुसी हिब्रु थे जो अमेरिका में तीन से बारह सालों से रह रहे थे। रुस में यहूदियों की तादाद 1.25-1.75% के बीच थी जबकि तमाम सरकारी विभागों में उनकी तादाद 50 फीसदी से ज्यादा थी। लेनिन के मुताबिक इन प्रशिक्षित यहूदियों की बदौलत ही वे राज्य की नौकरशाही का पूरा कायापालट करने में कामयाब हो सके थे। लेनिन ने कानून बनाया कि antisemitism यानी यहूदियों के खिलाफ अभिव्यक्ति के लिये सजाए मौत होगी। यहूदियों के खिलाफ दिये गए भाषण तक के लिये सजाए मौत या आजन्म कठोर कारावास की सजा दी जाती थी। सभी अखबारों तथा प्रचार

माध्यमों पर यहूदियों का कब्जा था। प्रावदा का यहूदी भाषा Yiddish (Varhait) में 3 मार्च 1918 से प्रकाशन शुरू हुआ तथा अगस्त से प्रावदा का हिब्रू भाषा में भी प्रकाशन शुरू हुआ। (The Greater Soviet Encyclopaedia, Moscow, 1932, Vol. 24, p. 120.) यहूदियों का रुस के फिल्म इंडस्ट्री पर भी पूरा नियंत्रण था। यहूदी लेखकों ने क्रांति से संबंधित साहित्य का निर्माण किया। यहूदी गायकों ने काल्पनिक शौर्य गीत तथा मिथक तैयार किये।

बोल्शेविक नेता सत्ता पर काबिज होते ही राजघरानों के प्रासादों में रहने लगे। मास्को के निकट गोर्की में ग्रैंड ड्युक Sergei Alexandrov की सारी इस्टेट को लेनिन ने कब्जा किया। सारे देहातियों को जबर्दस्ती हटाया गया ताकि लेनिन के अंगरक्षकों के लिये रहने की व्यवस्था की जा सके। ट्राट्स्की ने राजकुमार Felix Yusupov की इस्टेट पर कब्जा जमाया। Slezkine के मुताबिक मास्को तथा लेनिनग्राद के यहूदी कम्युनिस्ट नेता अपना मनोरंजन भव्य थिएटर्स में करते हैं, अपने बच्चों को बेहतरिण स्कूलों में दाखिल कराते हैं, ग्रामिण महिलाएं nannies के तौर पर उनकी देखरेख में जुटी होती हैं, वे अपने सप्ताह का अंतिम दिन दर्शनीय dachas में ऐशो-आराम से बिताते हैं। यहूदी कम्युनिस्ट नेता देहातों में बने भव्य और सुंदर प्रसादों में रहते हैं। उनके पास बेहतरीन कारें हैं। वे बेहतरीन खाना खाते हैं तथा मंहंगी शराब पिते हैं। वे मंहगे डिजायनर कपड़े पहनते हैं। सेवा के लिये नौकरों की फौज रखी गई है। छुट्टियां बिताने के लिये काले सागर तथा अन्य दर्शनीय तथा मनोरंजन के स्थलों में उनकी निजी कांटेजेस हैं।

रुस में जहां चर्चों तथा अन्य धार्मिक स्थलों को सामुहिक पाखानों तथा गोदामों में तब्दिल किया गया वहीं किसी भी यहूदी धार्मिक स्थल (synagogue) को जरा भी नहीं छेडा गया। न ही किसी यहूदी धर्मगुरु (rabbi) को सलीब पर लटकाया गया। सन 1922 में मास्को में ही कई चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया जबकि दो हजार लोग समा सके ऐसे विशाल यहूदी धर्मस्थल का निर्माण किया गया। रुस में कुल मिला कर 60000 चर्चों को ध्वस्त किया गया। रास्तों चौराहों तथा शहरों को सत्ताशीन यहूदी नेताओं के नाम दिये गए।

रुस में यहूदियों को गैर-यहूदियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती थी। उन्हे गैरकानूनी व्यापार करने तक की इजाजत थी जबकि गैर-यहूदी व्यापार पूरी तरह से ठप था। यहूदियों को हर तरह के लायसेंस दिये जाते थे तथा उनके द्वारा गैर-यहूदियों पर किये जाने वाले अपराधों को नजरंदाज किया जाता था। यहूदियों ने लगभग सारे व्यापार घरानों का व्यापार हथिया लिया था।

लोगों का सारा व्यापार ठप हो गया था। दुकाने बंद थी तथा सब तरफ भूखमरी का माहौल था। यहूदी गैर-यहूदियों पर आतंक ढाते थे क्योंकि देश के हथियारों पर तथा अनाज के वितरण पर उनका एकाधिकार था। ये यहूदी स्थानीय भाषा बोल नहीं पाते थे। लोगों से वे विजेता शासक की तरह बर्ताव करते थे। सारे सोवियत में हर कमिटी और हर कमिसार में यहूदी भरे पड़े थे। अधिकतर ने अपना यहूदी नाम बदलकर

रुसी नाम रखा था। लेकिन वे जनता से अपनी पहचान नहीं छुपा सके। [Vol. II, Jews in the Soviet Union, p. 111] जनता को राज्य की यानी यहूदी नेताओं की मिल्कियत माना जाता था। उन्होने लोगों को बारह घंटों तक गुलामों की तरह मेहनत करने पर मजबूर किया था। मजदूर थक हारकर अपने गंदे, बदबूदार भीड़ भरे छोटे छोटे घरों की ओर लौटते थे जिनमें वे अन्य परिवारों के साथ रहने पर मजबूर किये गए थे। भूख तथा बीमारी से मरना गैरयहूदियों के लिये आम बात थी। कभी कोई यहूदी भूख या बीमारी से नहीं मरा।

वरीष्ठ अनाकिस्ट नेता Alexander Berkman जिन्हे अमेरिकन सरकार ने रुस निर्वासित किया था लेनिन तथा अन्य वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताओं के साथ सहयोग कर रहा था। अलेक्झांडर बर्कमैन ने काफी वक्त रुस में बिताया और अपने निष्कर्ष में पाया कि 500,000 कम्युनिस्टों ने सारे रुस को गुलाम बनाया था। रुस की आबादी 100,000,000 से भी ज्यादा थी। वहां समानता की बजाय घोर असमानता फैली है; बोलने की आजादी की बजाय लोगों की अभिव्यक्ति को कुचला जा रहा है। लोगों को हिंसा और आतंक से दबाया गया है। मौजूदा हालात बोल्शेविक तानाशाही का अवश्यंभावी (inevitable) परिणाम है। बोल्शेविकों की ताकत बहुत ही नग्न्य है। विरोधी पार्टियों के नेताओं की कमजोरी से तथा जनता के थकहार जाने से वे सत्ता पर आसिन है। आज वे क्रांति के सबसे बड़े दुश्मन है। इसके पहले रुस कभी भी ऐसी संपूर्ण तानाशाही में नहीं रहा है। बोल्शेविक अपने बर्ताव से खुद को बदतर क्रूर तानाशाह साबित कर चुके हैं। उसने समाजवादी गुलामी का गठन किया है। (The Bolshevik Myth (Diary 1920-22) by Alexander Berkman) लेनिन इ. को सहयोग करने गए इम्मा गोल्डमैन इ. नेताओं ने अपने ऐसे ही अनुभव व्यक्त किये हैं।

चुनावों में रुस की जनता ने बोल्शेविकों को नकार दिया !

लेनिन ने 9 नवंबर के आदेश से प्रेस की स्वतंत्रता खत्म की थी। लेनिन के मुताबिक क्रांतिकारी अवरथा में बोलने की स्वतंत्रता बुर्जुआ कल्पना है। ट्राट्स्की ने जाहीर तौर पर बुर्जुआ अखबार Rech के सारे संस्करण को जलाने का आदेश दिया था। चुनाव तंत्र का दूरुपयोग करने के बावजूद सन 1917 में 25 (12th) नवंबर को हुए Constituent Assembly के चुनाव में बोल्शेविक बुरी तरह से परास्त हुए। कुल 707 सीटों में से उन्हे मात्र 175 सीटें मिली। सोशल रिक्लुयुशनरियों ने 410 सीटें हासिल कर बहुमत हासिल किया था। उदारवादी नेताओं को 105, मेन्शेविकों को 16, बुर्जुआ कॅंडेटस को 17 तथा युनायटेड पिपल्स मुव्हमेंटस् को 86 सीटें हासिल हुईं। दिसंबर के अंत तक लेनिन ने सभी बुर्जुआ पार्टियों पर पाबंदी लागु कर दी। 5th (18th) जनवरी 1918 को Constituent Assembly ने बोल्शेविक सरकार को 237 के मुकाबले 136 वोटों से नकार दिया। दूसरे ही दिन लेनिन ने "Latvian riflemen" (जर्मन सैन्य टूकडी) की मदद से संसद भंग कर दी। जर्मन सैनिकों ने लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाई जो Constituent Assembly की रक्षा कर रहे थे। इस तरह बोल्शेविकों ने दोबारा तख्ता पलट किया था।

बैंकरों ने रुस में कम्युनिस्ट सत्ता को बचाया !

एक मई 1918 को बोल्शेविक लगभग सत्ता से बेदखल होने की हालत में पहुंचे। तब अमेरिका के वाशिंगटन डी. सी. में वाल स्ट्रीट के पूंजीपतियों तथा बैंकर्स ने बोल्शेविकों की मदद के लिये 'अमेरिकन लीग' नामक कमिटी कायम की। इस कमिटी में Vacuum Oil Company के George P. Whalen को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसमें General Electric कंपनी के Coffin and Oudin तथा Federal Reserve System के Thompson तथा Baltimore व Ohio Railroad के Willard इ. शामिल थे। इन्होंने अमेरिकी सरकार में मौजूद कम्युनिस्ट समर्थक लॉबी की मदद से अघोषित तरीके से बोल्शेविकों को नीचे बताये मुताबिक मदद पहुंचाई।

पश्चिमी देशों की कथित नाकाबंदी तथा सैनिक हस्तक्षेप :- पश्चिमी देशों की रुस की घेराबंदी से कम्युनिस्टों को अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका मिला क्योंकि कम्युनिस्ट बूरी हालात का सारा दोष इस नाकेबंदी पर मढ़ सकते थे। लोगों को बोल्शेविक सत्ता के सही चरित्र को समझना मुश्किल हो गया। देश के दुश्मनों, वर्गशत्रुओं तथा उनके जासूसों से रुस को बचाने के नाम पर राज्य आतंकवाद जारी रखने की कम्युनिस्टों को पूरी छूट मिल गई। ट्राट्स्की ने सभी किसान युवकों को लाल सेना में अनिवार्य रूप से शामिल कराने का आदेश दिया। आदेश को मनवाने के लिये लोगों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कईयों को वर्गशत्रु करार देकर मार डाला गया। यहूदी कम्युनिस्टों का मकसद रुस की गैर-यहूदी आबादी को जल्द से जल्द बेबस, लाचार और प्रतिरोधहीन बनाना था। इसलिये लेनिन ने घोषित किया की समूचे बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर दिया जाये। लगभग सभी स्वतंत्र रूप से विचार करने वाले लोगों की हत्याए कर दी गई तथा बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अमेरिकी पूंजिपतियों तथा बैंकर्स की आर्थिक मदद से बनाये गए विशाल गूलगों (जेलों) में कठोर परिश्रम करने के लिये टूंस दिया गया।

मित्र देशों की सेना ने अघोषित रूप से बोल्शेविकों को मदद पहुंचाई :- पश्चिमी देशों के बैंकर्स तथा पूंजिपतियों ने बोल्शेविकों की उदारता से मदद की। इन्होंने दिसंबर 1917 में भारी मात्रा में हथियार तथा टिन की आपूर्ति की। इतिहासकार Louis Fischer के मुताबिक मित्र देश की सेनाओं ने बोल्शेविकों के खिलाफ सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की क्योंकि बैंकर्स तथा पूंजीपतियों के दबाव की वजह से अमेरिका के शासक बोल्शेविकों की सत्ता को बचाना चाहते थे। अमेरिका के स्टेट विभाग ने 15 फरवरी 1918 को अपने राजदूत David Francis को तार भेजकर कहा कि वह बोल्शेविकों के साथ अनौपचारिक तौर पर संबंध बनाकर रखे ताकि औपचारिक तौर पर कम्युनिस्ट सत्ता को मान्यता देने की नौबत ही न आये। जुलाई 1918 में जर्मन टूकडियों तथा चीनी समर्थकों ने बोल्शेविकों को सोशल रिव्यूलिशनरियों की बगावत को कुचलने में पूरी मदद की और बोल्शेविक सत्ता को बचा लिया। फिनीश (Finnish) जनरल Carl Gustaf Mannerheim का मानना था कि उसके बेहद अनुशासित सैनिक Eastern Karelia पर कब्जा करने तथा पेट्रोग्राड की बोल्शेविक सत्ता को खत्म करने में सक्षम

थे। लेकिन जर्मन सैनिकों ने उनकी इस कार्रवाई को रोक दिया। अगर Finland के सैनिक बोल्शेविकों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करते तो उनके खिलाफ लंदन किसी भी सबब पर युद्ध छेड़ सकता था। (Under the sign of Scorpion by Juri Lina) उपर से आये निर्देशों के तहत मित्र देशों की सेना ने बोल्शेविकों के लिये अपने हथियार तथा अन्य सैन्य सामग्री वहीं छोड़कर पीछे हटना शुरू किया। Antony Sutton के मुताबिक अमेरिका ने बोल्शेविकों के लिये युद्ध सामग्री भेजी। मार्च 1918 के आरंभ से ही पांच अमेरिकन सैन्य अफसर लाल सेना के विभिन्न दस्तों को प्रशिक्षण दे रहे थे। ("The National Suicide", Melbourne, 1973, p. 76) Sutton ने दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा है कि ट्राटस्की ने सन 1919 में अमेरिकन राजदूत David R. Francis से कहा कि अमेरिका लाल सेना को प्रशिक्षित करे। जापान सोवियत संघ पर हमला न करने पाये इसलिये अमेरिका ने सूदूर पूर्व (Far East) पर तब तक कब्जा जमाये रखा जब तक लाल सेना अपने पैरों पर खड़ी होकर सोवियत क्षेत्र को नियंत्रित करने की हालत में नहीं पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति Woodrow Wilson ने सूदूर पूर्व के अमेरिकी सेना के कमांडर William S. Graves को यह गोपनीय आदेश जारी किया था। अंटोनी सटन (Antony Sutton) ने इन दस्तावेजों का उल्लेख किया है।

अमेरिका के नियंत्रण में Trans-Siberian Railway थी इसलिये उन्होंने आसानी से कोलचॅक की ईसाई सफेद सेना को Vladivostok से खदेड़ दिया। अमेरिकन सेना ने सारे क्षेत्र को बोल्शेविकों के हवाले किया। लाल सेना ने खुशी में उत्सव समारोह मनाये। उन्होंने अमेरिका को अपना सच्चा दोस्त बताया। जब रुसी सेना ताकतवर हुई तो अमेरिकी सेना वापस चली गई। ब्रिटीश जलसेना ने ईसाई सफेद सेना के जनरल Nikolai Yudenich को सन 1919 में बेसहारे छोड़ दिया। ब्रिटीश सेना ने सफेद सेना को मात्र अन्न इ. की सहायता की थी।

फ्रांसिसी सेना को आदेश था कि वे पूरी तरह से निष्क्रिय-तटस्थ रहे। ये सेनाएं 5-6 th अप्रैल 1919 को वापस चली गईं। मित्र देशों की सेना ने सैनिकों की गतिविधियों में तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं की। मित्र सेना ने सफेद सेना को हर वक्त धोखा दिया। आरंभ में उन्होंने सफेद सेना के खिलाफ युद्ध तक किया। जबकि बोल्शेविकों को पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद के अलावा महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गईं। The Manchester Guardian (2nd of May 1919) के मुताबिक ब्रिटेन ने सोवियत रुस के 250000 सैनिकों के लिये गोलाबारुद भेजा। जबकि सफेद राष्ट्रीय सेना को दिखावे के लिये नगन्य युद्ध सामग्री भेजी गई। फ्रांस ने सफेद सेना की बहुत ही नाममात्र की आर्थिक मदद की। मित्र देशों ने बोल्शेविकों को प्रत्यक्ष रूप से मदद की जब बोल्शेविकों ने युक्रेन पर कब्जा किया जबकि युक्रेन के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नेता Simon Petlyura के स्वाधिनता सेनानियों को कोई मदद नहीं दी गई। सफेद सेना में मुख्यतः राष्ट्रवादी स्वयंसेवक थे। ("Ukraine & Ukrainians" by Dr Ivan Owechko, p. 114)

संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका तथा उसके सहयोगी देश उत्तरी रुस से पूरी तरह से

हट गए ताकि सफेद सेना के मनोबल को तोड़ा जा सके क्योंकि तब जनरल Anton Denikin ने 31 अगस्त 1919 को Kiev पर कब्जा कर लिया था तथा मास्को की ओर बढ़ने लगा था। इसका खुलासा Paul Johnson की किताब "Modern Times" में किया गया है। (Stockholm, 1987, p. 109). पोलिश सोसॅलिस्ट जनरल Jozef Pilsudski ने बोल्शेविकों को Wisla की लड़ाई में परास्त कर दिया था। उसे लेनिन के साथ शांति कायम करने पर मजबूर किया गया। लेनिन ने कबूल किया था कि Pilsudski ने अगर युद्ध को एक सप्ताह भी जारी रखा होता तो रूस में बोल्शेविक सत्ता का अंत होता क्योंकि जनरल Wrangel की सेना उनकी ओर लगातार बढ़ रही थी तथा लाल सेना उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। जब लाल सेना ने सन 1918-19 में पोलंड पर हमला किया, पोलिश यहूदियों ने लाल सेना को सक्रीयता से मदद पहुंचाई। सफेद राष्ट्रवादी सेना को कुचलने के लिये बोल्शेविकों को पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में रायफलें तथा गोलाबारुद हासिल हुए। (Under the sign of Scorpion by Juri Lina)

इतिहासकार Igor Bunich के मुताबिक लाल सेना में जर्मनी तथा अन्य राष्ट्रीयता के सैनिक मौजूद थे। कुल 280,000 अंतर्राष्ट्रियतावादी बोल्शेविक सत्ता का संरक्षण कर रहे थे। जर्मनी ने घोषित किया था कि सोवियत सत्ता को खतरा पैदा होता है तो वे फौरन अपने सैनिक भेजेंगे। लेनिन के अंगरक्षक भी मुख्यतः जर्मन ही थे। नवंबर 1917 में जर्मनी ने बोल्शेविकों को 11.5 मिलियन मार्क्स की आर्थिक मदद दी। लेनिन ने अपने वादे के मुताबिक 15 दिसंबर को जर्मनी के साथ अलग से विशेष शांति समझौता किया। Brest-Litovsk में 3 मार्च 1918 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे सफेद सेना से लड़ने के लिये सोने की शक्ल में 40 मिलियन रुबल मुल्य की रकम हासिल हुई। इसलिये 20 अगस्त 1918 में लेनिन ने अपने खुले खत में अमेरिकन मजदूरों से गुजारीश की कि वे जर्मनी के खिलाफ युद्ध में सहयोग ना करें। 16 मार्च 1921 को सोवियत संघ तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 14 फरवरी 1919 को अध्यक्ष विल्सन ने रूस से सभी विदेशी सेना की वापसी की मांग की।

युक्रेन की जनता को भूखे मारने की कम्युनिस्ट कार्रवाई !

युक्रेन में The Holodomor शब्द का मतलब भूख से मारना है। कम्युनिस्टों ने किसानों के उत्पाद को जबरन कब्जे में लेने की मुहिम चलाई। इस अनाज को विदेशों में बेचकर अकाल के हालात पैदा किये गए। लेनिन ने अकाल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया था क्योंकि उसकी नजर में अपनी आजादी को पसंद करने वाले युक्रेन के लोग कम्युनिस्ट सत्ता के दुश्मन थे। अकाल बोल्शेविक सत्ता को मजबूत करने तथा गैर यहूदी रूसी आबादी को कम करने का कारगर साधन था। लोगों में typhus तथा दिगर गंभीर बिमारियां पैदा हुई। ("In the Light of Day", Moscow, 1992, p. 52). जुलाई 1921 में दस मिलियन लोग भूखमरी की कगार पर थे। बोल्शेविकों को सन 1921 में अनाज जबर्दस्ती कब्जाना बंद करना पड़ा। सन 1921-22 में 35 मिलियन लोगों के

पास अन्न नहीं था।(Vladimir Berelovich's article "The Diplomacy of Starvation" in the weekly newspaper Russkaya Mysl, Paris, 27th of September 1985.)

युक्रेन में यहूदी कम्युनिस्टों द्वारा दूसरा Holodomor सन 1932 तथा 1933 में पैदा किया गया। इस अकाल में युक्रेन के 60 लाख लोग भूख से मर गए। इस हकीकत को सोवियत सरकार ने छुपाने-नकारने की कोशिश की। बोलने वालों को चुप करा दिया गया। इस विनाशकारी अकाल की खबर युक्रेन के संगठनों ने छोटे छोटे पर्चों के माध्यम से बाहर पहुंचाई। सरकार ने इन पर्चों को शत्रु का प्रचार कहा। युक्रेन के अकाल के बारे में कोई भी साहित्य छपने नहीं दिया गया तथा इसे प्रचारित करने वालों को गिरफ्तार किया गया।

सरकार की निगरानी में होने वाली खेती को सामुहिक फार्म कहते हैं। किसान मात्र मजदूर होते थे तथा सारे उत्पाद पर सरकार का कब्जा होता था। सरकार के पास अनाज होने के बावजूद उसे लोगों में वितरित नहीं किया गया ताकि वे सामुहिक खेती में बंधुआ मजदूर बन जाये। किसी के पास से कुछ अनाज बरामद हो तो उसे जमाखोर करार देकर मौत के घाट उतारा जाता था।

युक्रेनियन कम्युनिस्ट नेता के मुताबिक सरकार तथा किसानों के बीच जीने और मरने का कठोर खूनी संघर्ष चल रहा है। यह साल हमारी ताकत तथा उनकी सहनशक्ति की परिक्षा का साल था। अकाल ने लोगों को समझा दिया है कि यहां के मालिक कौन है। भले ही इसमें करोड़ों की मौतें हुईं लेकिन सामुहिक खेती हर हाल में कायम रहेगी।- M. M. Khatayevich युक्रेन का कम्युनिस्ट नेता।(Victor A. Kravchenko, I Chose Freedom [Transaction Publishers, 1989], p. 130).

कम्युनिस्ट रुस आतंकवादी शासन था !

कितने लोगों की गिरफ्तारी करनी है इसकी तादाद पहले से ही कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा मूकरी कर दी जाती थी। जो भी इन गिरफ्तारियों की आलोचना करता उसे भी गिरफ्तार किया जाता था। उन्हें जानवरों की तरह हांककर तथा वाहनों में तुंसकर सायबेरिया, taiga तथा tundra जैसी भयानक थंड वाली जगहों में निर्वासित किया गया। वर्ग शत्रु करार देकर उनसे बेहद कठिन परिश्रम कराया जाता था। बर्फ की वजह से वहां की जमीन में पेड़-पौधे तक बड़ी मुश्किल से उगते थे। 35 सालों के कम्युनिस्ट शासन में गिरफ्तार लोगों में से 40-50 मिलियन लोगों की मौतें हुईं। Solzhenitsyn के मुताबिक 60 मिलियन लोगों की मौत हुई। 15 मिलियन लोगों को राज्य के दूश्मन करार देकर उनके नागरिकता के अधिकार छीने गए। उनके खेतों को तबाह किया गया।

चंद ही सालों में सन 1928 से 1931 तक 138,000 लोगों को उनकी नौकरियों से हटाया गया। उनमें से 23,000 को दुश्मनों की श्रेणी में रखा गया। सन 1930 में 12 दिसंबर को जारी एक आदेश के तहत 30 से ज्यादा प्रकार के (श्रेणियों के) लोगों से नागरिकता के अधिकार छीने गए। इनमें पूर्व के जमींदार, पूर्व के व्यापारी,

पूर्व के राजघरानों के लोग, पूर्व के पुलिसकर्मी, जार की नौकरी में रहे अधिकारी, पूर्व के जमीनदार (kulaks), निजी छोटे उद्योगकर्ता, सफेद सेना के पूर्व कर्मचारी, चर्च के पादरी इ., नन, राजनीतिक पार्टियों के पूर्व सदस्य, इ. को उनके परिवार के सदस्यों समेत इन श्रेणियों में रखा गया। कुल 7 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए। उनका वोट का अधिकार छीना गया। उन्हें रहने, इलाज हासिल करने, राशन हासिल करने, तथा नया आंतरिक पासपोर्ट का कानून लागू होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये विशेष अनुमतिपत्र पाने तक के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जनवरी 1930 से जून 1931 में Donets क्षेत्र के 48% इंजिनियरों को या तो बर्खास्त किया गया या गिरफ्तार किया गया। परिवहन क्षेत्र में ही 4,500 लोगों को “भीतराघात के विशेषज्ञ” करार दिया गया।

7 अगस्त 1932 के आदेश के अनुसार राज्य की संपत्ति को चुराने या उसे बर्बाद करने के आरोप में (जैसे कि कटाई हो चुके खेतों में पडी इक्की दुक्की गंधु की बालियों को इकट्ठा करने इ.) के आरोप में अगस्त 1932 से दिसंबर 1933 में 125,000 लोगों को अपराधी करार देकर उनमें से 5,400 को सजाए मौत दी गई। निकिता खुश्चेव ने सरकारी जांच के नतिजों को सन 1958 में हुई कम्युनिस्ट पार्टी की 22 वीं काँग्रेस में उजागर किया कि मात्र सन 1937-1938 में सरकारी गुप्तचर संस्था NKVD ने कुल 15,75,000 लोगों को गिरफ्तार किया था।

कम्युनिस्ट रुस में गुलाम-मजदूरी की व्यवस्था !

लेनिन तथा ट्राट्स्की श्रम का सैनिकिकरण चाहते थे। उन्होंने रुस को जबरन कराये जाने वाले श्रम कॅम्पों (forced labor camps) में तब्दिल कर दिया। एक बोलशेविक आदेश के मुताबिक “यह जरूरी है कि सोवियत संघ को बचाने के लिये उसके शत्रुओं को concentration camps में अलग-थलग रखा जाये।” (George Leggett, *The Cheka: Lenin's Political Police* [Clarendon Press, 1981], p. 179) 15 जून 1929 को सोवियत संघ की काउंसिल ऑफ नॅशनल इकानॉमी ने “निरंतर कार्य-सप्ताह” का आदेश जारी किया जिसमें साल भर में सिर्फ पांच छुट्टियाँ थी। (Writings of Leon Trotsky, 1929) गुलग (Gulags) केवल ताउम्र श्रम (work forever) कॅम्प मात्र नहीं थे। वास्तव में वे “श्रम से मारने” (work to death) के कॅम्प थे। इन 80 बहुत बड़े कॅम्पों के समुहों में तथा सैकड़ों असामुहिक (single) कॅम्पों में मरने वालों की दर बहुत ज्यादा थी। Kolyma [far northeastern Siberia] के एक कॅम्प में ही कम से कम 3 मिलियन लोग असहनीय हालातों में मारे गये जहां का तापमान -60 degrees C तक पहुंच जाता था। मात्र 1917-1941 में कुल 40 मिलियन लोग इन कॅम्पों में मारे गए। Solzhenitsyn के मुताबिक अक्टूबर क्रांति से लेकर सन 1950 तक कुल 66 मिलियन लोग मारे गए। [GULAGArchipelago, p. 37]

कम्युनिस्ट रुस में विदेशी भी गुलाम मजदूर बनाये गए !

यहूदी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से शुरु किये गए प्रकल्पों में

काम कराने के लिये भारी तादाद में मजदूरों की जरूरत थी। इसलिये कम्युनिस्ट सरकार ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी देशों की सरकारों की मूक सहमति से कई गुलाम-मजदूरों के कॅम्प कायम किये। फ्रांस में सन 1995 को "Foreign Slaves in the GULAG" के नाम से फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म के मुताबिक जब पश्चिमी देश दूसरे महायुद्ध में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे उस वक्त मास्को से जर्मनी में सोवियत झोन में कार्यरत NKVD तथा Smersh (Death to the spies!) के लिये आदेश आया कि इस क्षेत्र के सभी विदेशियों को बंदी बनाकर भेजा जाये। इटली, फ्रांस, पोल तथा रुस सहित अन्य देशों के मजदूर जो युद्ध से संबंधित उद्योगों में काम करते थे उन्हें तथा विदेशी निर्वासीत लोगों को और कई विदेशी युद्ध-बंदी जो जर्मनी के जेल-कॅम्पों में बंद थे उन्हें रुस में जबरन मजदूरी करने भेजा गया। जर्मनी के युद्ध-बंदियों को भी रुस भेजा गया। यहूदी बैंकर्स नियंत्रित पश्चिमी देशों की सरकारों ने इन लोगों को गायब (missing) या निर्वासित हुए (deserted) घोषित किया। लेनिन ने हर मजदूर के काम का औसत कोटा तथा उन्हें दिये जाने वाले राशन की मात्रा तय की। (Under the sign of Scorpion by Juri Lina)

कम्युनिस्ट रुस में सामुहिक जनसंहार !

यहूदी कम्युनिस्टों की चेका नामक राजनीतिक पुलिस थी। राजनीतिक कैदियों को रुस के विभिन्न कॅम्पों में यातनाएं देना, उन्हें उत्तर तथा साईबेरिया के बेहद ठंडे प्रदेशों में निर्वासित कर देना आम पध्दति थी। चेका द्वारा सामुहिक हत्याएं कर देना भी रोजमर्रा की बात थी। हत्यारों के प्रिय नारे "Long live the red terror !" "Death to the bourgeois !" थे। गिरफ्तार लोगों को ट्रक में ठूंसा जाता था। चेका के लोग हवा में फायर करते हुए चलते थे ताकि लोग घरों की खिडकियों को बंद कर दे। शहर के बाहर पहले से बनी सामान्य कब्रों के किनारे ले जाकर इन लोगों के कपड़े उतारकर उनपर गोलियाँ चलाई जाती थी। मरे तथा घायलों को इन सामुहिक कब्रों में धकेल दिया जाता था। इसके बाद इन सामुहिक कब्रों को ढक दिया जाता था।

अंग्रेज संशोधक Philipp van der Est के मुताबिक बोल्शेविकों द्वारा किये गए सामुहिक जनसंहारों में मरने वालों की तादाद आरंभ में 66 मिलियन थी जो बाद में बढ़कर 143 मिलियन तक जा पहुंची। खुद कम्युनिस्टों ने अपने इन जनसंहारों को "the Red Terror" नाम दिया। पहले के चार सालों में चर्च के 28 बिशपों को, 1215 पूजारियों को तथा 6000 monks को मार डाला गया। इसके बाद 8000 ईसाई डॉक्टरों तथा उनके सहायकों को मारा गया। 54650 थलसेना तथा नौसेना के अधिकारियों को, लेफ्टिनेंट तथा उपर की रैंक के 10500 पुलिस अफसरों को तथा 48500 निचली श्रेणी के पुलिस कर्मियों को मार डाला गया। पुरानी सेना के 260,000 flag-loyal सैनिकों को मार डाला गया। इसके बाद बुद्धिजिवियों को मारा गया। इनमें शिक्षकों, प्रोफेसर, इंजिनियर, भवन निर्माता, लेखकों तथा जजों का समावेश होता है। जजों, वकीलों, जिला अटर्नी तथा सभी उच्च शिक्षितों के व्यवसायों से संबंधित लोगों की तादाद कुल मिला कर 361,825 थी। बड़ी तादाद में किसानों को मार डाला गया।

इनकी कुल तादाद 12950 थी। बचे हुए चंद बुद्धिजीवी भारी अपमान तथ दमन के तले अपने आत्मसम्मान को समर्पित करने पर मजबूर हुए। मारे गए मजदूरों की तादाद 192,350 तथा किसानों की कुल तादाद 815,000 तक पहुंच गई। उपरोक्त आंकड़े चेका ने प्रकाशित सांख्यिकी से हैं जो उन्होने बोल्शेविक अखबारों में कथित “war communism” (1917-1921) के दौरान जारी किये थे। तब से ये तादाद बढ़ चुकी है क्योंकि यह खूनी सत्र इसके बाद भी जारी रहा। (A Sea of Blood The Truth about Bolshevik Russia By Dr. Gregor, First Edition published in 1926 by the German Folk Publishing House, Munich, Germany, Dr. E. Boepple) यहूदी नियंत्रित पश्चिमी देशों के अखबार, फिल्म, टेलिविजन इ. मीडिया तथा शैक्षिक संस्थाओं ने कम्युनिस्ट दमन और आतंक को हमेशा से ही नजरंदाज किया है या बहुत ही कम कर के आंका है। इन्हे शायद ही कभी किसी स्कूल या कॉलेज की इतिहास कक्षा में पढाया जाता है। सच्चाई की तह तक पहुंचना हमेशा से ही लगभग असंभव रहा है क्योंकि नकली दस्तावेज पेश किये गये, मूल दस्तावेजों को बदला तथा नष्ट किया गया, किताबों को जलाया गया, घटनाओं के गवाहों को मार डाला गया तथा इतिहास को यहूदी झूठ में तब्दिल किया गया।

कम्युनिस्ट रूस की नई आर्थिक नीति (NEP)

लेनिन ने सन 1921 में अपनी नई आर्थिक नीति को राज्य पूंजीवाद कहा क्योंकि विदेशी पूंजीपति अधिकारिक रूप से इन आर्थिक प्रकल्पों में 51 फीसदी तथा उससे से ज्यादा का निवेश कर सकते थे। ये पूंजीपति रूस में सन 1921 के पहले से ही सक्रिय थे। 28 अक्टूबर 1921 को Armand Hammer फोर्ड सहित अमेरिका की 38 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता था। वह सन 1943 में मास्को में अमेरिका का राजदूत बना। लेनिन की रुची रूस की संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा बटोरने में थी। इसलिये रूस की होने वाली लूट में बेतहाशा इजाफा हुआ। स्तालिन की पहली पंचवर्षीय योजना का इकलौता मकसद विदेशी पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिये नये नये प्रकल्प बनाना था। औद्योगिकरण से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। विदेशी पूंजीपति रूस से अकूत धन विदेश ले जाते रहे। सन 1923 में सोवियत रूस का पहला अंतर्राष्ट्रिय बैंक Ruskombank कायम हुआ। Morgan का सहयोगी Olof Aschberg को इसका मुखिया बनाया गया। गॅरन्टी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष Max May को इसका निदेशक (director) बनाया गया तथा Ruskombank बैंक ने गॅरन्टी ट्रस्ट कंपनी को उसका अमेरिकी एजेन्ट नियुक्त किया।

विदेशी प्रतिनिधियों के सामने झूठे दिखावे !

बेहतरीन सुविधाओं वाले स्कूल विदेशी प्रतिनिधियों को दिखाने के लिये बनाये गए थे। (Emma Goldman : My Disillusionment in Russia, 1923, The Anarchist Library) अलेक्झांडर बर्कमैन के मुताबिक इन चंद दिखावे की स्कूलों में बच्चों को बेहतरीन खाना दिया जाता था, उन्हें पहनने के लिये बेहतर कपड़े थे, वे संगीत,

थिएटर, नाचगाना तथा अन्य मनोरंजन के साधनों का आनंद उठाते थे। बाकी स्कूलों में बच्चों के कमरे बहुत बुरी अवस्था में गंदी तथा उपेक्षित हालातों में थे। बच्चों के कपड़े और बदन गंदे रहते थे। बालों में जुएं तथा शरीर पर कीटाणू थे। सोने के लिये गंदी चटाईयां थी। उन्हें बेस्वाद तथा अपर्याप्त खाना दिया जाता था। सजा के तौर पर रात में एक कमरे में भूखे पेट बंद कर दिया जाता था तथा बाहर से ताला लगाया जाता था। उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा भी जाता था। इन स्कूलों के कर्मचारियों की तादाद भी किसी अपराध से कम नहीं थी। एक स्कूल में 138 कर्मचारी थे जबकि बच्चों की तादाद मात्र 125 थी। एक अन्य स्कूल में कर्मचारियों की तादाद 40 जबकि बच्चों की तादाद मात्र 25 थी। स्कूलों की तरह ही श्रम इ. क्षेत्रों में दिखावे की इकाईयां कायम की गई थी।

मानवाधिकारों का मतलब सिर्फ यहूदी अधिकार थे !

यहूदी कम्युनिस्टों की नजर में मानवाधिकारों का मकसद मात्र "यहूदी-अधिकार" होता है क्योंकि तलमूद के मुताबिक गैर-यहूदी इन्सान ही नहीं है इसलिये उनके कोई इन्सानी अधिकार नहीं है। यहूदियों की गैर-यहूदियों पर कायम तानाशाही को कम्युनिज्म कहा गया है। गैर-यहूदियों को कम्युनिस्ट निजी संपत्ति का अधिकार, सरकार में प्रतिनिधित्व का अधिकार तथा कम्युनिस्ट पार्टी के अपने यहूदी मालिकों से सवाल पूछने के अधिकार भी नहीं है। न ही वे घर, जमीन या चीजों पर अपनी मिल्कियत रख सकते हैं। इसलिये गैर-यहूदियों से उनकी निजी संपत्ति को छीनकर यहूदी कम्युनिस्ट तलमूद में बताये गए अपने धार्मिक कानूनों पर ही अमल कर रहे थे।

जब कम्युनिस्ट किसी देश पर अपनी सत्ता कायम करते हैं, तो उनका सबसे पहला काम गैरयहूदी नेताओं को, प्रोफेसर्स को, डाक्टरों को, सरकारी अधिकारियों को, तथा ऐसे सभी गैर-यहूदियों को जो उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, उन्हें खत्म करना होता है। यह तलमूद के इस कानून का पालन करना है कि "गैर-यहूदियों के बेहतरिन से बेहतरिन इन्सान को भी कत्ल कर देना चाहिये - "The best of the gentiles — kill !"

गैर-यहूदियों पर संपूर्ण तानाशाही कायम किये बिना यहूदी खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। कम्युनिज्म में यहूदियों को किसी भी गैर-यहूदी को रिश्वत नहीं देनी पडती बल्कि हुक्म देना होता है। वे गैर-यहूदियों के मौत के वारंट जारी करते हैं जिनसे यहूदी पूजारियों की सत्ता को जरा भी खतरा महसूस होता है। यहूदी कम्युनिस्टों के चंद सालों के राज में कोई गैर यहूदी नेता नहीं बचता तथा आम जनता गहरी निराशा और हताशा में डूब जाती है। गैरयहूदी गरीबी तथा डर के माहौल में अर्धजीवित (zombie) अवस्था में जीते हैं।

रुस पर कब्जा करते ही यहूदी कम्युनिस्टों ने पहला काम antisemitism का कानून पास किया जिसके तहत यहूदियों की आलोचना को सजाए मौत दी जाती थी।

रुस में जो कुछ भी किया गया, वह पूरी तरह से यहूदियों के धार्मिक कानूनों

के मुताबिक था। ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस अध्याय 47 के verses 13-26 में यह विस्तार से बताया गया है कि यहूदी जोसेफ ने बड़ी तादाद में अनाज का संग्रह किया था (Gen. 41:29-57) ताकि वह अकाल जैसी हालातों में लोगों को उनके जानवरों, जमीन तथा उनकी अपनी खुद की स्वतंत्रता के ऐवज में अनाज बेच सके। रूस के किसानों को भी सन 1932-33 में कृत्रिम रूप से अकाल पैदा कर उन्हें सामुहिक खेती में गुलाम बनाकर रखा गया था। यहूदी धर्मग्रंथ के मुताबिक जोसेफ द्वारा इजिप्त के लोगों को गुलाम तथा खुद को बेहद ताकतवर बनाना धार्मिक रूप से पवित्र कार्य था। एक्सोडस (Exodus 3:22) में जेहोवा (Jehovah) ने आदेश दिया है कि आप लोग इजिप्त के लोगों को तबाह-बर्बाद कर दोगे और उनकी धन-संपत्ति पर अपना अधिकार कर लोगे। (Source: Robert Graves and Raphael Patai, Hebrew Myths, "The book of Genesis", London, 1964, pp. 266-267.) (Under the sign of Scorpion by Juri Lina)

अध्याय 7

वैश्विक सरकार को आकार !

यहूदी बैंकिंग समूह (Jewish banking cartel) ने सारी दुनिया को अपने आर्थिक तथा राजनीतिक नियंत्रण में लाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण शुरु किया ताकि उसके माध्यम से वे अपने फायदे के नियम-कानून विभिन्न अनुबंधों के माध्यम से सभी देशों पर लागू कर सकें। उनका अंतिम मकसद तलमूद पर आधारित वैश्विक सरकार को कायम करना है।

BIS, WB तथा IMF इ. का निर्माण !

रोथ्सचिल्ड परिवार का धन 500 trillion dollars का है। यह धन दुनिया की सारी संपत्ति का आधा है। दुनिया के बचे आधे धन को वह केन्द्रिय बैंकों के माध्यम से नियंत्रित करता है। The Peoples' Bank of China, the FED, ECB, the World Bank, the IMF इ. रोथ्सचिल्ड तथा दुनिया के 30-40 धनकुबेर परिवारों के नियंत्रण में है। वे बहुतांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं तथा अन्यो को अपने कर्ज के माध्यम से नियंत्रित करते हैं।

सन 1930 में The Bank for International Settlements (BIS) का निर्माण किया गया। BIS विभिन्न देशों के केन्द्रिय बैंकों से लेनदेन करता है। भारत का केन्द्रिय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अमेरिका का केन्द्रिय बैंक फेडरल रिजर्व है। विभिन्न देशों के केन्द्रिय बैंकों के अलग अलग नाम हैं। BIS को प्रभुसत्तापूर्ण देश जैसे अधिकार है। उसके कर्मचारियों को कूटनीतिक सुरक्षा (Diplomatic immunity) प्राप्त है। वे किसी भी देश में अपने साथ कुछ भी ला सकते हैं तथा ले जा सकते हैं। उनके आर्थिक

लेनदेन पर कोई टॅक्स नहीं लगाया जा सकता। इसमें BIS के कर्मचारियों को मिलने वाली तनखाह का भी समावेश है। सभी देशों में BIS की इमारतों तथा कार्यालयों को दूतावास की तरह के अधिकार है। इनके कामकाज पर सरकार न ही देखरेख रख सकती है न इनसे कोई जानकारी हासिल कर सकती है। उनका ऑडिट भी नहीं किया जा सकता। उन पर देशान्तरवास (immigration) के नियमों की पाबंदियाँ भी लागू नहीं होती। सभी वार्तालापों को encrypt करने और कहीं भी भेजने का उन्हें अधिकार है। वे खुद के सुरक्षाकर्मी रख सकते हैं तथा BIS सभी देशों के कानूनों से परे है।

सन् 1944 में New Hampshire के Bretton Woods में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तथा विश्व बैंक का गठन हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) का नियंत्रण बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं। वे या तो विभिन्न देशों के केन्द्रिय बैंकों के प्रमुख होते हैं या विभिन्न देशों के कोषागारों (treasury) के प्रमुख होते हैं जिनपर केन्द्रिय बैंकों का नियंत्रण होता है। वोटिंग अधिकार के मामले में अमेरिका के फेडरल रिजर्व तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर प्रभावी नियंत्रण होता है। IMF को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह अपनी खुद की कागजी मुद्रा "Special Drawing Rights," or SDR's को जारी कर सके। सदस्य देशों पर दबाव बनाया जाता है कि वे अपने देश की मुद्रा को इन SDR में पूर्ण हस्तांतरणीय (fully exchangeable) बनाये। दूसरे शब्दों में वैश्विक स्तर पर SDR सभी देशों की सामान्य मुद्रा है।

BIS के द्वारा दुनियाँ के केन्द्रिय बैंकों जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा विश्व बैंक के माध्यम से देश की सरकारों को आर्थिक रूप से नियंत्रित किया जाता है।

सन् 1987 में Edmond de Rothschild ने World Conservation Bank कायम किया। कर्ज के बदले में इन देशों को अपनी जमीन बैंक को देनी होती थी। इसतरह रोथ्सचिल्ड तीसरे देशों की जमीन जो दुनियाँ का 30 फीसदी है, को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था।

वैश्विक-मुद्रा के रूप में डॉलर !

सन् 1944 की जुलाई में अमेरिका में Bretton Woods में एक अंतर्राष्ट्रिय कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने उपस्थित देशों को अंतर्राष्ट्रिय व्यापार की मुद्रा के रूप में डॉलर को मंजूर करने के लिये मजबूर किया क्योंकि ये देश दूसरे विश्व युद्ध के खर्च से लगभग दिवालिया हो गए थे। इन देशों ने डॉलर को इस शर्त पर मंजूर किया कि 1) फेडरल रिजर्व दूसरे देशों के उत्पाद इ. को लूटने के मकसद से डॉलर को जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं छापेगा। 2) फेडरल रिजर्व अमेरिका से प्रति 35 डॉलर के बदले में एक औंस सोना कभी भी लिया जा सकेगा।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण !

सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इसका इकलौता मकसद

वैश्वीक सरकार (world government) को कायम करना है। 7th फरवरी को सिनेट के सामने बोलते हुए James Paul Warburg ने कहा कि “वैश्विक सरकार कायम होकर ही रहेगी, हम उसे चाहे या न चाहे। मुख्य सवाल यह है कि वैश्वीक सरकार सबकी सहमति से बनती है या जीतकर बनाई जाती है।” संयुक्त राष्ट्रसंघ केवल राजनीतिक विवादों को ही नहीं बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानवाधिकार इ. सभी क्षेत्रों के माध्यम से दुनिया भर के देशों को यहूदी बैंकर्स के हित में नियंत्रित करता है। वे राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक-धार्मिक, शैक्षणिक इ. सभी मामलों में अपना एकाधिकार चाहते हैं। (<https://www.henrymakow.com/How to Make Sense of Current Events - henrymakow.com.htm>) केन्द्रिय बैंकर्स तीन चरणों में वैश्वीक सरकार लाना चाहते हैं :- 1) दुनियां के देशों की अर्थव्यवस्था को केन्द्रिय बैंक के नियंत्रण में लाना, 2) युरोपियन युनियन जैसे केन्द्रिकृत बड़े सुपरदेशों का तथा कई देशों के बीच NAFTA जैसे मुक्त व्यापार के अनुबंधों को कायम करना 3) वैश्वीक केन्द्रिय बैंक के हाथों विश्व की अर्थव्यवस्था को केन्द्रिकृत करना, वैश्वीक मुद्रा जारी करना, तथा GATT जैसे समझौतों के जरिये राष्ट्रों की स्वतंत्रता को खत्म करना।

अमेरिका का यहूदी कॉलनी में रूपांतरण ?

यहूदी अपने ताकतवर सामाजिक, राजकीय, धार्मिक इ. संस्थाओं तथा संगठनों से राष्ट्र के भीतर ही एक राष्ट्र कायम करने के लिये मशहूर है। अमेरिका में यहूदियों की आबादी मात्र 3% है जबकि अमेरिकी सरकार (US-Administration) में वे लगभग 90% अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। अमेरिका का न्यूयार्क शहर वैश्वीक यहूदी शक्ति का केन्द्र है। उनकी नजर में न्यूयार्क का महत्व वहीं है जो रोम का महत्व कॅथलिक धर्मावलंबी के लिये तथा मक्का का महत्व किसी मूसलमान के लिये है। न्यूयार्क का Kehillah पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर संगठन है। अपने संगठन B'nai B'rith तथा अॅन्टी डिफेमेशन लीग (ADL) के माध्यम से बैंकर्स अमेरिका के सामाजिक जीवन को तथा राजनीति को नियंत्रित करते हैं। ADL उन सभी राजनीतिज्ञों के खिलाफ भर्सना तथा बहिष्कार की मूहिम चलाता है जो यहूदी बैंकर्स तथा इजरायल के हितों के खिलाफ हैं। वे किसी भी राजनेता को पराजित करने में तथा विभिन्न षडयंत्रों से उसका राजनीतिक जीवन तबाह-बर्बाद करने में कामयाब होते रहे हैं। ऐसे नेताओं को या तो यहूदियों की शरण में आना पडता है या फिर राजनीति से अलग हो जाना पडता है।

बैंकर्स अपने एजेंटों के माध्यम से अमेरिका के सभी राजनीतिक संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाते हैं तथा उनकी कार्रवाईयों को अपरोक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। बैंकर्स काले लोगों के संगठनों, गोरे वंशवादियों के संगठनों, महिलावादी संगठनों, विभिन्न धार्मिक संगठनों तथा कल्टस् जिसमें शैतानपूजक संगठन भी शामिल हैं को आर्थिक रूप से मदद करते हैं। बैंकर्स यहूदी-विरोधी संगठनों तक को आर्थिक सहायता देते हैं। इससे ADL को पूरी जानकारी होती है कि अमेरिका में यहूदी-विरोधी भावनाओं की तीव्रता किस हद तक पहुंची है। ADL यहूदियों को यहूदी-विरोधी

संगठनों का जरूरत से ज्यादा डर दिखाती है तथा डरे हुए यहूदियों से उनकी सुरक्षा के नाम पर हर साल कुल पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर का चंदा वसूलती है।

अमेरिका में यहूदी हर तरह की वांशीकताओं को बसाने का समर्थन करते हैं। अमेरिका में जितनी ज्यादा वांशीकताएं बसेगी उतने ही पैमाने पर अमेरिका में गोरों के वोटों की तादाद कम होती जाएगी और यहूदी अपने पसंद के उम्मीदवारों को जिता पाएंगे। लेकिन वे गैरयहूदियों को नागरिकता नहीं देने वाले इजरायल की वांशिक नीतियों का पूरा पूरा समर्थन करते हैं। यहूदी सभी गैर-यहूदियों के संगठनों तथा संस्थाओं में शामिल होते हैं लेकिन गैर-यहूदियों को अपने संस्था-संगठनों में शामिल नहीं करते। यहूदी अभ्यासक्रम की किताबों में से यहां तक कि बायबल में से यहूदी विरोधी बातों को हटाने के लिये आन्दोलन करते हैं जबकि वे अपने धार्मिक ग्रंथ तलमूद, तोराह इ. में गैर-यहूदियों के खिलाफ कही गई बातों पर पूरी शिद्दत से अमल करते हैं। वे किसी भी धर्म की आलोचना कर सकते हैं लेकिन कई देशों की सरकारों ने यहूदी प्रभाव में आकर antisemitism के खिलाफ कानून बनाये हैं जिसके तहत यहूदियों के खिलाफ या उनके धर्म के खिलाफ तर्कपूर्ण आलोचना करने वाले लेखकों को जेल भेजा जा चुका है।

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री Dr. Mahathir Mohamed ने समझाया था कि "यहूदी पूरी दुनिया पर अपने एजेन्टों के माध्यम से राज करते हैं, वे दूसरों को यहूदियों के हक में लड़ने और मरने के लिये राजी करते हैं उन्होंने लगभग सभी शक्तिशाली देशों पर अपना नियंत्रण कायम किया है यह बेहद कम आबादी वाला समाज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है।"

अध्याय 8

चीन में कम्युनिस्ट क्रांति !

जहां भी यहूदियों की आबादी तथा आर्थिक प्रभाव है उन सभी देशों में कम्युनिस्ट क्रांति की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युक्रेन, पोलंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी तथा बाल्टिक राज्यों में कम्युनिस्ट सरकारें कायम की गई थी।

चीन में यहूदियों की तादाद !

तांग साम्राज्य में 618-907 AD में यहूदी इराक से आकर चीन में बसे। Jesuit मिशनरी ने पाया कि होनान प्रांत के Kaifeng में यहूदियों के धर्मस्थल है। उनके ६ 1नी यहूदी पूर्वज काफी बड़ी तादाद में उत्तर-पश्चिम से तीन हजार साल पहले आये थे। उन्हे सम्राट Tai-tsti ने जमीन भेंट में दी जिनपर उन्होंने भव्य यहूदी धर्मस्थल बनाये। तेरहवी तथा चौदहवी शताब्दी के दौरान मंगोल शासक अपनी मध्य एशिया

तथा पूर्व यूरोप के विजय अभियानों के दौरान यहूदियों को बंदी बनाकर चीन लाये थे। जो यहूदी सन 1840 के पहले आये वे चीनी आबादी का हिस्सा बन गए और उनका नाक-नक्शा भी काफी हद तक चिनी आबादी की तरह हो गया।

आधुनिक चीन के काल में (since 1840) जब चीन को मजबूर किया गया कि वे अपने दरवाजे पश्चिमी देशों के लिये खोल दे, कई लहरों (waves) में यहूदी चीन आये। सबसे पहले उन्सिवी शताब्दी के दूसरे हिस्से में बगदाद मूल के सेफार्डिक यहूदी मुंबई (बॉम्बे) से व्यापार तथा उद्योगों की संभावना देखते हुए शंघाई, हांगकांग आये। दूसरी लहर में रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों से अशवेनाजी (Ashkenazi) यहूदी आये। तिसरी लहर में नाजी वर्चस्व वाले यूरोप के देशों से यहूदी शरणार्थी बनकर आये। सन 1937-1940 के दौरान लगभग 20,000 युरोपियन यहूदी शंघाई शहर में इकट्ठा हुए। यहूदियों की आखरी लहर में लगभग 1,000 यहूदी पोलंड तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों से सन 1940s के आरंभ से आये। सन 1941 में लगभग 1,000 यहूदी जापान से शंघाई आये। यहूदियों के प्रभावशाली नेता Zerach Wahrhafting ने सन 1941 में शंघाई के जापानी अधिकारियों से बातचित कर यहूदियों को शंघाई में बसने में मदद की।

उन्सिवी शताब्दी के मध्य में हांगकांग में यहूदी समुदाय को बसाने का काम इराकी यहूदियों ने किया था। ये लोग स्पेन तथा पुर्तुगाल से निकाले गये यहूदियों के वंशज थे। पहले अफीम युद्ध के बाद, विभिन्न देशों से यहूदियों को चीन लाकर उन्हें हांगकांग, शंघाई तीएनजीन, हारबीन तथा मंचुरिया के अनेक शहरों में स्थापित किया गया। उन्सिवी शताब्दी के आखीर से ही यहूदी भारी तादाद में रूस से पलायन कर चीन के हारबीन शहर पहुंचे। सन 1920 में वहां उनकी तादाद 25,000 थी। इन्होंने हारबीन को यहूदियों के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र में तब्दिल किया। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान भारी तादाद में यूरोप के यहूदियों ने चीन के शंघाई शहर में शरण ली। तब शंघाई शहर में आने के लिये विसा की जरूरत नहीं थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 25,000-30,000 यहूदी शंघाई आये। चीन में फेंच तथा अन्य देशों के हुक्मरानों ने यहूदियों का स्वागत किया। बर्लिन में Manchukuo दूतावास के राजदूत Wang Ti-fu के मुताबिक हजारों को एशियन डिप्लोमेटस् द्वारा विसा दिया गया। विएन्ना में चीनी कांसुल (consul) के जनरल Ho Feng-shan, काउनास (Kaunas) में जापानी कांसुल Chiune Sugihara, इ. ने उच्च अधिकारियों के मना करने के बावजूद यहूदियों को विसा जारी किया।

चीन में यहूदियों का विस्तृत सामाजिक संजाल (Network) !

हार्विन के यहूदी कई धार्मिक स्थलों (synagogues), स्कूलों, पुस्तकालयों, एक अस्पताल तथा दो यहूदी बैंकों, वृध्दाश्रम, सांस्कृतिक तथा थिएटर, तथा असंख्य सेवा संस्थाओं को चलाते थे। यहूदी धार्मिक स्कूल द तलमुद तोराह को हार्विन शहर में सन 1919 में कायम किया गया। रूसी तथा यिड्डीश (Yiddish) भाषाओं में यहूदी कई प्रकाशन संस्थाएं चलाते थे। सन 1937 में सूदूर पूर्वी यहूदी काउंसिल की

स्थापना की गई। सूदूर पूर्व के देशों में रहने वाले यहूदियों की कॉन्फ्रेंस हाबिन शहर में सन 1937-1939 में तीन बार आयोजित की गई। इन कॉन्फ्रेंसों में Tianjin, Shanghai, तथा चीन के दिगर शहरों के अलावा कोबे, जापान इ. देशों से प्रतिनिधि आये थे। सन 1937 की कॉन्फ्रेंस में निर्णय हुआ कि चीन के सारे यहूदी समूदायों को एक स्वयंनियंत्रित संगठन में तब्दिल किया जाये। संगठन में यहूदियों के सारे धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के अलावा मध्य यूरोप से आये यहूदियों की देखभाल करना सूदूर पूर्व के सारे यहूदियों का तथा उनके विभिन्न संगठनों का लेखाजोखा (register) रखना इ. काम शामिल होंगे। बिसवी शताब्दी में हारबिन के अलावा उत्तर-पूर्वी चीन, मंगोलिया के प्रदेश जैसे कि Hailar, Manchuli, Dalian, Mukden इ. के यहूदियों के संबंध हारबिन समुदाय से जुड़े थे। Matthew Nathan सन 1904 से 1907 तक हांगकांग का गवर्नर यहूदी था।

चीन में यहूदियों का अफीम-व्यापार का संजाल (Network) !

यहूदी डेविड सॅसुन (David Sassoon) को सन 1832 में बगदाद छोडना पडा था। उसने खुद को बाम्बे (मुंबई) में स्थापित कर लिया। अपने आठ बेटों को उसने चीन के हर बंदरगाह पर अफीम व्यापार का मुखिया बनाया। उसके कार्यालय हांगकांग, सिंगापूर, बर्मा, कॅन्टन से लेकर जापान तथा इंडोनिशिया में थे। ससुन ने अपने व्यापार का चीन तथा जापान में विस्तार किया। सिर्फ यहूदी उसके कर्मचारी होते थे। वह विभिन्न देशों के यहूदी परिवारों को चीन ले आया।

इंग्लंड की महारानी विक्टोरिया को तथा ब्रिटीश सरकार को इस अफीम व्यापार से होने वाले मुनाफे का एक बडा हिस्सा मिलता था। अंग्रेज सरकार ससुन की भाडे की सेना (mercenaries) के तौर पर काम करती थी। सन 1839 में पराजित चीनी हुक्मरानों तथा विजयी ससुन परिवार के बीच एक समझौते (The Treaty of Nanking) पर हस्ताक्षर किये गए। इसमें 1) चीन में अफीम व्यापार को पूरी तरह से कानूनी मान्यता देना, 2) चीनी हुक्मरानों द्वारा जब््त की गई अफीम के मुआवजे में 2 मिलियन पाउंड का मुआवजा अदा करना, तथा 3) अंग्रेजी सरकार को चीनी समुद्र के बाहर के दो सौ से ज्यादा टापु देना तथा चीन इंग्लैंड को युध्द खर्च के मुआवजे में 21 मिलियन पाउंड देगा यह तय किया गया। इससे ससून को समाधान नही हुआ और उसने मांग की कि उसे सारे चीन में अफीम के व्यापार का एकाधिकार दिया जाये। मांचु सरकार ने इसका विरोध किया जिससे अंग्रेज सेना ने फिर से चीन पर हमला किया। यह युध्द 1858-1860 के दौरान लडा गया जिसमें चीन की हार हुई। दि. 25 अक्तूबर 1860 में हुए शांति समझौते के तहत ब्रिटीशों को चीन के 87.5% हिस्से में अफीम का व्यापार करने की इजाजत दी गई जिससे सन 1864 के वर्ष में ससून परिवार को 20 मिलियन पाउंड का मुनाफा हुआ। इंग्लैंड को हांगकांग तथा Amoy, Canton, Foochow, Ningpo तथा Shanghai शहरों के बडे हिस्से दिये गए। ससून परिवार ने ब्रिटीश हुकुमत के क्षेत्रों में ताकतवर लोगों को अफीम व्यापार के लाइसेन्स जारी किये।

चीन में यहूदियों का व्यवसायिक साम्राज्य !

इलियास डेविड ससून (Elias David Sassoon) ने सन 1867 में E.D. Sassoon & Co की शाखाएं हांगकांग तथा शांघाई शहर में खोली। उसकी कंपनी ने अपने पिता की कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी कंपनी का नाम व्यापार तथा बैंकिंग ताकत का पर्यायी नाम बन गया। डेविड ससून के एक पुत्र आर्थर उस प्राविंशियल कमिटी में था जिसने सन 1864 में Hong Kong and Shanghai Banking Corporation कायम की थी। उसके दूसरे पुत्र फ्रेडरिक (Frederick) को सन 1884 में विधानसभा (Legislative Council) के लिये चुना गया। ससून परिवार ने जहाज उद्योग में, होटल व्यवसाय तथा जमीन-जायदाद के व्यवसाय में भारी निवेश किया। सर अलबर्ट ससून ने बाम्बे (मुंबई) में कपडे की मीलें खोली। पहले विश्व युद्ध के बाद भी उनका कपडा व्यवसाय में विस्तार होता गया जिसकी बदौलत इंग्लंड के Lancashire की मीलों का दिवाला निकल गया। हजारों को नौकरियां गंवानी पडी। इसके बावजूद रानी विक्टोरिया ने सन 1872 में उसे knight की उपाधि से सम्मानित किया। ससून परिवार के कई लोग Baronet बनाये गये। एक को सरकार में मंत्री बनाया गया। सन 1887 में ससून का विवाह **Aline Caroline de Rothschild** से हुआ। महारानी विक्टोरिया ने एडवर्ड को भी knight की उपाधि दी। ससून परिवार इंग्लंड स्थानांतरित हुआ। वे लंदन स्थित अपनी विलासिता पूर्ण विशाल estates से आधुनिक दूरसंचार के माध्यमों से अपने व्यापार को नियंत्रित करते थे।

इल्ली कदूरी (Elly Kadoorie) कदूरी सन 1880 में हांगकांग आया और ससून परिवार की कंपनी में शामिल हुआ। इल्ली शांघाई स्थानांतरित हुआ जबकि उसके भाई इल्लीस (Ellis) ने हांगकांग के व्यापार पर ध्यान दिया। उन्होंने रबर के पेड, बैंकिंग व्यवसाय, बंदरगाह तथा जमीन इ. के व्यापार में बेशुमार संपत्ति अर्जित की। सन 1914 में इल्लीस ने हांगकांग तथा शांघाई के होटल व्यवसाय में भारी निवेश किया। उसने चीन में Light and Power (now CLP Holdings) कंपनी खरीदी। यह हांगकांग की बिजली पैदा करने वाली सबसे बडी कंपनी थी।

अन्य यहूदी Emanuel Belilios ससून परिवार का समकालीन दूसरा एक बेहद धनी अफीम व्यापारी था। सन 1881 में उसे Legislative Council के लिये चुना गया था।

सन 1921 में Harry Odell नामक यहूदी को हांगकांग में थिएटर क्षेत्र को बढावा देने वाला पहला व्यक्ति कहा गया। उसने फिल्म इंडस्ट्री शुरु की। उसने प्रसिद्ध नाटककारों को आमंत्रित किया तथा अपनी यहूदी लॉबी की मदद से सरकार को राजी कर City Hall theatre complex बनाने में कामयाबी हासिल की। Tianjin के अधिकांश यहूदी व्यापारिक गतिविधियों में तथा विशेष तौर से बालों वाले चमडे (fur) के व्यापार में सक्रिय थे। शहर में इन यहूदियों की मिल्कियत की सौ से ज्यादा कंपनियां थी। चमडे को उत्तर-पूर्वी चीन से लाया जाता था तथा Tianjin शहर में उस पर

प्रक्रिया की जाती थी। तैयार चमड़े को अमेरिका तथा यूरोप भेजा जाता था। Tianjin के यहूदी अन्य कई चीजों का निर्यात भी करते थे।

चीन में अपराधिक माफिया !

पूँजीपति तथा व्यापारी अपने फायदे के लिये राजनीति तथा अपराध जगत का इस्तेमाल करते हैं। इसलिये चीन के अपराधिक माफिया Triads के बारे में जानना जरूरी है। वे 18 वीं शताब्दी से Hung Society में कार्यरत थे। ट्रायड विदेशी व्यापारियों को चीन में अफीम लाने में मदद करते थे। यानी वे ससून परिवार तथा अंग्रेज सरकार को सारे चीन तथा सूदूर पूर्व देशों में अफीम का व्यापार करने में मदद करते थे। मांचु किंग (Manchu Qing) वंश के राजाओं के काल में Triads गुप्त संस्थाओं की तरह काम करते थे। सन 1911 में मांचु वंश के आखरी सम्राट को अपदस्त करने में Triads की भूमिका थी। चीन में 1920 के दशक से लेकर 1940 के दशकों तक चले लंबे अर्से के युद्धपतियों (warlord) के काल में चीन तथा खासकर शंघाई में जहां यहूदी खासी तादाद में है, Triads बेहद फले फूले। हांगकांग में Triads स्थानीय अफीम व्यापार में सक्रिय थे तथा अंग्रेजी साम्राज्य की पुलिस को सहयोग करते थे। अकेले हांगकांग में पचास से ज्यादा Triad गिरोह है। चीन की Triad संस्थाएं दुनिया की बहुत बड़ी अपराधिक संस्थाओं में गिनी जाती हैं। उनके सदस्यों की तादाद लगभग ढाई लाख है, हांगकांग में उनकी तादाद एक लाख है। उनका अपराधिक साम्राज्य कई बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है। हांगकांग हमेशा से यहूदी ससून परिवार के नियंत्रण में रहा है। Triad के सदस्य कई रूप धारण करते हैं। अपराधी होने के साथ ही वे जज, सरकारी अफसर, राजनीतिक नेता इ. भी होते हैं।

चीन में विदेशी बैंकों का संक्षिप्त इतिहास !

यहूदियों का मुख्य वांशीक व्यापार सूदखोरी तथा बैंकिंग है। चीन में सबसे पहला विदेशी बैंक बाम्बे (मुंबई) का ब्रिटीश ओरिएंटल बैंक था। उसकी शाखाएं हांगकांग, Guangzhou तथा शंघाई में सन 1840s के दशकों में कायम हुई थी। चीन में कई ब्रिटीश बैंकों ने अपनी शाखाएं कायम की। लगभग चालीस सालों तक चीन में ब्रिटीश बैंकों का एकाधिकार था। हांगकांग तथा शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन जिसे सन 1865 में कायम किया गया था बाद में चीन का सबसे बड़ा विदेशी बैंक बना। 1890s के दशक के आरंभ के वर्षों में जर्मनी का Deutsch-Asiatische Bank, जापान का Yokohama Specie Bank, फ्रांस का Banque de l'Indo-Chine, तथा रूस का Russo-Asiatic Bank इ. बैंकों ने चीन में अपनी शाखाएं खोली। उन्सिवी शताब्दी के अंत में चीन के विभिन्न बंदगाहों के शहरों में नौ विदेशी बैंकों की पैंतालिस शाखाएं थी। चीन सरकार की विदेशी अदायगी तथा विदेशी व्यापार पर विदेशी बैंकों का पूर्ण नियंत्रण था। लडाईयों में हुई हार से मांचु सरकार विदेशी ताकतों को मुआवजे की रुकम अदा करने के लिये विदेशी बैंकों से कर्जा लेने पर मजबूर थी। विदेशी बैंक चीनी सरकार के नियंत्रण से बाहर थे। वे अपने बैंक नोट जारी कर सकते थे। वे चीनी लोगों

के बैंक खाते खोलते थे तथा स्थानीय बैंकों को कर्जा देते थे।

चीन का पहला केन्द्रिय बैंक सन 1905 में कायम हुआ तथा बाद में उसका नाम Great Qing Government Bank रखा गया। इस बैंक को पूरे अधिकार दिये गए थे कि वह अपनी मुद्रा जारी करें। इस मुद्रा का उपयोग टैक्स तथा ऋण अदायगी समेत सभी सरकारी तथा निजी लेनदेन में होता था। सन 1911 की Xinhai क्रांति के बाद Da Qing Bank का नाम "बैंक ऑफ चायना" किया गया। उत्तरी सैनिकिय चढाई (Expedition) से लेकर सन 1937 के दशक को चीन के बैंकिंग व्यवसाय का "सुनहरा दशक" कहा जाता है।

स्तालीन और माओ की बातचीत के अंशों से साबित होता है कि कम्युनिस्ट चीन में विदेशी बैंक ताकतवर थे तथा उन्हें कम्युनिस्ट सरकार द्वारा छोड़ा नहीं गया था। (Conversation between the Soviet Union's Joseph Stalin and China's Mao Zedong December 16, 1949 (<http://international.ucla.edu/asia/mao491216.htm>))

चीन की राष्ट्रवादी पार्टी कोमिन्तांग (Kuomintang) !

Dr. Sun Yat-sen ने अपना क्रांतिकारी आन्दोलन Canton में शुरू किया। यहूदी Morris Cohen जो ब्रिटीश नागरिक था, डॉ. सुन यात सेन का aide-de-camp बना। डॉ. सुन यात सेन ने उसे कई देशों में भेजा ताकि क्रांतिकारी सेना के लिये सैनिक विशेषज्ञ मिल जाये। सन 1911 में सुन यात सेन के नेतृत्व में Xinhai क्रांति द्वारा Qing Dynasty के राजवंश की सत्ता को पलटकर चीनी रिपब्लिक कायम किया गया। राजतंत्र के अंत से चीन में युद्धपतियों का दबदबा हो गया था। सोवियत सरकार ने सन 1923 में यहूदी Jacob Borodin को यहूदी Joffe के साथ भेजा ताकि वे डॉ. सुन यात सेन की कोमिन्तांग सरकार में मुख्य राजनीतिक सलाहकार बनकर डॉ. सुन यात सेन को बोल्शेविक रंग में रंग सके। डॉ. सुन यात सेन की बिबी यहूदी थी तथा चीन में सोवियत संघ के लिये जासूसी करती थी। सन 1925 में डॉ. सुन यात सेन की मौत के बाद चीन को एक करने की जिम्मेदारी कोमिन्तांग नेता चांग काई शेक (Chiang Kai-shek) पर आई।

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन !

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन सन 1921 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा शंघाई की मिटींग में किया गया। शंघाई में बड़ी तादाद में यहूदी रहते थे। पश्चिमी देशों से शंघाई तथा बाद में हांगकांग में कई यहूदी चीन में सशस्त्र क्रांति में मदद करने आये। बैंकर रोथ्सचिल्ड ने Dr. Ho Feng-Shan को विएन्ना में चीनी कांसूल जनरल के रूप में मई 1938 से मई 1940 तक स्थापित किया था। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तथा दौरान पश्चिमी देशों के 21,000 यहूदियों को चीन का विसा जारी किया। सन 1937 में Edgar Snow ने चिनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिये Red Star Over China नामक रॉकफेलर प्रायोजित किताब लिखी। एडगर स्नो के अवशेष

बेर्जींग युनिवर्सिटी में दफन है। सन 1930s के दशक से सन 1949 के दौरान कई विदेशियों ने चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही कायम करने में मदद की है। इनमें Manfred Stern सन 1932-1935 तक Otto Braun (alias: Li De) चीन में 1932-1939 तक कोमिंत्न का एजेंट था।

चीन में येल विश्वविद्यालय (Yale University) की स्थापना Eli Yale ने की थी। ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के लिये अफीम की स्मगलिंग करके उसने धन हासिल किया था। सन 1903 में येल डिवाइनिटी स्कूल ने सारे चीन में कई शाखाएं तथा अस्पताल कायम किये। इन सबको सामुहिक रूप से 'Yale in China' कहा जाता था। चीन में 'Yale in China' गुप्तचर संस्था का संजाल (network) था। 'Yale in China' को यहूदी कम्युनिस्ट प्रिय थे क्योंकि वे अफीम के उत्पादन में समर्पित थे। डॉ. अंथोनी सटन (Dr. Antony Sutton) की किताब 'The Patriot Review' के मुताबिक अमेरिका के Skulls and Bones नामक गुप्त संस्था (Secret Society) ने चीन में कम्युनिस्ट आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के प्रभाव में अमेरिकी सरकार तथा उसकी गुप्तचर संस्था Office of Strategic Services (OSS) ने 'Yale in China' को अपना साधन बनाकर कम्युनिस्टों को सत्ता में लाने की कोशिशें की।

कोमिंन्तांग में कम्युनिस्ट घुसपैठ !

सन 1923 से 1927 के दौरान कोमिंत्न एजेंट तथा यहूदी Mikhail Gruzenberg (Mikhail Borodin) को चीन भेजा गया था। उसने चीन की राष्ट्रीय सरकार की नौकरशाही में कम्युनिस्टों को शामिल करने के लिये कोमिंगतांग (KMT) सरकार को राजी किया। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पार्लियामेंट सदस्य Israel Epstein का नाम प्रमुख था। यहूदी Morris Cohen को कॅन्टन सरकार और दिगर देशों के कांसुलेट जनरलों (Consulates-Generals) के बीच वार्तालाप अधिकारी (liaison officer) नियुक्त किया गया था। कोहेन को चीन में Moi-Sha के नाम से जाना गया। उसे कॅन्टन की चीनी सेना का मिलिटरी काउंसिलर बनाया गया, हालांकि उस वक्त वह ब्रिटिश नागरिक था। यहूदी A. Joffe जो डॉ. सुन यात सेन के सोवियत मिशन का प्रमुख था वह सन 1926 में चांग काई शेक का राजनीतिक सलाहकार बना। उसने कोमिंन्तांग संगठन में कम्युनिस्टों का लाल विभाग संगठित किया। W. N. Levitshev तथा J. B. Gamarnik नामक दो यहूदी सन 1936 में चीन की लाल सेना के राजनीतिक विभाग के प्रमुख बने। राकफेलर द्वारा आर्थिक मदद हासिल लोगों को चीन भेजा गया। उन्होंने कोमिंन्तांग में शिरकत की और कोमिंन्तांग का भीतराघात करते हुए कम्युनिस्टों के लिये काम करते रहे।

जब चांग काई शेक को कम्युनिस्टों के षडयंत्रों का अहसास हुआ तो उन्होंने सन 1928 तक सोवियत संघ के कई एजेंटों को निष्काषित कर दिया। सन 1927 में पेकिंग के सोवियत दुतावास पर छापा मारा गया तब पता चला कि चीन को कब्जे में करने की कम्युनिस्टों की साजीश कितनी गहरी थी। परिणाम स्वरूप बोरोडिन तथा

उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।

तब भी नानकिंग के वित्त विभाग में पूरी तरह से Kann, L. Rajchman तथा R. Haas इ. यहूदियों का वर्चस्व था। यहूदी Ben Kizer [USA] को चीन में Unrra का प्रमुख बनाया गया। सन 1938 में इंग्लैंड में यहूदी Billmeir अपने व्यापारिक जहाज के जरिये सोवियत हथियारों तथा गोलाबारुद को चीन पहुंचाने का काम करता था। कोमिन्तांग सरकार में यहूदियों की भारी तादाद थी जो गुप्त रूप से कम्युनिस्टों के लिये काम करते थे।

माओ झेडांग (माओ त्से तुंग)

माओ झेडांग 'Yale in China' का एक छात्र था। उसके पिता की अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति की बदौलत उसे इस स्कूल में तथा बाद में उच्च शिक्षा के लिये चांगशा (Changsha) भेजा जा सका था। माओ को Skull and Bones गुप्त संस्था के यहूदियों ने शिक्षित किया था। उन्होंने माओ को internationalist Masonic Lodge में दीक्षा दी। माओ को Yale University के संसाधनों से प्रशिक्षित किया गया। माओ ने अपनी सहपाठी अपने शिक्षक की बेटी Yang Kaihui से विवाह किया। पेकिंग विश्वविद्यालय के डीन Chen Duxiu ने डॉ. सुन यात सेन की Xinhai क्रांति में हिस्सा लिया था। माओ पूरी तरह से नियंत्रण तथा ब्लैकमेल करने योग्य मोहरा था।

कम्युनिस्ट लाल सेना में यहूदियों को बड़े पद तथा बड़ी उपाधियाँ दी गई थी। विएन्ना के डॉक्टर Jakob Rosenfeld को चीनी क्रांति का नायक करार दिया गया। कॅनेडा के डॉक्टर Norman Bethune की चीन-जापान युद्ध के दौरान की सेवाओं से प्रभावित माओ ने उसपर एक लेख लिखा। यहूदी डॉक्टर General Luo का स्थान लाल सेना के उच्च पदाधिकारियों में महत्वपूर्ण था। उसे सन 1947 में कम्युनिस्ट सेना की प्राविंशियल सरकार में "स्वास्थ्य मंत्री" कहा गया। सन 1930 के दशक में यहूदी जनरलों ने माओ से लाल सेना का नियंत्रण छीनकर अपने हाथों में ले लिया था लेकिन बाद में दोबारा यह नियंत्रण माओ को वापस दे दिया गया।

चांग काई शेक ने लाल सेना को ऐतिहासिक शिकस्त दी और "Jianxi Soviet" को कूचल दिया। तब 16 अक्टूबर को लांग मार्च (पलायन) शुरु हुआ। चांग काई शेक ने माओ की सेना का न पीछा किया और न ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की क्योंकि उसके बेटे को मास्को में बंधक बनाया गया था और चांग काई शेक को डर था कि उसके बेटे को मार डाला जाएगा।

चीनी गृहयुद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नियंत्रण वाले Jiangxi तथा Yan'an की सोवियतों का खर्चा अफीम के व्यापार से चलता था। अफीम के व्यापार से कम्युनिस्टों को प्रतिवर्ष साठ मिलियन अमेरिकन डॉलर की आय होती थी। अफीम के अधिक उत्पादन तथा दिगर कम्युनिस्ट अधिकारियों तथा अन्यों ने जबर्दस्त दबाव से अफीम व्यापार बंद करना पड़ा।

अमेरिकी सरकार में कम्युनिस्ट समर्थक लॉबी !

अमेरिकी सरकार यहूदी बैंकर्स के प्रभाव में होने से सरकार में बड़ी तादाद में कम्युनिस्ट समर्थक थे। Dean Acheson अमेरिका में सोवियत हितों को सुरक्षित रखने का काम करता था। वह सन 1941 में सरकार का असिस्टेंट सचिव था। उसने सुनिश्चित किया कि स्टेट डिपार्टमेंट की सूदूर पूर्व डिविजन में कम्युनिस्टों तथा कम्युनिस्ट समर्थकों का वर्चस्व रहे। Alger Hiss सोवियत संघ का जासूस साबित हुआ था। John Carter Vincent को Office of Far Eastern Affairs का निदेशक (director) बनाया गया। साबित हुआ कि वह भी कम्युनिस्ट है। John Stewart Service चीन में विदेशी सेवा अफसर था। वह स्टेट डिपार्टमेंट की जानकारियों को चीनी कम्युनिस्टों तक पहुंचाता था। अमेरिकी गुप्तचर संस्था FBI ने उसे अमेरिसिया (Amerasia) जासूसी मामले में गिरफ्तार किया। विदेश सेवा अधिकारी John P. Davies सरकार में कम्युनिस्टों के लिये समर्थन जुटाता रहा। Owen Lattimore को चांग काई शेक का अमेरिकी सलाहकार नियुक्त किया गया था। साबित हुआ कि वह भी कम्युनिस्ट है। अमेरिकी सरकार में साबित हुए कम्युनिस्टों में सरकारी कोषागार में सहायक सचिव Harry Dexter White भी था। अमेरिकी सीनेट की अंतर्गत सुरक्षा कमिटी ने पाया कि इंस्टिटयुट ऑफ पॅसिफिक रिलेशन्स (IPR) में 54 लोग वैश्वीक कम्युनिस्ट षडयंत्रों में शामिल थे। इनमें Alger Hiss, Frederick Vanderbilt Field, Owen Lattimore, तथा John Stewart Service इ. लोग शामिल थे। रुजवेल्ट (FDR) प्रशासन में कम्युनिस्ट लॉबी माओ का महीमामंडन करती थी तथा चांग काई शेक को एक क्रूर, भ्रष्ट, फासिस्ट, प्रतिक्रियावादी खलपुरुष के रूप में प्रचारित करती थी। सन 1943 से 1949 के दौरान 22 कम्युनिस्ट समर्थक किताबें अमेरिका में छपी गईं। IPR को रॉकफेलर तथा Carnegie कांडेंडेशन से आर्थिक सहायता मिलती थी। इस संस्था ने चीन पर अमेरिकी स्कूलों तथा सेना के लिये बहुत बड़ी तादाद में पुस्तिकाएं छपीं। इन पुस्तिकाओं में यह असत्य फैलाया जाता था कि चीन के कम्युनिस्ट खेतिहर सुधारवादी है जबकि चीन के राष्ट्रवादी फासिस्ट है।

सोवियत सरकार अधिकारिक तौर पर तथा अमेरिकी सरकार जनता के डर से गैरअधिकारिक यानि छूपे तौर पर चीन के कम्युनिस्टों का समर्थन करती थी। चीन में राजदूत Hurley ने खुद को स्टेट डिपार्टमेंट में कम्युनिस्ट समर्थकों के बीच घिरा पाया। ये लोग चीन में सशस्त्र कम्युनिस्ट सत्ता कायम करना चाहते थे। उनके इन अधिनस्थों के कार्यकलापों से Hurley को बड़ा आघात लगा। मजबूरन उन्होंने अपने अधिनस्थ 11 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। जब वे चीन से वापस अमेरिका आये तो उन्होंने पाया कि अब ये लोग उसके उच्च अफसर बना दिये गए हैं। इसलिये Hurley ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

चीन के राष्ट्रवादियों के खिलाफ स्तालिन की नीति !

द्वितीय विश्व युद्ध में स्तालिन जर्मनी के विरुद्ध मित्र देशों का सहयोगी था।

इसके बावजूद उसने जापान के साथ आपस में युद्ध न करने का समझौता किया हुआ था। स्तालिन चाहता था कि जापान चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को बेहद कमजोर और जर्जर बना डाले।

स्तालिन ने चीनी कम्युनिस्टों को आदेश दिया कि वे चांग काई शेक को जापान के विरुद्ध सिमित सीमा तक ही मदद करे। इसलिये माओ ने लाल सेना से कहा कि हमारी नीति यह है कि हम अपनी 70 फीसदी ताकत को खुद को ताकतवर बनाने में, 20 फीसदी ताकत को समझौतों में तथा केवल 10 फीसदी ताकत को जापानियों के खिलाफ लड़ने में खर्च करे। इसलिये कम्युनिस्टों ने जापानियों के खिलाफ न के बराबर लड़ाईयां लड़ी। वे मुख्यतः नॅशनलिस्टों के खिलाफ हमले करते थे जिन्हे सत्ता से बेदखल करना उनका मकसद था। Chang तथा Halliday के मुताबिक सच्चाई यह है कि कम्युनिस्टों ने शायद ही कभी जापान से युद्ध किया। कुछ चंद मामलों में जब लालसेना ने जापानियों के खिलाफ संघर्ष किया तो माओ बहुत गुस्सा हुआ। यह कम्युनिस्ट प्रचार कि माओ की लाल सेना ही जापानियों से लड़ रही थी और चांग काई शेक कुछ भी नहीं कर रहा था सरासर झूठा प्रचार है। सन 1940 में लाल सेना के कमांडर Peng Dehuai ने माओ के आदेश की अवहेलना करते हुए जापान के खिलाफ संघर्ष किया था। यही एक इकलौता संघर्ष था जो लालसेना ने जापानियों के खिलाफ किया था। माओ का लाल सेना को आदेश था कि "जब जब दुश्मन आगे बढ़े पीछे हटो"। उन्होने इस आदेश का पालन लगभग सभी जगहों में किया। चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सेना ने सभी मुख्य लड़ाईयां लड़ी। लाल सेना मात्र आगे बढ़ रही जापानी सेना द्वारा पीछे छोड़े गए क्षेत्रों पर कब्जा करने का काम करती रही। Chang तथा Halliday के मुताबिक बर्मा में चांग काई शेक के नॅशनलिस्टों ने अपने एक अभियान में जितने जापानियों को out of action किया पूरी लाल सेना ने समूचे आठ साल के इतिहास में इतना नहीं किया था।

जब सन 1937 में जापान की सेना मंचुरिया पहुंची तो स्तालिन ने आदेश जारी किया कि चीनी कम्युनिस्ट नॅशनलिस्ट चांग काई शेक की सेना पर हमले करने बंद कर दे क्योंकि उस वक्त नॅशनलिस्ट जापान की सेना को पीछे धकेल रहे थे। जब जर्मनी तथा उसके साथी देशों ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया तब इस आदेश को 22 जून 1941 के बाद बड़ी शिद्दत से लागु कराया गया। रुस की लालसेना को भारी नुकसान पहुंच रहा था। स्तालिन को डर था कि जापान पूर्व से रुस पर हमला कर कम्युनिस्ट सत्ता को खत्म ना कर दे।

Jung Chang तथा इतिहासकार Jon Halliday के मुताबिक अपने आरंभिक काल से ही माओ सत्ता के लिये लालायित था। उसने सुनिश्चित किया कि उसके सारे प्रतिस्पर्धी या तो गिरफ्तार किये जाये या मारे जाये। माओ के लिये खुद की सत्ता महत्वपूर्ण थी। माओ ने पूरी लाल सेना के साथ धोखा किया जब वह माओ के विरोधियों जैसे कि Chang Kuo-tao इ. के नेतृत्व में थी। बिना स्तालिन की मदद के माओ को पार्टी का नियंत्रण कभी हासिल नहीं हो सकता था।

कम्युनिस्ट सत्ता के लिये अमेरिका की कोशिशें !

अमेरिकन सरकार यहूदी बैंकर्स के दबाव में चांग काई शेक के राष्ट्रवादियों के खिलाफ कम्युनिस्टों को हर तरह से मदद देती थी। क्योंकि चांग काई शेक के राष्ट्रवादी सैनिक जापानी सैनिकों से लड़ रहे थे, अमेरिकी जनता को दिखाने के लिये अमेरिका की अधिकारिक घोषित नीति चांग काई शेक को जापानियों के खिलाफ मदद करने की थी। सन 1943 के आखीर में तेहरान में तथा याल्टा में फरवरी 1945 में युद्धकालीन कॉन्फ्रेंसस् हुई। रुजवेल्ट ने स्तालिन से कहा कि वह जापान के साथ अपना शांति समझौता तोड़ दे और सूदूर पूर्व युद्ध में शामिल हो जाए। स्तालिन ने मांग की कि अमेरिका उसकी बारह लाख पचास हजार पूर्वी सेना को टैंकों, प्लेनों, अन्न तथा हथियारों से सुजजित करे। रुजवेल्ट ने इन मांगों को मंजूर किया और 600 जहाजों में आने वाला सामान सोवियत संघ रवाना किया। चांग काई शेक को अमेरिका के सहयोगी के रूप में पिछले चार सालों में दी गई सामग्री से दूगनी सैन्य सामग्री स्तालिन को हासिल हुई। इसके साथ ही स्तालीन ने मंचुरिया के Dairen तथा Port Arthur पर भी अपने कब्जे की मांग की। इससे स्तालिन को चीन में अपने अडीग पैर जमाने का मौका मिलता था। साथ ही उसे मंचुरिया के रेलमार्गों पर चीन तथा रुस का संयुक्त नियंत्रण प्राप्त हो जाता था। रुजवेल्ट ने चांग काई शेक से बातचित किये बिना ही स्तालीन की मांग मान कर बिना किसी अधिकार के उसने स्तालिन के हवाले दूसरे देश का सार्वभौमिक प्रांत सौंप दिया था। अमेरिकन अध्यक्ष ने यह निर्णय सिनेट तथा अमेरिकन जनता की जानकारी तथा सहमति के बिना ही किया था। अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी Alger Hiss ने किया। Alger Hiss बाद में सोवियत जासूस साबित हुआ था।

चीन के लिये नियुक्त अमेरिकी अधिकारी का नाम Stilwell था। वह जापान के खिलाफ बर्मा में चीनी सेना की कार्रवाई की देखरेख करता था। उसने मांग की कि चांग काई शेक अपनी 30 डिविजनों के साथ बर्मा में जापानियों का प्रतिरोध करें। चांग काई शेक ने यह मांग नामंजूर कर दी क्योंकि ऐसा करने से चीन पर कब्जा करने का जापानियों तथा कम्युनिस्ट दोनों को मौका मिलेगा। Stilwell ने बर्मा अभियान के लिये स्तालिन से प्रार्थना तक नहीं की।

अध्यक्ष रुजवेल्ट ने चांग काई शेक को निर्देश दिया कि वह चीनी सेना को बर्मा भेजने के मामले में Stilwell के हाथों में "निर्विवाद नियंत्रण" प्रदान करे। चांग काई शेक ने इस निर्देश को मानने से इन्कार किया और मांग की कि Stilwell को बदला जाये वरना वह अकेले ही जापानियों का मुकाबला करेगा। चांग काई शेक के मुताबिक Stilwell कम्युनिस्टों के साथ मिलकर राष्ट्रवादी सरकार का तख्ता पलटना चाहता था। रुजवेल्ट को चांग काई शेक की बात माननी पडी।

अध्यक्ष Truman ने George Marshall को चीन के लिये अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। जब वह चीन पहुंचा तब चीन में राष्ट्रवादियों के मुकाबले कम्युनिस्टों की तादाद पांच के मुकाबले एक की थी और वे बडी आसानी से कम्युनिस्टों को पीछे

धकेल रहे थे। लेकिन मार्शल की चीन में जहां भी नियुक्ति हुई उसने कम्युनिस्टों की मदद की तथा नॅशनलिस्टों का भीतराघात किया। जब चांग की राष्ट्रवादी फौज माओ को शिकस्त देने की कगार पर थी, मार्शल ने तीन अवसरों पर हस्तक्षेप कर युद्ध विराम कराया था। इससे हर बार माओ को अपनी ताकत को संगठित करने तथा हथियारों से सुसज्जित होने का मौका मिला। विवाद पैदा कर मार्शल ने आदेश जारी किया कि चांग काई शेक को भेजी जाने वाली हथियारों की खेप को रोक दिया जाये। इसका नतिजा यह हुआ कि कम्युनिस्ट नियंत्रण के क्षेत्रों की तादाद जो मात्र 57 थी बढ़कर 310 तक जा पहुंची। मार्शल के 15 माह की चीन में कारकिर्द का खात्मा जनवरी 1947 को हुआ। उसके अमेरिका वापस लौटने के बाद अध्यक्ष Truman ने उसकी असफलताओं को पुरस्कृत करते हुए उसे राज्य का सचिव बना दिया। तब मार्शल ने नॅशनलिस्टों पर हथियारों का प्रतिबंध लाद दिया जबकि कम्युनिस्टों को सोवियत संघ से लगातार भारी तादाद में हथियारों की पूर्ति होती रही।

जापानी तथा कम्युनिस्टों के हमलों की वजह से राष्ट्रवादी सरकार के कार्यालय तितर बितर हो गए थे। राष्ट्रवादी सरकार को कागजी मुद्रा पर निर्भर करना पड़ा। चीन में मुद्रास्फिती पैदा हुई। हालात को स्थिर करने के लिये चांग काई शेक ने अमेरिका से सोने का ऋण देने की प्रार्थना की। अध्यक्ष रूजवेल्ट ने यह प्रार्थना मान ली लेकिन सोने की खेप को सरकारी कोषागार के सहायक सचिव Harry Dexter White जो सोविएत एजेन्ट था ने जानबूझकर रोका तथा विलंबित किया। परिणामस्वरूप चीनी मुद्रा ध्वस्त हुई और भ्रष्टाचार बढ़ गया।

Dean Acheson ने अमेरिकी काँग्रेस को गुमराह करते हुए बताया कि नॅशनलिस्टों को दो बिलियन से ज्यादा की अमेरिकी डॉलर की मदद दी जा चुकी है। जबकि दी गई मदद गैर-सैनिकीय थी तथा कुछ सामग्री उपयोग के काबिल भी नहीं थी। जब अप्रैल 1948 के चुनावों में चीन एक अहम मुद्दा बना तब अमेरिकी काँग्रेस ने नॅशनलिस्ट सरकार के लिये 125 मिलियन डॉलर की सैनिकीय सहायता की घोषणा की। इसकी पहली खेप सात महिनो बाद मिली। पहला जहाज सन 1948 के आखीर में पहुंचा :- कुल मशिन्सगन में से 480 मशीन गन्स के स्पेअर पार्ट जैसे कि उनकी तिपाही, माउंट इ. नहीं थे। थाम्पसन मशिन गन्स की क्लीप्स या मॅगझीन्स नहीं थे। वहां न ही लोडिंग मशिन्स थी और न ही गोलाबारी के बेल्ट थे। सिर्फ एक हजार लाईट मशिन गन्स में माउंटस् थे तथा 2280 लाईट मशिन गन्स के लिये सिर्फ एक हजार क्लिप्स थी।

अमेरिका के एटम बम ने हीरोशिमा को तबाह-बर्बाद कर दिया। स्तालिन की सेना ने जापान के आत्मसमर्पण के पांच दिन पहले लगभग हार चुके जापान के खिलाफ 9 अगस्त 1945 में हिस्सा लिया। स्तालिन ने अपनी रुसी लाल सेना को आदेश दिया कि वह जापान के आत्मसमर्पण के बाद भी आगे बढ़ती जाये। कई सप्ताह तक सेना आगे बढ़ती रही। ताकि उसके द्वारा कब्जाये हुए क्षेत्र को तथा जापानी हथियारों को माओ के हवाले किया जा सके। रुस की लाल सेना ने चीन, मंगोलिया के अंदरूनी प्रांत तथा मंचुरिया में काबिज की हुई जमीनों के क्षेत्रफल उसने पूर्वी यूरोप में काबिज किये हुए देशों के क्षेत्रफलों से भी बड़े थे। माओ को मिले ये क्षेत्र और हथियारों की

मदद से लाल सेना को चीनी गृह युद्ध में बड़ी बहत मिलने लगी। मार्शल व्दारा लागु किये गए हथियारों के प्रतिबंध की वजह से सन 1948 तक नॅशनलिस्टों को कम्युनिस्टों के हाथों अपनी हार होगी यह स्पष्ट नजर आने लगा। माओ को अमेरिका से भी मदद मिली जबकि चांग काई शेक को सतत रुप से धोखा दिया गया। चांग काई शेक की नॅशनलिस्ट सेना के अफसरों में कम्युनिस्ट एजन्ट भरे पडे थे जिन्होने कदम कदम पर भीतरघात किया। उन्होने गोपनीय सैनिकीय जानकारियां लाल सेना को पहुंचाई, उन्होने अपने कदमों से राष्ट्रवादी सेना का कल्लेआम कराया या उन्हे लाल सेना के आगे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। सन 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई। चांग काई शेक अपने 20 लाख समर्थकों के साथ फार्मोसा (आज का तायवान) भाग गया। वहां उसने अपनी राष्ट्रवादी सरकार कायम की। 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने बिर्जींग के तियानानमेन चौक (Tiananmen Square) में पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना के कायम होने की घोषणा की।

पश्चिमी देशों के यहूदिनियंत्रित मीडिया को तथा इतिहासकारों को माओ की लाल चीनी क्रांति के उगम में यहूदी बैंकर्स की भूमिका पर लिखने से प्रतिबंधित किया गया। इस पर पर्दा डालने के लिये माओ को गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ के रुप में प्रचारित किया गया। माओ की सफल गुरिल्ला रणनीति को लेकर झुठा जनवादी साहित्य तैयार किया गया।

चीनी कम्युनिस्ट सरकार के नियंत्रक (Handlers) !

Israel Epstein तथा Sidney Shapiro चीन की कम्युनिस्ट सरकार के treasury (money) तथा media (propaganda) जैसे दो महत्वपूर्ण विभागों को नियंत्रित करते थे। Virginius Frank Coe सन 1950 में चीन आया। माओ सभी आर्थिक मामलो में इसी विदेशी जासूस पर निर्भर था। सन 1958 में वह चीन में पूर्णकालीन रुप से स्थायी हो गया। सन 1950 में यहूदी जासूस Solomon Adler चीन पहुंचा। वह चीन के विदेश विभाग में चीनी नेतृत्व के सलाहकार के रुप में कार्य करने लगा। Solomon Adler सन 1944 में Chungking में ट्रेजरी अधिकारी के रुप में कार्यरत था। उसने अनुवादक, आर्थिक सलाहकार व संभवतः Central External Liaison Department तथा चीनी गुप्तचर संस्था के साथ कार्य किया। Israel Epstein चीन में बहुत ही महत्वपूर्ण appropriations विभाग का मंत्री बना। एक अन्य यहूदी Robert Lawrence Kuhn जो निवेशक बैंकर था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में "consultant" बन गया। Sidney Rittenberg चीन में सन 1944 से 1979 तक रहा। उसने माओ, मिलिटरी नेता Zhu De, Zhou Enlai, तथा अन्य बडे चीनी नेताओं के साथ युद्ध के दौरान काम किया। वह इन केन्द्रिय नेताओं के साथ Yanan में रहा। माओ के शासन में वह चीन के विदेश गुप्तचर विभाग का प्रमुख रहा। Sidney Shapiro पॉलित-ब्युरो का सदस्य था।

चीनी जनता का क्रूर दमन !

सत्ता संभालने के बाद माओ का पहला काम कथित जमीन सुधार तथा प्रतिक्रांतिकारियों का दमन करना था। आम लोगों की उपस्थिति में सामुहिक रूप से कथित प्रतिक्रांतिकारियों की हत्या की जाती थी। पूर्व कोमिंतांग के अफसरों, व्यापारी, पश्चिमी देशों की कंपनियों में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी, बुद्धिजीवी, ऐसे लोग जिनकी निष्ठा पर संदेह है तथा बड़ी तादाद में गांव के जमींदार इ. के जनसंहार किये जाते थे। सन 1976 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के आकलन के मुताबिक माओ के कथित जमीन सुधार अभियान में दस लाख लोगों को तथा प्रतिक्रांतिकारियों के खिलाफ चलाये गए अभियानों में आठ लाख लोगों को मारा गया। माओ ने खुद दावा किया कि सन 1949 से 1953 के दौरान सात लाख लोग मारे गए। माओ ने इन हत्याओं का यह कह कर समर्थन किया कि सत्ता कायम रखने के लिये ये हत्याएं जरूरी थीं। इसके अलावा कम से कम 15 लाख लोग लेबर कॅम्पों में कठोर परिश्रम करने भेज दिये गए।

कथित लंबी छलांग (The Great Leap Forward)

सन 1958 में माओ ने दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की। इस योजना को लंबी छलांग करार दिया गया। माओ का मकसद खेती पर पूरा नियंत्रण कायम कर अनाज के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण पर पूरा नियंत्रण कायम करना था। इस योजना के तहत किसानों की जमीन को सामुहिक खेती में बदला गया जिसमें सब किसानों की हैसियत मात्र कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों जैसी होती है तथा सारी उपज पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार यह तय करती है कि किसान से मजदूर बनाये गये लोगों को क्या मजदूरी दी जाये। सरकार उत्पादीत अनाज को विदेशों में बेचकर राज्य के खजाने को बढ़ा सकती थी। यहूदी Coe को इस योजना का जनक माना जाता है। गाय, भैंसे, घोड़े, गधे इ. सारे जानवरों को तथा सारे खेतिहर औजार इ. सामुहिक यानी सरकार को नियंत्रित करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की मिल्कियत के माने गये। सभी किस्म के निजी उत्पाद पर पाबंदी आयद कर दी गई। लंबी छलांग के तहत माओ ने नीचे दिये गए कई अवैज्ञानिक तथा साबित नही किये गये तरिकों को लागू किया।

बीजों को बहुत गहरा बोना :- माओ ने आदेश दिया कि बीजों को जमीन में ज्यादा गहराई में बोया जाये जिससे बड़ी जड़ों वाले पौधों से ज्यादा फसल मिलेगी। किसानों से कहा गया कि वे बीज करिब करीब बोये क्योंकि एक ही जाति के पौधे एक दूसरे से प्रतियोगिता नही करेंगे।

गोरैया (Sparrows) संहार अभियान :- इस अभियान को सन 1958 से 1962 के दौरान चलाया गया। आदेश दिया गया कि चीन के किसान अपने खेतों में बर्तन इ. जोर जोर से बजाकर गोरैया को भगा दे तथा दुंदुं दुंदुंकर अंडों-बच्चों सहित उनके घोंसलों को नष्ट कर दे। अप्रैल 1960 तक चीन की राष्ट्रीय अकादमी ऑफ सायंस ने पाया कि गोरैया अनाज से ज्यादा इल्लियों, किडों इ. को खाती है। जब इस योजना को बंद किया गया तबतक बहुत देर हो चुकि थी क्योंकि गोरैया नही होने से कीडों-इल्लियों की आबादी बेतहाशा बढ़ गई तथा सारे चीन में उन्होने फसलों की तबाही मचा दी।

बीज जमीन में गहरे बोन से पैदावार पर प्रतिकूल असर पडा था। हालत और ज्यादा बदतर हो गई और अकाल विकराल हो गया। यह अनुमान लगाया गया है कि सन 1959 से सन 1961 के दौरान तीन लाख अस्सी हजार लोग भूख से मर गये।

घर के पिछवाडों में फौलाद का उत्पाद :- अगस्त 1958 में तय हुआ कि लोगों के घरों के पिछवाडों में फौलाद की भट्टियां लगवाकर फौलाद के सालाना उत्पाद को दुगुना किया जाये। भट्टियाँ जलाने के लिये बड़ी तादाद में पेड काटे गए। पुराने बर्तन तथा दिगर धातु की चीजों को इन भट्टियों में गलाया गया ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके। खेतिहर, कारखानों के मजदूरों, स्कूलों के बच्चों, अस्पतालों के कुछ कर्मचारियों इ. को लकड़ी तथा लोहे इ. की वस्तुओं को इकट्टा करने के कामों में लगाये जाने से खेती, कारखाने इ. के काम प्रभावित हुए। बिना अनुभव तथा बिना metallurgy के ज्ञान के जो फौलाद ? के ढेले तैयार हुए उनकी कोई खास उपयोगिता नहीं थी।

बिना विशेषज्ञों के प्रकल्पों का निर्माण :- बिना प्रशिक्षित इंजिनियरों के कई सिंचाई इ. प्रकल्प बनाये गए क्योंकि माओ की नजर में इंजिनियर बुर्जुआ थे। नहरों, बांधों इ. प्रकल्पों में लाखों लोगों को तथा कैदियों को जबरन काम पर लगाया गया। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कराई गई जिससे कईयों की मौतें हुई। बिना विशेषज्ञों के दोषपूर्ण ढंग से बने कई प्रकल्प बेकार साबित हुए।

लंबी छलांग का परिणाम !

अपने वरिष्ठ अधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त करने तथा उनके रोष से बचने के लिये पार्टी के हर स्तर ने अनाज के उत्पादन की तादाद को बढा चढा कर पेश किया। इसलिये राज्य के लिये उस तादाद में अनाज इकट्टा करने का आदेश दिया गया। सन 1958 से 1960 के दौरान चीन बड़ी तादाद में चावल इ. (grains) का निर्यात करता था ताकि दुनियां को माओ की सामुहिक खेती इ. की योजनाओं की कामयाबी पर मुहर लगाई जा सके। जबकि देश में अन्न की भारी कमी थी। फौलाद के उत्पाद तथा सिंचाई इ. के प्रकल्पों की वजह से खेती में काम करने वाले लोगों की तादाद कम हो गई थी जिससे अनाज की पैदावार पर बुरा असर पडा था। कुछ हिस्सों में सुखा पडने तथा कुछ हिस्सों में बाढ आने से हालात और भी बदतर हो गए। ग्रामिणों के पास खाने के लिये अनाज नहीं था। अकाल से सन 1959-1962 के दौरान मरने वालों की तादाद एक करोड तक पहुंच गई। बाद के वर्षों में बच्चों की कुपोषण की वजह से सन 1962 में लंबी छलांग के खत्म होने के बाद भी मौतें होती रही। Banister के मुताबिक सन 1958-61 के दौरान सरकारी जन्म मृत्यु रिकार्ड के मुताबिक पंद्रह मिलियन मौतें ज्यादा हुई थी। इसे ध्यान में रखकर कि अकाल के दौरान मरने वालों की सूचना देने में कोताही बरती जाती है यह आंकडा 30 मिलियन के आसपास का हो सकता था। Hu Yaobang के मुताबिक अधिकारिक आंकडे 20 मिलियन मौतें है। दूसरे सुत्रों ने यह आंकडे 20 मिलियन से लेकर 72 मिलियन तक बताये है।

सौ तरह के फूल खिलने दो अभियान !

सन 1959 की जुलाई-अगस्त में Lushan में आयोजित पार्टी कॉन्फ्रेंस में कई नेताओं ने कहा कि लंबी छलांग अभियान नाकामयाब था। इन नेताओं में सबसे ज्यादा मुखर नेता Peng Dehuai था जो रक्षा मंत्री तथा कोरियन युद्ध का जनरल था। माओ ने Peng Dehuai तथा उसके समर्थकों के खिलाफ निष्काषण अभियान चलाया। लंबी छलांग योजना को सन 1962 में बंद करना पड़ा। लंबी छलांग योजना की नाकामी से माओ की प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा। Liu Shaoqi तथा Deng Xiaoping जैसे मध्यम स्तर के नेता ज्यादा ताकतवर बन कर उभरे। पार्टी का अध्यक्ष Liu Shaoqi को बनाया गया। माओ पार्टी चेअरमैन के पद पर कायम रहने में कामयाब रहा। माओ ने सौ तरह के फूल खिलने दो अभियान का आगाज किया। माओ ने लोगों से कहा कि वे खुलकर अपनी राय जाहिर करें कि चीन पर किस तरह से शासन किया जाये। जैसे ही लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी घोषित की गई उदारवादी तथा बुद्धिजीवियों ने कम्युनिस्ट पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने शुरु किये। इस आलोचना को जानबूझकर सहन किया गया जिससे बाकी लोग और भी खुलकर बोलने लगे। माओ को यह जानकर हैरानी हुई तथा आघात लगा कि लोग उसकी कड़ी आलोचना तथा उसके नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। कुछ महिनों के बाद ही माओ ने आलोचना करने वालों के खिलाफ दमनचक्र शुरु किया। माओ ने दक्षिणपंथियों के खिलाफ क्रूर अभियान चलाया जिसकी अगुआई की जिम्मेदारी Deng Xiaoping के हाथों दी गई। इस अभियान में कई मिलियन लोगों को मार डाला गया। कम से कम पांच लाख लोगों को उनके पदों से हटाया गया। उनमें से कईयों को जबरन श्रम कराने कथित सुधार कॅम्पों में डाला गया। Jung Chang के मुताबिक सौ तरह के फूल खिलने दो अभियान का मूल मकसद पार्टी नेतृत्व के विरोधियों की पहचान करना था। यह एक कूटनीतिक चाल थी जिसके तहत शासन के विरोधियों, खासकर बुद्धिजीवियों को तथा पार्टी के निचले स्तरों के विरोधी कार्यकर्ताओं की पहचान कर उनसे निपटा गया।

कथित सांस्कृतिक क्रांति !

कम्युनिस्ट पार्टी में Liu Shaoqi तथा Deng Xiaoping के बढ़ते प्रभाव से माओ चिन्तित हो उठा। इसलिये माओ ने सन 1966 में कथित सांस्कृतिक क्रांति का आगाज किया। यह घोषित किया गया कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को उदारवादी बुर्जआ जैसे वर्गशत्रुओं से खतरा है। इनके प्रभाव को खत्म करने के लिये सांस्कृतिक क्रांति करना जरूरी है। इस छलावे से माओ को बिना किसी के हस्तक्षेप के कथित सांस्कृतिक क्रांति को जारी करने का मौका मिला। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की बागडोर सीधे रेडगार्ड के नवयुवकों पर सौंपी जिन्होंने अपने खुद के न्यायालय (tribunals) कायम किये। स्कूल बंद किये गये और युवा बुद्धिजीवियों को कहा गया कि वे गांवों का रुख करें।

सन 1966 के अक्टूबर में माओ के उध्दहरण वाली किताब बड़ी तादाद में छपी गई जिसे लाल किताब के नाम से प्रसिध्द किया गया। पार्टी के सदस्यों को हमेशा

इस किताब को अपने साथ रखने का आदेश दिया गया। माओ के चित्र के बड़े बड़े होर्डिंग्स जगह जगह लगाये गए। माओ के चित्र कार्यकर्ताओं के घरों में, सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों तथा अस्पतालों यहां तक कि दूकानों तक में लगाये गए। लोग खुद को प्रतिक्रांतिकारी करार दिये जाने के डर से अपनी जगहों में ये चित्र लगाये जाने का विरोध नहीं कर सके। गीतों में माओ की महानता प्रचारित की गई। माओ पर बनाए गए बच्चों के गीत स्कूलों में बच्चों को रटाये गए। “माओ दस हजार साल जिंदा रहे” (Long Live Chairman Mao for ten thousand years) यह घोष-वाक्य हर जगह गाया, बजाया और लिखा गया। इसके पहले “दस हजार साल जिंदा रहे” का घोष-वाक्य सिर्फ चीन के सम्राट के लिये ही सुरक्षित था। माओ की सांस्कृतिक क्रांति ने चीन की सांस्कृतिक विरासतों को ध्वस्त करना शुरू किया। मशहूर दार्शनिक Chen Yuen समेत चीन के लोगों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया। समूचे चीन में आर्थिक तथा सामाजिक अराजकता का माहौल पैदा हुआ।

सन 1965 के बाद से Sidney Rittenberg, Solomon Adler इ. यहूदियों ने एक तरह से चीन के रेडियो इंटरनेशनल पर कब्जा कर लिया था। प्रचार प्रसार की बागडोर उनके हाथों में थी। सांस्कृतिक क्रांति के संबंध में पिपल्स डेली में संपादकीय लिखकर लोगों को सांस्कृतिक क्रांति के लिये उकसाया गया। Israel Epstein चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। सांस्कृतिक क्रांति के लिये वही जिम्मेदार था। उसी ने माओ की लाल किताब भी लिखी थी।

इसी दौरान माओ ने Lin Biao को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर Lin Biao से गठजोड़ कायम किया ताकि माओ अपने राजनीतिक दूश्मनों से निपट सके। लीन की मदद से माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर अपने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वीयों के खिलाफ कार्रवाईयां की। सन 1971 आते तक लिन की सेना इ. पर भारी पकड़ देखकर माओ उसके प्रति भी आशंकित हो उठा। माओ को लगा कि लिन उसका तख्ता पलट कर खुद चीन का शासक बनना चाहता है। Lin Biao को अपनी गिरफ्तारी का अहसास हो गया था इसलिये चीन से भागते वक्त उसके प्लेन की मंगोलिया के हवाई क्षेत्र में दूर्घटना हो गई जिसमें वह मारा गया। कईयों का मानना है कि यह दूध टिना कराई गई। उसे मरणोपरांत पार्टी से निष्काषित किया गया। चीन के अधिकारिक इतिहास के मुताबिक सांस्कृतिक क्रांति का अंत माओ की सन 1976 में हुई मौत के बाद ही हुआ था।

नई यहूदी वैश्वीक व्यवस्था !

अमेरिकी अध्यक्ष केनेडी की हत्या !

सन 1963 में 4 जून को अमेरिकी अध्यक्ष केनेडी ने Executive Order No. 11110 के जरिये सरकार को अपनी मुद्रा जारी करने का हक दिया। यह माना जाता है कि देढ़ बिलियन डॉलर की मुद्रा छापकर चलन में उतारी गई। इससे फेडरल रिजर्व की सरकार पर पकड़ कमजोर हुई। ठिक पांच महिने बाद John F. Kennedy की Dallas Texas में हत्या कर दी गई। षडयंत्रपूर्ण तरीकों से सारी मुद्रा को वापस लाकर नष्ट किया गया।

वैश्विकरण (Globalization) का असली मतलब !

वैश्विकरण शब्द एक छलावा मात्र है। वह विश्व के सारे देशों में मुक्त रूप से पूंजी के आने जाने और मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करने; तीसरे देशों के मुल्कों से कर्ज के सूद को लगातार वसूलने; तीसरे देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाली चीजों के व्यापार में मंदी लाने; तीसरे देशों ने अपने संवेदनशील चीजों के व्यापार के संरक्षण के लिये बनाये गये आयात शुल्क नियमों (tariff) को हटाने; विदेशी निवेश पर लगे सारे प्रतिबंध हटाने; बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तीसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की अनुमति देने; देश का धन उत्पादक, विकास, कल्याण इ. जनहितकारी गतिविधियों पर खर्च करने से रोकने; जीवनावश्यक चीजों तथा सेवाओं जैसे कि बिजली, इंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, अनाज इ. की कीमत में तेजी से बढ़ाव कराने; कमजोर वर्ग को दी जाने वाली सबसिडी को खत्म करने; कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को खत्म करने; सामाजिक उत्पादों में कर्मचारियों की तादाद कम करने; तिसरी दुनिया के देशों के घरेलु उद्योगों को ध्वस्त करने; छोटे उद्योगों को तबाह-बर्बाद करने; अनाज की सुरक्षा ध्वस्त करने; अधिकतम जमीन धारण करने की सीमा को खत्म करने; आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर उनकी जमीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने; सभी आर्थिक गतिविधियों का, बहुमूल्य उद्योग तथा नैसर्गिक संसाधनों का निजीकरण करने; किसानों को खतरनाक जी.एम.ओ. बीजों पर निर्भर कराने; श्रम को खतरनाक कामों को गरीब देशों के मजदूरों से कम मजदूरी पर कराने; औरतों के श्रम, शरीर इ. का शोषण करने; वेश्यावृत्ति, जुए, शराब, पोर्न, इ. व्यवसायों को फलने फूलने देने; विकसित देशों के खतरनाक कचरे को गरीब देशों में फेंकने की व्यवस्था है। (<http://www.rupe-india.org/35/globalisation.html> Introduction 'Globalisation')

ब्राजिल के लिये बने तथा उजागर हुए (leaked out) विश्व बैंक के दस्तावेज "Master Plan for Brazil" में निम्नलिखित पांच अनिवार्यताएं लिखी गई हैं :- ब्राजिल अपने कर्मचारियों की तनखाह तथा अन्य लाभ कम करे, पेन्शन्स कम करे, काम के घंटे बढ़ाये, नौकरी की सुरक्षा (Job Stability) कम करे तथा रोजगार कम

करे।

डॉलर का संकट !

सन 1970 में फ्रांस ने अमेरिका को सूचित किया कि वे Bretton Woods में हुए समझौते के मुताबिक उनके पास जमा डॉलर को सोने से बदलना चाहते हैं। इतना सोना अमेरिका के पास नहीं था। इसलिये 15 अगस्त 1971 को अध्यक्ष Richard Nixon ने अस्थायी तौर पर डॉलर की सोने में रूपांतरनियता को मुलतवी कर दिया। तब कई देशों की मुद्राओं ने खुद को डॉलर से असंबंधित करना शुरू किया। विश्व के देश अमेरिका को दिये गए कर्ज के प्रति आशंकित हो उठे। वे अमेरिका को बिना किसी जमानत (collateral) के और ज्यादा कर्ज देने में आनाकानी करने लगे। इसलिये अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन ने पर्यावरण आन्दोलन शुरू किया। इसके अंतर्गत "wilderness zones", "Road less areas", "Heritage rivers", "Wetlands" इ. के नाम पर विशाल सरकारी जमीनों में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया। इसका असली मकसद इन जमीनों को तथा उसके भीतर की खनीज संपदा को कर्ज की अमानत के रूप में गिरवी रखना था। इस जमीन का कुल क्षेत्रफल अमेरिका की कुल जमीन का पच्चीस फीसदी है। अमेरिका के उद्योगों में लाखों नौकरियाँ खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका के मजदूरों को कम तनखाह मिलने लगी क्योंकि उनके मुकाबले चीन में मजदूरी बहुत सस्ती थी। बेरोजगारी रिकार्ड स्तर पर पहुंची है। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने मुख्यालय दूसरे देशों में स्थानांतरित कर रही हैं। अमेरिका एक ऐसा देश बन चुका है जो हर चीज का उपभोग लेता है जबकि वह बहुत कम उत्पादन करता है। उसका सारा दारोमदार डॉलर पर है जिसे अंतराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम के रूप में दुनिया के देशों पर थोपा गया है।

पेट्रो-डॉलर !

अमेरिका ने डॉलर की घटती मांग से निपटने लिये मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों को प्रस्ताव दिया कि अगर वे अपने तेल को सिर्फ डॉलर में बेचेंगे तो वह उनके देश पर होने वाले किसी भी बाहरी आक्रमण से उनकी रक्षा करेगा। इस संकल्पना को पेट्रो-डॉलर नाम दिया गया है। अमेरिका की पैदावार कम होने लगी। जी.एम.ओ. जैसे घातक प्रयोगों से कोई अमेरिकी कृषि पैदावार लेना नहीं चाहता था। अमेरिका से जमीन के सिवा और कुछ हासिल करने में दिक्कत होने लगी तब समस्या पैदा हुई कि वे डॉलर का क्या करे। यूरोप की कारें तथा विमान अमेरिकी कारों तथा विमानों से न सिर्फ बेहतर थे बल्कि सस्ते भी थे। इजरायल का मूस्लिम देशों के प्रति आक्रमक रवैया और यहूदी बैंकर्स के दबाव में अमेरिका द्वारा उसे आंखें मूंद कर किया जाने वाला समर्थन उन्हे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि इजरायल के खिलाफ अमेरिका उनकी रक्षा कैसे कर सकता है ? इसलिये तेल उत्पादक देश अपना तेल डॉलर की बजाय अन्य मुद्राओं में बेचना चाहते थे।

इराक ने सन 2000 में अपना तेल युरो में बेचना चाहा। यही वजह थी कि अमेरिका ने आक्रमण कर सद्दाम हुसैन को मार डाला और डॉलर स्थापित किया। लिबिया में Muammar Gaddafi की सरकार की मित्कियत का केन्द्रिय बैंक था। उसकी मुद्रा दीनार, सोने पर आधारित थी। गद्दाफी ने ऐलान किया कि उसके देश का तेल सिर्फ दिनार के बदले में ही बिक्री के लिये उपलब्ध है। दूसरे अफ्रीकी देश यह देखकर कि दिनार तथा युरो की मांग बढ़ रही है वे भी दिनार में लेनदेन करने लगे। इससे डॉलर के वर्चस्व को खतरा पैदा हुआ। इसलिये अमेरिका ने लिबिया पर हमला किया, क्रूरता से Qaddafi का कत्ल किया, लिबिया में एक निजी केन्द्रिय बैंक कायम किया तथा दीनार की जगह डॉलर में लेनदेन कायम किया। इसी वजह से अमेरिका ने सीरिया इ. देशों को गृहयुद्ध की आग में धकेला है। अमेरिका का मकसद ईरान को अपने तेल को सिर्फ डॉलर में बेचने के लिये मजबूर करना तथा निजी केन्द्रिय बैंक को कबूल करवाना है।

युरोपियन युनियन !

सन 1993 में "युरोपियन युनियन कमीशन" का गठन किया गया। युरोपियन युनियन की पार्लियामेंट मात्र एक सलाह देने वाली संस्था है तथा उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सन 1993 में 1 नवंबर को युरोपियन युनियन का गठन किया गया। तब युरोपियन युनियन कमिशन के चेअरमैन Jacques Delors के अधिकार उसके सदस्य देशों की सरकारों के अधिकारों से ज्यादा थे। (Under the sign of scorpion by Juri Lina) युरोपियन युनियन युक्रेन सरकार को युरोपियन युनियन में विलिन करने की कोशिशें कर रही थी ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को निजी मित्कियत के केन्द्रिय बैंक के साथ जोड़ी जा सके। युक्रेन की सरकार युरोपियन युनियन में विलिन सायप्रस, ग्रीस, स्पेन तथा इटली इ. देशों पर युरोपियन केन्द्रिय बैंक के वर्चस्व से आशंकित थी। तब रूस ने युक्रेन के सामने बेहतर विकल्प रखा जिसे युक्रेन ने मंजूर कर लिया। तब से युक्रेन में CANVAS तथा USAID जैसे संगठनों को हर तरह की मदद पहुंचाकर युक्रेन में गृहयुद्ध के हालात पैदा किये गए। आम लोगों पर गोलियां चलवाकर उसका दोष तात्कालीन अध्यक्ष Yanukovich पर मढ़ा गया। युरोपियन युनियन के Catherine Ashton तथा इस्टोनिया के विदेश मंत्री Urmas Paet के बीच हुए वार्तालाप उजागर हुए जिससे स्पष्ट हो गया कि लोगों पर गोलियां चलाने वाले युक्रेन सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे षडयंत्रकारियों के लोग थे। Urmas Paet ने इन संभाषणों की सत्यता को कबूल किया था। बैंकर्स का यह पुराना तरिका है। यह पुरानी तिकडम थी जिसका इस्तेमाल अमेरिका कई सरकारों के तख्ते पलटने के लिये करता रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही अमेरिकी सरकार ने 56 देशों की सत्ता पलटने की कोशिशें की जिनमें से 25 देशों में वह कामयाब हुआ है। मकसद इन देशों की संपत्ति को बैंकर्स के हाथों में पहुंचाना था।

संस्कृतिक-संघर्ष : तृतीय विश्वयुद्ध का कार्यक्रम !

कथित सांस्कृतिक संघर्ष (clash of civilizations) बैंकिंग व्यवस्थाओं के बीच का संघर्ष है। मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने की वजह यह है कि पूरातन ईसाईयों की तरह ही इस्लाम ने भी सूदखोरी को प्रतिबंधित किया है। इसलिये वे व्याज पर दी जाने वाली मुद्रा का विरोध करते हैं। वेनेजुला के भूमिगत तेल भंडार जो सउदी अरेबिया के तेल भंडारों से भी बड़े हैं, तथा वेनेजुला की सोने की खदानें बैंकर्स को ललचाती हैं। इसलिये वेनेजुला भी बैंकर्स के निशाने पर है।

BRICS इ. का गठन !

Brazil, Russia, India, China, तथा South Africa ने मिल कर BRICS नामक आर्थिक व्यवस्था का गठन किया है। लगभग 80 देश BRICS के तहत लेनदेन करने के लिये राजी हैं। अमेरिका के रुस और चीन के खिलाफ चल रहे आर्थिक युद्ध के बावजूद उनकी रुबल तथा युआन मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा बैंकिंग के लिये डॉलर से ज्यादा आकर्षक मानी जाती है। इसलिये अमेरिका युक्रेन में संकट पैदा कर रुस के साथ युद्ध के हालात पैदा कर रहा है। चीन का HSBC बैंक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहांतक कि अमेरिका के परंपरागत सहयोगी देश भी इस बैंक को सहयोग करने के लिये आगे बढ़ रहे हैं। शंघाई स्थित Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) में 50 देश शामिल हैं तथा शामिल होने वाले देशों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसलिये अमेरिका अन्य देशों को चीन से युद्ध के लिये उकसा रहा है।

चीन नई यहूदी वैश्वीक व्यवस्था का एजेन्ट है !

सोवियत संघ की तरह ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीष नेतृत्व में यहूदियों की बहुतायत है। अंतर्राष्ट्रीय यहूदियों ने योजनाबद्ध तरिकों से चीन को मुख्य आर्थिक तथा सामरिक ताकत के रूप में उभारा है। चीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पश्चिमी तकनीक तथा अन्य सभी सहायता हासिल होती रही है। इसलिये चीन की असली बागडोर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में है। चीन का लगातार बढ़ता कर्जा साबित करता है कि यहूदी बैंकर्स का शिकंजा चीन पर लगातार कसते जा रहा है। चीन की सरकार यहूदी बैंकर्स के एजेन्ट के रूप में काम करने पर मजबूर है। चीनी मजदूरों से बहुत कम मजदूरी पर ज्यादा काम कराया जाता है। इसलिये अमेरिका की हजारों फॅक्टरियाँ चीन में स्थानांतरित हो चुकी हैं। चीन का कथित विकास मात्र बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों का विकास है।

चीन में रोथ्सचिल्ड की उपस्थिति सन 1838 से है। चीन का नया Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) भी रोथ्सचिल्ड नियंत्रित बैंक है जिसका मकसद दुनियां के बचे हुए देशों को अलग मुखौटे से अपने नियंत्रण में लाना है। इसी वजह से IMF, the World Bank तथा the Asian Development Bank ने चीन के नेतृत्व में बने इस बैंक को अपना समर्थन दिया है। बिजिंग पूरी तरह से रोथ्सचिल्ड के वैश्वीक कार्यक्रम को लागू कर रहा है। बिजिंग के नेतृत्व में बना

यह बैंक रोथ्सचिल्ड की “नई वैश्वीक व्यवस्था” के अनुरूप है। इसलिये विश्वबैंक तथा AIIB एक दूसरे से भागिदारी करने के लिये तैयार हुए हैं। अधिकारिक विश्व बैंक तथा AIIB की संयुक्त आर्थिक सहायता रुपरेखा के मुताबिक वे मिलकर AIIB-World Bank के प्रकल्पों को चालना देंगे। बहुत जल्द समूचा विश्व रोथ्सचिल्ड के आर्थिक साम्राज्य की गुलामी में आ जाएगा।

तलमुद के मुताबिक यहूदियों का राजा अनिवार्य रूप से इजरायल से सारी दुनियाँ पर हुकुमत करेगा। तोराह के कार्यक्रम को लागु करने के लिये यहूदी कई शताब्दियों से लगातार कार्यरत रहे हैं। रोथ्सचिल्ड इसमें पूरा पूरा विश्वास करते हैं और इसे लाने के लिये समर्पित है।

रोथ्सचिल्ड ने इजरायल का निर्माण करवाया ताकि वहां से सारी दुनियाँ पर राज किया जा सके। यहूदियों की धार्मिक किताब तोराह (Torah) के मुताबिक वैश्वीक पैमाने पर गैरयहूदियों का जनसंहार होगा। उनमें से सिर्फ चंद लोगों को ही यहूदियों की गुलामी करने के लिये बक्शा जाएगा। यही यहूदी धर्म का मूल उद्देश्य है। यहूदियों द्वारा मनाये जाने वाले सारे त्योहार जैसे कि Passover, Purim, Hanukkah दुश्मनों पर पाई गई जीत और उनके जनसंहारों से संबंधित है। आधुनिक जनसंहारों के कई उदाहरण हैं :- अमेरिकी तथा ब्रिटीश युध्दपोतों ने sadistically जर्मनी के शहर Dresden पर 3300 टन आग फैलाने वाले (incendiary) बम बरसाये जिसमें 3-5 लाख लोग जलने से मर गए। दि. 9-10 मार्च 1945 को अमेरिका के जहाजों ने जापान के टोकियो शहर पर आग फैलाने वाले बम तथा उच्च शक्ति के बम बरसाये जिससे 83793 लोगों की मौते हुई। जब जापान आत्मसमर्पण के कगार पर था तब जानबूझकर अमेरिका ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर आण्विक बम बरसाये और इन शहरों को राख कर दिया। इराक की जनता की आर्थिक घेराबंदी कर लाखों बच्चों तथा बिमारों को दवा इ. जरूरी चीजों का अभाव पैदा कर मार डाला। विएतनाम, अफगानीस्तान तथा अन्य देशों में कई मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा है। उनपर रासायनिक बम बरसाये हैं। यह चंद उदाहरण मात्र हैं। यहूदी बैंकर्स के हित में लडने के लिये कर्ज में दबकर गुलाम बन चुके देशों की सेनाएं मौजूद हैं। उनके पास CIA, Mossad इ. गुप्तचर संस्थाएं हैं तथा वे लगभग सभी देशों की गुप्तचर संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं ताकि वे रुकावट बनने वाले हर किसी को कुचल सके।

अध्याय 10

भारत तथा अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां !

बैंकर्स के हितों की रक्षा के लिये दुनियाँ भर की कम्युनिस्ट पार्टियों की जुमाइंदगी उन देशों के ताकतवर कथित उच्च जाति-वंशों के हाथों में जानबूझकर दी गई है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों का नेतृत्व आर्य-ब्राह्मणों के हाथों में दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टियों का नेतृत्व शोषित जनता के हाथों में ना आये इसलिये नीचे दिये गए नियमों पर सख्ती से अमल किया जाता है :-

1) तानाशाही का नियम :- इतिहास में तानाशाही हमेशा से ही चंद ताकतवर लोगों के हाथों में रही है। क्योंकि तानाशाही हमेशा से ही स्वतंत्रता की विरोधी है, तानाशाही में लोकतंत्र और स्वतंत्रता कभी कायम नहीं हो सकती। आम मेहनतकश इन्सान जो कम शिक्षित है, आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, तथा जो आठ से ज्यादा घंटे काम करता है, मामूली नेता भी नहीं बन सकता। इसलिये "मजदूरों की तानाशाही" का मतलब उच्च जाति-वंश के संपन्न पार्टी नेताओं की तानाशाही है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों का नेतृत्व नीचे से लेकर उच्च स्तरों पर आर्य-ब्राह्मण जातियों का है। इसलिये सर्वहारा वर्ग का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है और हिफाजत उच्च जाति-वंशों के हितों की की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टियों का इतिहास इस बात का साक्षी है।

2) केन्द्रिय-लोकतंत्र (Central-Democracy) का नियम :- यह नियम अपने आप में एक विरोधाभास है क्योंकि लोकतंत्र और केन्द्रियता कभी एक साथ नहीं रह सकते। केन्द्रियता तानाशाही का रूप है। इस सिद्धान्त के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को अपने वरिष्ठ नेताओं के आदेशों पर अनिवार्य रूप से अमल करना होता है। "विकेन्द्रिकरण के सिद्धान्त" को लागु कर जहां सर्वहारा सीधे तौर से अपने निर्णयों को अमल में लाने की जिम्मेदारी दिये गए व्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं, संगठन का नेतृत्व आम लोगों के हाथों में लाया जा सकता है।

3) आर्थिक घटकों की अनिवार्यता का नियम :- कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा समाज में होने वाले किसी भी बदलाव के लिये आर्थिक घटकों को अंतिम मानने से यह सुनिश्चित हुआ है कि बहुजन समाज अपने उपर होने वाले जाति, धर्म, वंश रंग, राष्ट्रीयता, भाषा, प्रांत इ. से होने वाले अन्यायों के खिलाफ कोई आवाज ही न उठा सके। कम्युनिस्ट पार्टियों के ब्राह्मणवादी नेतृत्व ने इन सभी जुल्मों के खिलाफ उठने वाली आवाज का विरोध तथा भीतराघात किया है। सभी कम्युनिस्ट पार्टियाँ फुले, शाहु, अय्यंकाली, अम्बेडकर इ. को बुर्जआ विचारधारावाले इ. कहकर तथा उनका संघर्ष मार्क्स के सिद्धान्तों के मुताबिक नहीं था कहकर उन्हें सिर से नकारते रहे हैं।

4) कम्युनिज्म को लुभावना चारा बनाना :- तथाकथित कम्युनिज्म मजदूरों को यहूदी बैंकर्स के कांटे में फँसाने के लिये लगाया गया आकर्षक चारा मात्र है। मार्क्स की समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था बैंकर्स के हित में दूनियाँ के इतिहास की सबसे क्रूरतम शोषण-व्यवस्था है। इसलिये वे कम्युनिज्म को आकर्षक लुभावने चारे के रूप में पेश करते रहे हैं, ताकि अंदर का जानलेवा कांटा छुपा रहे।

5) पार्टी का संकीर्ण पाखंडियों में रूपांतरण करना :- कम्युनिस्ट पार्टियों के उच्चवर्णीय नेतृत्व ने खुद की तरह ही अपने सदस्यों को भी संकीर्ण तथा पाखंडी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे खुद को प्रगतिशील प्रचारित करते हैं लेकिन वे सबसे बड़े संकीर्णतावादी हैं। वे मार्क्सवादी साहित्य के अलावा अन्य साहित्य को अवैज्ञानिक,

बुर्जुआ इ. करार देकर उन्होने खुद की हालत बंद कुए में पड़े मेंढक जैसी बनाई है। उन्होने खुद को मार्क्स, लेनीन, माओ के साहित्य में कैद कर लिया है इसलिये वे विभिन्न विचारों को जानना समझना ही नहीं चाहते। कोई अगर देश की हालातों के मुताबिक साम्यवादी सिधान्तों को लागु करने की बातें करता है तो उसको संशोधनवादी, जातियवादी इ. करार देकर उसकी भर्सना की जाती है। वे सैधान्तिक रूप से परिवार संस्था को नकारते है लेकिन परिवार में ही रहना पसंद करते है। वे मुक्त यौनाचार के सिधान्त के समर्थक है लेकिन वे ऐसे मुक्त यौनाचार के कम्युन्स अपने बीच कायम नहीं करते। वे धर्म के विरोधी है लेकिन सारे धार्मिक कर्मकांडों का पालन करते है। वे शोषण के खिलाफ लडने की बातें करते है लेकिन सवर्णों के जातीय दमन-शोषण के पर गांधी के बंदर बन जाते है। वे जनवाद का नारा लगाते है और तानाशाही के भी समर्थक है। वे समानता का गुणगाण करते है और खुद के सवर्ण होने पर गर्व भी करते है। वे सभी किस्म की संपत्ति के सामुहिकीकरण का समर्थन करते है जबकि उन्होने अपने बड़े-बड़े घरों में कभी गरीब कम्युनिस्टों को रहने के लिये नहीं बुलाया है; उन्होने अपने धन की एक कौडी तक हडताल-पीडित मजदूरों पर खर्च नहीं की है बल्कि हमेशा उनसे ही चंदा इ. वसूलकर ऐश करते रहे है। ऐसे अनेक विराधाभासों में भारत के कम्युनिस्ट अपना जीवन बिताते है।

6) शोषित-बहुजनों से असहनीय नफरत :- तलमूद से प्रभावित मार्क्स जिस तरह अफ्रीका वंशियों, स्लाव, रूसी इ. समूदायों से नफरत करता था उसी तरह मनुस्मृति से प्रभावित भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों का सवर्ण आर्य-ब्राह्मण नेतृत्व भारत की शोषित-पिछडी जातियों से नफरत करता है। उन्होने दलितों तथा पिछडों के संघर्षों को हमेशा से ही नुकसान पहुंचाया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों का आर्य-ब्राह्मण नेतृत्व गैर-ब्राह्मण क्रांतिकारियों से नफरत करता रहा हे। नारायण मेघाजी लोखंडे ने भारत में सबसे पहले ट्रेड युनियन कायम की थी और भारत की सबसे पहली कामयाब हडताल की थी। इसके बावजूद भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया क्योंकि वे पिछडे ओबीसी समाज से थे। भारत की सबसे पहली खेत मजदूरों की हडताल जो एक साल से ज्यादा समय तक चली महान सामाजिक क्रांतिकारी अय्यंकाली ने की थी। वे दलित समाज के थे। हडताल के दौरान सवर्ण जमींदारों ने दलित खेत मजदूरों के खिलाफ हर तरह की क्रूर तिकडमें आजमाई, प्रतिशोधात्मक हमले इ. कार्रवाईयां की। आर्थिक बहिष्कार तक किया। महान अय्यंकाली ने जातियों के बीच किये गए परस्पर सहयोग के समझौतों की बंदौलत न सिर्फ इन सभी तिकडमों का मुकाबला किया बल्कि सवर्ण जमींदारों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। खेत मजदूरों की सारी मांगे मनवा ली गई। आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेतृत्व ने महान अय्यंकाली को पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया।

भारत के राज्य बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने कई दशकों तक राज किया। इस दौरान आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेतृत्व ने इस बात को सुनिश्चित किया कि दलित, आदिवासी, तथा ओबीसी जातियों को उन्हे संविधान द्वारा नौकरियों तथा शिक्षा में दिये गए आरक्षण के अधिकारों से वंचित रखा जा सके। कम्युनिस्ट पार्टियों का आर्य-ब्राह्मण

नेतृत्व खुलेआम आरक्षण का विरोध करता है। उन्हीं के विरोध की वजह से महिला आरक्षण बिल अटका पडा है क्योंकि वे दलित, आदिवासी तथा पिछड़ी ओबिसी जातियों की महिलाओं को महिला आरक्षण में उनका हिस्सा नहीं देना चाहते।

कम्युनिस्ट पार्टियों के आर्य-ब्राह्मण नेतृत्व ने दलितों के खिलाफ अपनी प्रतिशोध की भावना के तहत बँटवारे के समय मुस्लिम अल्पमत तथा दलित बहुमत के जेस्सोर, खुलना, बरीसाल, फरीदपुर, ढाका, मैमनसिंह, तथा 98% चकमा बौद्धों की आबादी वाले चिटगांग हिल इ. क्षेत्रों को जबरन पाकिस्तान के हवाले किये। जबकि पाकिस्तान को वही हिस्से दिये जाने थे जहां मुस्लिम आबादी 50 फीसदी से ज्यादा की है। जब पश्चिमी पाकिस्तान के धर्मातरित आर्य-ब्राह्मण मूस्लिमों के बेतहाशा जुल्मों की वजह से बंगाली दलित भारत आये तो कम्युनिस्ट पार्टी के ब्राह्मणवादी नेतृत्व ने उनको हर तरह से प्रताडित करने में भारत की सरकार पर काबिज अपने जातभाई आर्य-ब्राह्मणों का पूरा पूरा साथ दिया। उन्हे भारत भर में दूरदराज के क्षेत्रों में विस्थापित किया। पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने मोरिचझांपी में बंगाली दलितों की घेराबंदी कर उनका जनसंहार किया तथा षडयंत्र से सुंदरबन के बाघों का शिकार बनाया।

कई दशकों से भारत में रह रहे बंगाली दलित शरणार्थी तथा यहां पैदा हुए उनके बच्चों तक को नागरिकता हासिल करने से ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेतृत्व की पूर्ण सहमति से कानूनन प्रतिबंध लगाया गया है। इन बंगाली दलितों को जबरन भारत-बंगलादेश सीमा पर बने "नो मॅन्स लैंड" में बंदूक की नोक पर धकेला जाता है जहां इधर या उधर की सीमा में आने की कोशिश करते वक्त वे गोलियों से भून दिये जाते हैं। यह सिलसिला कई दशकों से लगातार जारी है।

कम्युनिस्ट पार्टियों का आर्य-ब्राह्मण नेतृत्व बहुजन-विरोधी तथा जनविरोधी के रूप में बेनकाब हो चुका है। इसलिये उनकी पार्टी में बहुत ही कम भ्रमित लोग बचे हैं। गांव में चौपाल होती है इसलिये वहां लोग इकट्टा होकर गप्पे हांकते हैं। क्योंकि भारत भर में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालयों की इमारतें हैं, वहां कथित कम्युनिस्ट नेता चाय की चुस्कियों पर मार्क्सवाद की गप्पें हांकते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से कम्युनिस्ट पार्टियों के कंकालों पर मांस की पतली सी पर्त नजर आती है।

सभी सत्ताधारी पार्टियां उद्योगपतियों के हितों के लिये ऐसे कदम उठाती हैं जिससे मजदूरों को नुकसान होता है। इसलिये इस बात को सुनियिचत करने के लिये कि मजदूरों का गुस्सा शोषकों को भारी नुकसान ना पहुंचाये सत्ताधारियों ने ट्रेड युनियन्स बनाई है। ये युनियनयें कुछ नकली संघर्ष के बाद लिये गए मजदूर विरोधी कदम में थोड़ी सी राहत दिलवाकर मजदूर विरोधी कदम को लागु करने में मदद करती हैं। कम्युनिस्ट ट्रेड युनियन नेता अपनी युनियनों में उन मजदूरों को लाती हैं जो अब भी नाखुश हैं और संघर्ष पर आमादा हैं। आर्य-ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता बिना सुरक्षा इंतेजाम के हडताल कर उसे नाकाम बनाते हैं। इस नीति से वे क्रांतिकारी मजदूरों की बर्खास्तगी और भूखमरी को सुनिश्चित कर देते हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि कम्युनिस्ट नेता पर्दे के पिछे उद्योगपतियों से मजदूरों को धोखा देने की कमीशन

लेते हैं। मजदूरों से सदस्यता फीस, किये गये छोटे मोटे कामों में से कमीशन, पार्टी के लिये चंदा तथा वोट इ. लाभ उठाते हैं।

अगर मजदूरों की कमान गैर-आर्य-ब्राह्मण ईमानदार नेताओं के हाथों में है तथा वे आने वाले संकटों से निपटने का पहले से प्रबंध कर लेते हैं और हड़ताल को सफल बनाते हैं तो ये सफलताएं भी आर्य-ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं के खातों में चली जाती हैं। इनके उदाहरणों से वे मजदूरों तथा जनता को मूर्ख बनाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों का आर्य-ब्राह्मणवादी नेतृत्व परजीवियों की जमात है जो शोषित और दमित अवाम की मेहनत पर फलते फूलते रहा है। भारत के ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेतृत्व पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिये "मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्टों से सावधान !" नामक जागरूकता किताब पढ़ें। यह किताब हमारी वेबसाइट <https://www.bahujanmarch.org> पर मुफ्त डाउनलोड के लिये उपलब्ध है।

अध्याय 11

क्या छुटकारे का कोई रास्ता है ?

शोषण-व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक मूलाधार

हर व्यक्ति में पाई जाने वाली आलस, लालसा, स्वार्थ, ईर्ष्या, अहं इ. मूलभूत प्रेरणायें हैं जो हर किस्म की शोषण-व्यवस्थाओं को जन्म देती हैं। आप चाहे जैसी अच्छी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्यों ना कायम कर ले लेकिन इन प्रेरणायों की बदौलत वह व्यवस्था धीरे धीरे शोषण व्यवस्था में तब्दिल होने लगती है क्योंकि जनता के हित के नियमों कानूनों को नजरंदाज किया जाता है तथा अपने फायदे के मुताबिक नियम लागू किये जाते हैं।

झाओनिजम तथा ब्राह्मणवाद का यकीन है कि समाज के खास संपन्न जाति-समुदाय को ईश्वर ने अन्धों पर क्रूरता से शासन करने का अधिकार दिया है। ऐसा कोई भी इन्सान जो उपरोक्त बात में भरोसा करता है वह चाहे किसी भी जाति-समूह, वंश या रंग का क्यों ना हो वह झाओनिस्ट तथा ब्राह्मणवादी है। जो इन्सान झाओनिस्ट-ब्राह्मणवादी मकसद के लिये अपने किसी खास स्वार्थ को पूरा करने के लिये काम करता है वह झाओनिस्ट-ब्राह्मणवादियों का दलाल है। जो कोई यह सब मजबूरी में करता है वह झाओनिस्ट-ब्राह्मणवादियों का गुलाम है। शैतानवाद का मूलाधार भी झाओनिजम और ब्राह्मणवाद है। झाओनिजम, ब्राह्मणवाद तथा शैतानवाद यह एक ही चीज (phenomena) का नाम है जिसका विकास व्यक्ति के आलस, लालच, ईर्ष्या तथा नफरत जैसी प्रवृत्तियों से हुआ है। झाओनिजम, ब्राह्मणवाद तथा शैतानवाद (ZBS) के मुताबिक हर किसी ताकतवर इन्सान को यह हक है कि वह कमजोरों को गुलाम बनाए, उनपर चाहे जैसा जुल्म करें या उनका क्रूरतम तरीकों से विध्वंस करे। झाओनिजम,

ब्राह्मणवाद तथा शैतानवाद अपने मकसद को पाने के लिये धोखेबाजी, मक्कारी, झूठ (साम, दाम, दंड, भेद) इ. किसी भी अनैतिक बातों के इस्तेमाल को जायज मानता है। झाओनिजम, ब्राह्मणवाद तथा शैतानवाद शोषण-व्यवस्थाओं का मूलाधार है।

अगर आप किसी शोषक सरकार को चाहे हजारों बार ही क्यों ना बदल डाले, आलसी, मतलबपरस्त, लालची, मक्कार, इर्षालू लोग हर बार राजसत्ता पर काबिज होकर शोषण-व्यवस्थाओं को जन्म देंगे। इसलिये जबतक लोग आलस, लालच, इर्षा, तथा नफरत इ. प्रवृत्तियों की व्यर्थता को जान-समझकर अपनी इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कायम नहीं कर लेते और खुद में सामाजिक न्याय पर आधारित नैतिकता को विकसित नहीं कर लेते शोषण व्यवस्थाओं से बचा नहीं जा सकता। इसी वजह से बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लोगों की सामाजिक न्याय पर आधारित नैतिक जागरुकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। नैतिक जागरुकता प्राप्त किये हुए लोग ही समतामूलक समाज व्यवस्था के लिये सच्चा जनवादी संघर्ष कर सकते हैं। इसी मकसद से उन्होंने "भीमयान बौद्ध धम्म" कायम किया। भीमयान बौद्ध धम्म ब्राह्मणवादी मिलावटों से मुक्त बौद्ध धम्म है। नैतिक जागरुकता से ही सच्चा लोकतंत्र निर्माण हो सकता है। ऐसे ही लोकतंत्र में समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की कल्पना की जा सकती है।

शोषण-व्यवस्थाओं का भौतिक मूलाधार

1) सूदखोरी शोषण व्यवस्थाओं का भौतिक मूलाधार :- शोषण व्यवस्था का बहुत बड़ा भौतिक मूलाधार सूदखोरी है। अगर आप व्याज लेने तथा देने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दे और सामाजिक योजना के तहत उत्पादन करे तो मंहगाई इ. की कभी समस्या पैदा नहीं होगी।

2) केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था शोषण व्यवस्थाओं का भौतिक मूलाधार :- केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था निरंकुशता और तानाशाही को जन्म देती है। आप राज्य यंत्रणा को जितना विकेन्द्रित करेंगे आम लोग उतने ही शक्तिशाली बनते जाएंगे।

राज्य-व्यवस्था का पर्याय !

राज्यसंस्था का इकलौता पर्याय सामाजिक न्याय पर आधारित नैतिक रूप से जागरुक "लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज" है। नैतिक रूप से जागरुक लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की मुख्य विशेषताएं नीचे दिये मुताबिक हैं :-

1. लहरोंवाली संगठन संरचनाएं :-

अधिकतम संभव विकेन्द्रीकरण से जाति व्यवस्था जैसी श्रेणियों वाली पीरमिड वाली सामाजिक संरचनाओं के विधंस से समानता की प्रतिक लहरों वाली सामाजिक संरचनाओं का निर्माण होता है। लहरों वाली संरचना में क्षेत्रीय ईकाईयां जरूरी वस्तुओं के उत्पादन करने के साथ ही आत्मरक्षा करने में भी सक्षम होती है। सर्वोच्च ताकत मूल ईकाई की आम जनता के हाथों में होती है। हर किसी को शस्त्र रखने की पूरी आजादी है।

उच्च प्रशासनिक संरचनाएं मात्र विभिन्न क्षेत्रीय ईकाईयों के बीच कार्य संबंधी तालमेल कायम करने के लिये बनाई गई विकेन्द्रित संरचनाएं हैं जिनका मकसद बड़े प्रकल्पों जैसे की रेल्वे, राष्ट्रीय मार्ग, नहरें, अतिरिक्त उत्पाद का आपस में विनिमय-वितरण, बड़े उद्योग, उच्च तकनीकी सामग्री का निर्माण इ. हैं जिसमें सभी संबंधित इकाईयों के संसाधनों के एकत्रिकरण से ही इन्हें अंजाम दिया जा सकता है। उपरोक्त उत्पादन अथवा सेवा एककों का नियंत्रण सिर्फ संबंधित क्षेत्रीय ईकाईयों द्वारा किया जाएगा। जिन लोगों को उच्च जिम्मेदारी दी गई है वे दो साल जैसी छोटी अवधि में दोबारा सामान्य लोगों के स्तर पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगातार दो बार नहीं चुना जा सकता और उस व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन में तीन बार से ज्यादा के लिये नहीं चुना जा सकता। लोगों को यह अधिकार है कि वे जब चाहे तब अपने प्रतिनिधियों को हटा सकते हैं।

2. जागरुक लोगों की सामाजिक न्याय तथा श्रम पर आधारित संस्कृति :- स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज की सफलता नीचे दी हुई बातों पर निर्भर करती है :-

i) आलस, लालच, ईर्ष्या तथा व्देष इ. की व्यर्थता का पूरी तरह से अहसास होना, शारीरिक मेहनत, मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय पर तथा समाजोपयोगी अर्थपूर्ण जीवन जीने पर पूरा विश्वास होना स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिये जरूरी शर्त है।

ii) राजनीतिक रूप से जागरुक होना तथा व्यवस्थापन में शिक्षित-दक्षित होना तथा अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए सक्रिय रूप से हिस्सा लेना जरूरी शर्त है।

iii) लिये जाने वाला हर निर्णय सामाजिक न्याय पर आधारित नैतिकता की कसौटी पर पूरा उतरना जरूरी शर्त है। यानी निर्णय से मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा तथा सभी का फायदा होता है। खाप पंचायतों के बहुमत के निर्णय मानवाधिकारों का कैसा हनन करते हैं यह सर्वविदित है।

iv) आमतौर से सभी निर्णय सर्वसम्मती से लिये जाने चाहिये ताकि उन्हें सभी का पूरा सहयोग प्राप्त हो सके।

उपरोक्त चारों शर्तों को पूरा किये बिना सामाजिक न्याय पर आधारित जागरुक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज की सफलता नामुमकिन है। सामाजिक न्याय पर आधारित स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के हर जाति-समुदाय को उसके आबादी के अनुरूप नौकरियों तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण हासिल हो। इससे किसी भी जाति-समुदाय का अन्यो पर वर्चस्व कायम नहीं होगा। सभी को शिक्षा, रोजगार तथा बूढ़े, अपंगों को सामाजिक सुरक्षा देना मूलभूत क्षेत्रीय इकाईयों की जिम्मेदारी होगी। शोषण और दमन को बढ़ावा देनेवाली सभी विचारधाराओं का प्रतिकार किया जाएगा तथा जो समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है उनका प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

3. सूदखोरी तथा अन्यायपूर्ण मूनाफे पर प्रतिबंध :- सूदखोरी करने तथा ब्याज लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। मूल क्षेत्रीय इकाईयों विभिन्न उत्पादों का

तथा सेवाओं का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्य निर्धारण करेगी तथा किन चीजों का कितना उत्पादन करना है यह लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय होगा। क्षेत्रीय इकाईयां अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा जारी करेगी।

4. निजी संपत्ति तथा उत्तराधिकार :- कोई भी किसी को अपना निजी नौकर नहीं बना सकेगा। इसलिये हर कोई सिर्फ उतनी ही जायदाद का जैसे कि घर, वाहन, खेत, उद्योग इ. का मालिक बन सकता है जितने की वह खुद अपने या अपने परिवार के स्वैच्छिक परिश्रम से देखभाल कर सकता है। व्यक्ति इतना ही धन इकट्ठा कर सकता है जिससे उसकी मूलभूत जरूरतें अच्छी तरह से पूरी हो जाती हैं, और जिससे अलग संपन्न वर्ग का निर्माण नहीं होता। इस सीमा का नीतिगत निर्धारण स्थानिय इकाई पूरी सहमति से तय करेगी। व्यक्ति उत्तराधिकार में संपत्ति हासिल कर सकता है बशर्ते उसकी कुल संपत्ति निर्धारित सीमा के भीतर हो।

ऐसी सभी उत्पादन इकाईयां जो एक व्यक्ति के परिश्रम से नहीं चल सकती, उन्हें सामुहिक तौर पर आपसी सहमति से चलाया जाएगा। ये सभी "कर्मचारी" उस इकाई के मालिक माने जायेंगे और होने वाले लाभ का न्यायपूर्ण तरीके से आपस में वितरण करेंगे। औद्योगिक इकाई की आय का आपस में वितरण किस प्रकार से होगा इसकी नीति क्षेत्रीय इकाई तय करेगी। जबतक कोई कर्मचारी है उसकी उस औद्योगिक इकाई में मित्कियत रहेगी।

5. नागरी सेवाएं तथा सुरक्षा :- मूलभूत क्षेत्रीय इकाई खुद ही सभी नागरी सेवाओं को जैसे कि शांति कायम रखना, न्यायदान करना तथा क्षेत्रीय इकाई की सुरक्षा करना इ. को पूरी पारदर्शिता के साथ अंजाम देगी। गरीबी, दमन तथा शोषण इ. अपराध के मुख्य कारण हैं। इन कारणों के खत्म हो जाने के बाद अधिकांश अपराध अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। जो कुछ भी वारदातें बचती हैं वे अपवादात्मक स्थितियाँ होती हैं। इनका सामाजिक तौर पर निपटारा किया जाएगा। इसलिये जेल, पुलिस तथा न्यायालय इ. जैसी स्थायी संस्थाएं नहीं होंगी।

सामाजिक-न्याय के संगठनों का स्वरूप !

अगर आप सामाजिक न्याय की पर आधारित व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो आपको पहले शोषकों के क्रूरतम चरित्र तथा ताकत को जान-समझकर उसके अनुरूप होने वाले संघर्ष को जानना समझना होगा तथा अपनी क्षमताएं, अक्षमताएं, जिम्मेदारियां तथा अपने साधन संसाधनों को जान समझकर खुद की प्राथमिकताओं को तय करना होगा तथा संघर्ष की जरूरतों के मुताबिक संघर्ष करना होगा।

दमित-शोषितों के सभी औपचारिक संगठनों की संरचना जाति-व्यवस्था की तरह पिरॅमिड वाली होती है जिसमें संगठन की सारी ताकत शीर्ष नेताओं के हाथों में केन्द्रित होती है। ये नेता अक्सर ही शिक्षित और संपन्न होते हैं। इसलिये संगठन का नेतृत्व करने के लिये उनके पास भरपूर समय होता है। बैंकर्स को दमित-शोषितों के औपचारिक संगठन पसंद होते हैं क्योंकि वे इन संगठनों के नेताओं को खरीद सकते हैं,

उन्हे ब्लैकमेल कर सकते हैं; संगठन में अपने एजेन्ट घूसा कर उसे नुकसान पहुंचाना, संगठन को दो फाड़ो में विभाजित करना इ. कामों को अंजाम दे सकते हैं। या फिर सारे संगठन को विशेष जेलों (concentration camps) में दूंस सकते हैं।

इसलिये सामाजिक न्याय के लिये पूरी तरह से समर्पित लोग जिन्होंने अपने लालच, आलस, ईर्ष्या पर पूरी तरह से नियंत्रण कायम किया है उन्हे शोषितों के मिशन के प्रति समर्पित होना है न कि किसी संगठन के प्रति क्योंकि कोई भी एक संगठन शोषितों के संघर्ष के सारे कार्यक्षेत्रों जैसे कि आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक, कृषि, स्वास्थ्य, महिला, छात्र इ. में कार्य नहीं कर सकता और न ही साथ साथ शोषकों के सशस्त्र आतंकवादी संगठनों से निपट सकता है। इसलिये उन्होंने शोषितों के सभी "मिशन" के कामों में मदद करनी चाहिये चाहे फिर वह कार्य कोई भी संगठन क्यों ना कर रहा हो। मिशन के काम वे काम हैं जिनसे शोषक वर्ग तथा उसकी शोषण-व्यवस्था कमजोर होती है, शोषित जनता का सतत रूप से सशक्तिकरण होता है तथा शोषण के खिलाफ उनका संघर्ष और ज्यादा मजबूत होता है। मिशन के ऐसे कामों को व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर तथा सामाजिक स्तर पर बिना किसी जोखिम या नुकसान के यकीनी तौर पर अनुकूल परिणामों के साथ अंजाम दिया जा सकता है। इन कामों को हमने अपनी वेबसाइट : <https://www.bahujanmarch.org> पर "Genuine Struggle" शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया है। मिशन के यह कार्य 1) व्यक्तिगत सशक्तिकरण, 2) पारिवारिक सशक्तिकरण तथा 3) सामाजिक सशक्तिकरण इन तीन स्तरों में स्पष्ट किये हैं। पहले दो स्तरों के कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे शोषकों या उसके एजेन्टों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त हैं। इन्ही से सामाजिक न्याय का व्यापक जनाधार बनता है। आप चाहे किसी भी औपचारिक संगठन के सदस्य क्यों ना हो आप अपने लिये अपनी क्षमताओं, जिम्मेदारियों तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद का कोई मिशन का काम अपने लिये चुन ले और उसमें समर्पित हो जाये। इसमें कोई भी बाधा नहीं है क्योंकि आपका संगठन आप से चंदा मांगने, सभा-मोर्चे में शामिल होने इ. के लिये पूरे वर्ष में मुश्किल से 15 बार आप से संपर्क करता है। बाकी के 350 दिन आपके अपने होते हैं।

“सामाजिक-राजनितिक स्तर के कामों को अंजाम देने के लिये यह जरूरी है कि अपने अपने पसंदीदा कामों के लिये समर्पित 1-5 व्यक्ति अपना एक अनौपचारिक, स्वयंपूर्ण संगठन बनाये। किसी भी निर्णय पर अमल करने के लिये सभी की पूर्ण सहमति का होना अनिवार्य शर्त है। जो सदस्य असहमत हैं उन्होंने खुद का अलग समुह बनाकर अपने कामों को अलग से अंजाम देना चाहिये। ऐसे समुह का अपना कोई नाम नहीं होता और न ही वे खुद को समुह के रूप में लोगों के सामने उजागर करते हैं। ऐसे छोटे छोटे अनौपचारिक, स्वयंपूर्ण, एकदूसरे से असंबंधित समुह आम जनता के बीच लोगों की बुनियादी तीव्र चाहत के मुताबिक अपने कामों का निर्धारण करते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप वे आम लोगों की सहमति से उनके बीच एक सदस्य के रूप में तय कामों में हिस्सा लेते हैं। वे सिर्फ अपने कामों, विचारों तथा परस्पर संबंधों से

लोगों को प्रभावित करते हैं।

समूह के सदस्य लोगों की स्वतंत्रता के लिये जरा भी खतरा नहीं है क्योंकि वे किसी भी पद पर नहीं होते। सच्चे जनसंघर्ष में कोई पद ही नहीं होते बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं जिसे अलग अलग लोग अलग अलग समय पर पूरा करते हैं।

जागरुकता समूह जनता के किसी भी संघर्ष का नेतृत्व करने की कोशिश नहीं करते बल्कि संघर्ष के लक्ष्य को स्पष्ट करने, प्रचार करने, तथा आम लोगों की बुनियादी चाहतों के मुताबिक मिशन के कामों की रूपरेखा पेश करते हैं। ताकि लोग संघर्ष के नाम पर ऐसा कोई आत्मघाति काम ना चुन ले जिससे सिर्फ नुकसान ही होता है। शोषक तथा उनकी शोषण व्यवस्था कमजोर होनी चाहिये न कि वे खुद। नुकसान शोषकों का होना चाहिये न कि उनका खुद का। इससे परे जाने का मतलब सामाजिक न्याय के मुक्ति संघर्ष के समूचे उद्देश्य को नुकसान पहुंचाना है।

ऐसा कोई भी काम जो "मिशन" की कसौटी पर खरा नहीं उतरता शोषितों के मिशन का काम नहीं है क्योंकि ऐसे कामों से शोषितों को फायदे की बजाय सिर्फ नुकसान होता है। ऐसे कामों को हमने अपनी वेबसाइट <https://www.bahujanmarch.org> पर "Fake Struggle" शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया है।

अनौपचारिक जागरुकता समूहों की भूमिका संघर्ष में शामिल होकर संघर्ष को चालना देनेवाले (catalysts) की होनी चाहिये। असंबंधित जागरुकता समूह अपने जागरुकता के कामों में तालमेल से संबंधित होते हैं न की प्रत्यक्ष (physical) रूप से। सामाजिक न्याय को कामयाब बनाने के लिये अंततः वैश्वीक स्तर पर कोशिशें होनी चाहिये क्योंकि शोषक वैश्वीक स्तर पर संगठित हैं।

संदर्भ सूची

Books and PDF Documents

A Critique of Marxism by Sam Dolgoff, First published by Soil of Liberty, Minneapolis, 1983. www.zabalazabooks.net

A Sea of Blood The Truth about Bolshevick Russia By Dr. Gregor, First Edition published in 1926 by the German Folk Publishing House, Munich, Germany, Dr. E. Boepple

Emma Goldman : My Disillusionment in Russia, 1923, The Anarchist Library

Marxism Unmasked: From Delusion to Destruction By Ludwig Von Mises, Foundation For Economic Education Irvington-on-Hudson, NY 10533

Mullins' New History of the Jews by Eustace Mullins published by The International Institute of Jewish Studies, 126 Madison Place Staunton, Virginia 24401

The History of Money From Its Origins to Our Time

N.W.O. Forbidden History

Under the sign of Scorpion by Juri Lina

All Wars Are Bankers' Wars! by Michael Rivero

Marx and Satan By Richard Wurmbrand

Red Jenny A Life with Karl Marx, by H.F. Peters, St. Martin's Press New York , ISBN 0-312-00005-7

Marx and Anarchism by Rudolf Rocker, 1925, The Anarchist Library Anti-Copyright

Karl Marx Debunked by Leon Hamilton, Social Justice

Socialism Study Guide, AP European History by Mr. Mercado

Origin of the Family, Private Property, and the State by Friedrich Engels, Written: March-May, 1884; First Published : October 1884, in Hottingen-Zurich; Source: Marx/Engels Selected Works, Volume Three

Marx, Engels, and the Abolition of the family by Richard Weikart, History of European Ideas, Vol. 18, No. 5, pp. 657-672, 1994 0191-6599 (93) E0194-6 _ . Copyright c 1994 Elsevier Science Ltd Printed in Great Britain

Marxism as Pseudo Science by Ernest Van DenHaag Fordham University

Karl Marx : The almost Capitalist By Louis O. Kelso, American Bar Association Journal, March 1957

Karl Marx: A Failed Vision of History

Statism and Anarchy

Edward Jenks, The State and the Nation, 1919

Michael Bakunin Selected Writings, , Edited and Introduced by Arthur Lehning, Jonathan Cape Thirty Bedford Square London

The French Revolution and the Idea of the Nation

The Bolshevik Myth (Diary 1920–22) by Alexander Berkman, The Anarchist Library

The Secret Powers Behind Revolution Freemasonry and Judaism, By Vicompte Leon De Poncix, Omni /Christian Book Club P.O. Box 900566, Palmdale , CA 93590

Writings of Leon Trotsky [1929], PATHFINDER PRESS, INC. NEW YORK, First Edition, 1975

The Chronology of the Jews of Shanghai from 1832 to the Present Day

Web Pages

[http://www.mileswmathis.com/Reading the Signs](http://www.mileswmathis.com/Reading%20the%20Signs), by Miles Mathis First published November 23, 2014

http://transmissionsmedia.com/Wall Street Funded Both Communists and Nazis _ Transmissions.html

http://www.thedailydigest.org/Rothschild World Government Take Over Timeline _ The Daily Digest.html

<http://www.unique-design.net/Karl Marx, oops! I mean Groucho Marx councils us - Who are you going to believe me or your own two eyes.html>

<https://www.stormfront.org/Jewish Bankers Again Target Russia for Revolution - Stormfront.htm>

<https://www.henrymakow.com/How to Make Sense of Current Events - henrymakow.com.html>

<http://www.rupe-india.org/35/globalisation.html> Introduction 'Globalisation'

<http://www.biblebelievers.org.au> Murder by Injection Chapter 10 The Rockefeller Syndicate by Eustace Mullins

<http://www.apfn.org/apfn.htm> The Rockefeller Syndicate

http://www.thedailydigest.org/Rothschild World Government Take Over Timeline _ The Daily Digest.html

<https://www.henrymakow.com/How to Make Sense of Current Events - henrymakow.com.htm>

<https://www.henrymakow.com/How to Make Sense of Current Events - henrymakow.com.htm>

Death of communism part 2 by <http://www.deathofcommunism.josru.com>

https://www.psychologytoday.com/How Hunter-Gatherers Maintained Their Egalitarian Ways _ Psychology Today

<http://zioncrimefactory.com/> The Jew World Order Unmasked by ZionCrimeFactory

<http://www.mileswmathis.com/Reading the Signs, by Miles Mathis First published November 23, 2014>

http://transmissionsmedia.com/Wall Street Funded Both Communists and Nazis _ Transmissions.html

http://www.thedailydigest.org/Rothschild World Government Take Over Timeline _ The Daily Digest.html

<http://www.unique-design.net/Karl Marx, oops! I mean Groucho Marx councils us - Who are you going to believe me or your own two eyes.html>

<https://www.henrymakow.com/How to Make Sense of Current Events - henrymakow.com.html>

<http://www.rupe-india.org/35/globalisation.html> Introduction 'Globalisation'

<http://www.biblebelievers.org.au> Murder by Injection Chapter 10 The Rockefeller Syndicate by Eustace Mullins

<http://www.apfn.org/apfn.htm> The Rockefeller Syndicate

<http://international.ucla.edu/asia/mao491216.htm> (Conversation between the Soviet Union's Joseph Stalin and China's Mao Zedong December 16, 1949)

Mao Zedong From Wikipedia, the free encyclopedia

Mao: The Unknown Story From Wikipedia, the free encyclopedia

<https://lipstick-and-war-crimes.org/> Mao Was a Yale Man - Rothschilds Create People's Republic of China - The Book Lipstick and War Crimes by Ray Songtree.
html

Great Leap Forward From Wikipedia, the free encyclopedia

History of banking in China From Wikipedia, the free encyclopedia

<http://theinfounderground.com/smf/index.php?PHPSESSID=8c366a111329380f98b355e6f9e94101&topic=12486.msg48354#msg48354> (Timeline: Jewish Subversion in China)

<https://www.thenewamerican.com/> U.S. Allies Join Communist Chinese-led International Bank.htm

<http://batr.org/forbidden/> Red China is a Creation of Globalists.htm

<http://www.theeuropeangreens.eu/> Are China, Russia and the rest of the world dismantling the Jewish allergy within their nations, or is this another game of Divide and Conquer - THE EUROPEAN GREENS (Eng).htm

<https://www.thenewamerican.com/> China Betrayed Into Communism.htm

written by James Perloff

<http://smoloko.com/> China is owned by the Illuminati Jewish Bankers – do not be fooled – Smoloko.htm

<https://www.thenewamerican.com/> Chinese Mega-bank Partners With World Bank for New World Order.htm

<https://lorddreadnought.livejournal.com/> Communist China was created by the Jews and serves their interests.%20 lorddreadnought.htm

<http://www.biblebelievers.org.au/>Hong Kong, the Land Built on Opium

<http://www.jewsofchina.org> The Jewish Community of China.htm

<https://www.jpost.com/> Honoring the millennial friendship between Jews and China - Opinion - Jerusalem Post.htm

<http://www.jewwatch.com/>Jewish Faces in the Chinese Government.htm

<https://www.henrymakow.com/>Mao's Monstrous Record Has Been Suppressed - henrymakow.com.htm

<http://www.texemarrs.com/> The Illuminati and Its Triad of Evil.htm

<http://factsanddetails.com/> TRIADS AND ORGANIZED CRIME IN CHINA%20 %20 Facts and Details.htm



**Bhima Koregaon
Bahujan Valour
Memorial**